20 जनवरी, संयुक्तांक (नवंबर,2025–जनवरी,2026) ⭑ वर्ष 34-35, पृष्ठ संख्या 72, अंक 11,12,01

राजस्थान सुजस

2 साल
नव उत्थान - नई पहचान

बढ़ता राजस्थान
हमारा राजस्थान

- प्रदेश में तकनीक और स्टार्टअप के सशक्त ईकोसिस्टम के निर्माण के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है।
- राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।
- राज्य सरकार द्वारा लाई गई **'एआई-एमएल पॉलिसी 2026'** से एआई सिस्टम अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और निजता-संरक्षण के प्रति जवाबदेह बनेंगे।
- तकनीक और आईटी के उत्सव डिजिफेस्ट ने स्टार्टअप्स को निवेशकों से, विद्यार्थियों को अवसरों से और उद्योग को सरकार से जोड़कर डिजिटल राजस्थान का मार्ग प्रशस्त किया है।
- राजस्थान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नवाचार, निवेश और सुशासन का अग्रणी केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
- राज्य सरकार प्रदेश के विकास के साथ-साथ अपनी संस्कृति और साहित्य के विकास के लिए भी प्रतिबद्ध है।
- ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना की ताकत और संकल्प का जीवंत उदाहरण है।
- हमारी सरकार पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के सम्मान और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।
- राज्य सरकार जनजातीय समाज के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है।
- प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
- राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि प्रवासी राजस्थानियों की सक्रिय भागीदारी से प्रदेश में निवेश, नवाचार तथा विकास के नए आयाम स्थापित हों।
- राज्य सरकार की निवेश अनुकूल नीतियों के कारण राज्य देशभर में निवेश के नए केन्द्र के रूप में उभर रहा है।

"राजस्थान देश के बेस्ट परफॉर्मर स्टेट की श्रेणी में पहुंच गया है। प्रदेश 12 राष्ट्रीय योजनाओं में प्रथम स्थान, 4 योजनाओं में द्वितीय स्थान और 7 योजनाओं में तृतीय स्थान पर है। यह हमारी सरकार की प्रतिबद्धता, मेहनत और जनता के विश्वास का परिणाम है।"

- निवेश प्रणाली का सरलीकरण करते हुए राज्य सरकार प्रदेश को देश का अग्रणी निवेश गंतव्य बनाने के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है।
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार विकसित राजस्थान@2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
- राज्य सरकार ने एक रोडमैप बनाकर गत दो वर्षों में पानी, बिजली, उद्योग, रोजगार सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्राथमिकता के साथ कार्य किया है।
- हम जनता के सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं और प्रदेश के विकास का पहिया बिना रुके, बिना थमे आगे बढ़ रहा है।
- हमारी सरकार समृद्ध एवं विकसित राजस्थान की नींव रखते हुए गरीब को गणेश मानकर जनसेवा को प्राथमिकता देकर कार्य कर रही है। ■

प्रधान संपादक
राकेश शर्मा

वरिष्ठ संपादक
डॉ. गोरधन लाल शर्मा

संपादक
डॉ. रजनीश शर्मा

सहायक संपादक
डॉ. प्रियंका चतुर्वेदी
मोहित जैन

संकलन एवं वितरण
ऋतु शर्मा
रणवीर सिंह कुशवाह

राजस्थान सुजस में प्रकाशित सामग्री में व्यक्त विचार लेखकों के अपने एवं आंकड़े परिवर्तनशील हैं। आवश्यक नहीं कि शासन उनसे सहमत हो। सुजस में प्रकाशित सामग्री का विभाग किसी भी रूप में उपयोग कर सकेगा।

ग्राफिक डिजाइनिंग
रेनबो ऑफसेट प्रिंटर्स
लागत मूल्य 45.20 रुपये

संपर्क
संपादक
राजस्थान सुजस (मासिक)
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग
सचिवालय, जयपुर-302005
मो. 80581 15790
e-mail
editorsujas@gmail.com
publication.dipr@rajasthan.gov.in
Website
www.dipr.rajasthan.gov.in

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान का मासिक

वर्ष : 34-35 अंक 11,12,01

इस अंक में

नवंबर, 2025 – जनवरी, 2026

शब्द भावना	02
संपादकीय	04
धर्म ध्वजा का आरोहण (ऋषिता मेहरा)	30
गौमाता की महिमा (पंकज ओझा)	32
भारतीय संविधान (सूर्य प्रताप सिंह राजावत)	42
हे गिरिराज गोवर्द्धन ! (रामानंद राठी)	52
जेएलएफ–2026 (आशीष जैन)	55
डिजिफेस्ट-2026 (आशीष खण्डेलवाल)	58
गुप्तकालीन शिखरबंद देवरा (डॉ. अरुणा व्यास)	62
Role of Environmental Laboratories ... (Dr. Aruna Sharma)	64
प्रदेश नीति (शैलेन्द्र सिंह)	66
सामयिकी	68
प्रश्नोत्तरी	70

बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान **05**
- वी. श्रीनिवास, मुख्य सचिव

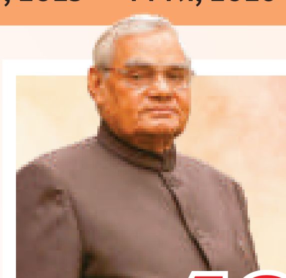
सुशासन के पथ पर अटल भारत **48**
- अमन हरसाना

प्रवासी राजस्थानी दिवस **19**
- डॉ. गोरधन लाल शर्मा
राजस्थान प्रशासनिक सेवा

गंगनहर **56**
- अनिल शाक्य

78वां भारतीय सेना दिवस **34**
- वंजुल सांखला

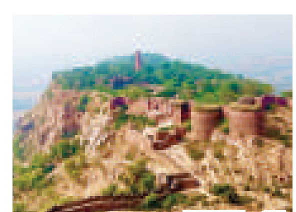
धरोहर विजय मंदिर गढ़ **71**
- अमन हरसाना

संपादकीय

परंपरा से प्रगति तक राजस्थान की नवोन्मेषी यात्रा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत@2047 के दूरदर्शी संकल्प और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्णायक, परिणामोन्मुख नेतृत्व से राजस्थान आज नवोन्मेषी यात्रा में विकास की नई ऊंचाइयों की ओर उन्मुख है। जहां परंपरा और प्रगति, शौर्य और सुशासन, सांस्कृतिक गौरव और तकनीकी नवाचार-सभी एक साझा दृष्टि में एकीकृत होते दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश का समेकित परिदृश्य इस परिवर्तन का सजीव प्रमाण है। भारतीय सेना का 78वां सेना दिवस समारोह, राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की श्रृंखला, प्रवासी राजस्थानी दिवस और डिजिफेस्ट जैसे नवाचारात्मक आयोजन, सभी मिलकर 'विकसित राजस्थान' की उस आधारशिला को सुदृढ़ करते हैं, जो **'विकसित भारत@2047'** के राष्ट्रीय संकल्प से गहराई से जुड़ी है।

देश में पहली बार सैन्य छावनी क्षेत्र से बाहर आमजन के बीच जयपुर में आयोजित सेना दिवस परेड और उससे जुड़ी शौर्य संध्या ने पूरे राज्य में देश भक्ति की एक सुदृढ़ भावना और उल्लास भर दिया। सेना दिवस प्रदर्शनी के माध्यम से लाखों युवा सैन्य गतिविधियों से रूबरू हुए। राजस्थान के लिए यह गर्व का अवसर रहा।

राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल के दो वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सुशासन को केवल उपलब्धियों की सूची तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे जनसंवाद और जनभागीदारी से जोड़कर प्रस्तुत किया। विकास रथ अभियान के माध्यम से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में गांव-गांव और ढाणी-ढाणी तक पहुंच बनाकर आमजन को सरकारी योजनाओं से जोड़ा गया। इसी प्रकार सुझाव पेटिकाओं के जरिए प्राप्त जन-सुझावों को बजट में समाहित करने का निर्णय सरकार की सहभागी शासन दृष्टि को दर्शाता है। राज्य सरकार ने सुशासन, सहभागिता और समावेशी विकास को मात्र औपचारिक नीति नहीं, बल्कि अपनी कार्यसंस्कृति के रूप में स्थापित करने का काम किया है।

प्रवासी राजस्थानी दिवस और डिजिफेस्ट के सफल आयोजन ने राजस्थान की आर्थिक, सांस्कृतिक और डिजिटल शक्ति को एकीकृत रूप में प्रस्तुत किया है। प्रवासी राजस्थानियों का जुड़ाव आज निवेश, नवाचार और रोजगार के अवसरों में परिवर्तित होकर राज्य के समग्र विकास को गति दे रहा है, वहीं डिजिफेस्ट ने डिजिटल क्षमता और तकनीकी दक्षता के माध्यम से युवा शक्ति को अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान को ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में अग्रसर किया है।

समग्र दृष्टि से देखें तो राज्य का विकास वाक्य –**"बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान"** अब उस साझा विश्वास, दृढ़ प्रतिबद्धता और ठोस क्रियान्वयन का जीवंत प्रतीक बन चुका है, जो राज्य को सुशासन, समावेशी विकास, नवाचार और दूरदर्शिता के सहारे न केवल राष्ट्रीय उत्थान में अग्रणी बनाएगा, बल्कि वैश्विक मंच पर उसकी प्रतिष्ठा और पहचान को भी सशक्त करेगा। बीते तीन महीनों की इस समग्र यात्रा को अपने भीतर समेटे, नवम्बर–दिसम्बर 2025 और जनवरी 2026 का यह संयुक्तांक प्रगति और नवाचार के एक दस्तावेज के रूप में आप सभी सुधि पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

वन्दे मातरम्!

(राकेश शर्मा)
प्रधान सम्पादक

2 साल
नव उत्थान - नई पहचान

बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान

''प्रजासुखे सुखं राज्ञः, प्रजानां च हिते हितम्।''

— कौटिल्य, अर्थशास्त्र

वी. श्रीनिवास, मुख्य सचिव

राजा का सुख प्रजा के सुख में और उसका हित प्रजा के हित में निहित होता है–सुशासन का यह शाश्वत सूत्र आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जब राज्य की नीतियां सत्ता के नहीं, समाज के कल्याण को केंद्र में रखती हैं, तब शासन विश्वास का स्वरूप ग्रहण कर लेता है।

सुशासन का मर्म यही है कि सत्ता का प्रत्येक निर्णय जनहित में हो और शासन की हर दिशा लोककल्याण की ओर अग्रसर रहे। किसी भी राज्य की दिशा और दशा उसके शासन से निर्धारित होती है। जब नेतृत्व स्पष्ट हो, नीतियां जनहित में हों और निर्णय समयबद्ध क्रियान्वयन में बदलें, तब शासन केवल प्रशासन नहीं रहता, वह समाज की चेतना बन जाता है।

जनहित केन्द्रित शासन का मूल अर्थ केवल व्यवस्था चलाना नहीं, बल्कि राजधर्म, न्याय और लोककल्याण के आधार पर राज्य का संचालन करना है। जब शासन नीति से नहीं, नीयत से संचालित होता है, तब विकास आंकड़ों तक सीमित नहीं रहता, वह जनजीवन में अनुभूति बनकर उतरता है। आज यही अनुभूति हमारे राजस्थान के जन गण मन को हो रही है।

राजस्थान में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार के दो वर्ष इसी सुशासन परंपरा की पुनर्स्थापना के सशक्त साक्ष्य हैं। इन दो वर्षों में राज्य सरकार ने यह सिद्ध किया है कि स्पष्ट नीति, दृढ़ इच्छाशक्ति और जनसरोकारों के प्रति संवेदनशीलता हो तो, अल्प समय में भी बड़े परिवर्तन संभव हैं। इन दो वर्षों में राजस्थान ने न केवल विकास की गति पकड़ी है, बल्कि शासन की दिशा भी बदली है। यह कार्यकाल घोषणाओं के साथ-साथ उनके क्रियान्वयन, आकांक्षाओं की पूर्ति और उपलब्धियों का रहा है। आमजन से किए गए वादों का 70 प्रतिशत से अधिक हिस्सा मात्र दो वर्षों में पूरा होना और बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन संकेत है कि सरकार ने समय, संसाधन और संकल्प तीनों का समुचित उपयोग किया है।

इन दो वर्षों में सरकार ने यह सिद्ध किया है कि सुशासन केवल प्रशासनिक अनुशासन नहीं, बल्कि संवेदनशीलता, पारदर्शिता और परिणामों की संस्कृति है। जल, ऊर्जा, सड़क, कृषि, महिला सशक्तीकरण, स्वास्थ्य और कानून-व्यवस्था हर क्षेत्र में ठोस उपलब्धियां सामने आई हैं। इसी कारण राजस्थान आज राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में सम्मिलित हो चुका है। यही नव–उत्थान से नई–पहचान तक निरन्तर बढ़ता राजस्थान है।

सुशासन की इस निर्णायक और परिणामोन्मुख यात्रा में राजस्थान आज देश के बेस्ट परफॉर्मर स्टेट्स की अग्रिम पंक्ति में मजबूती से खड़ा है। 11 राष्ट्रीय योजनाओं में प्रथम, 5 योजनाओं में द्वितीय और 9 योजनाओं में तृतीय स्थान प्राप्त करना केवल आंकड़ों की श्रेष्ठता नहीं दर्शाता, बल्कि यह उस सशक्त शासन प्रणाली का प्रमाण है, जिसमें दूरदर्शी नीति, प्रशासनिक दक्षता और समयबद्ध क्रियान्वयन एक साथ धरातल पर उतरे हैं। नि:संदेह यह रोडमैप **'विकसित भारत@2047'** के साथ **'विकसित राजस्थान@2047'** के संकल्प को पूरा करने का संकेत है।

जनकल्याण से अन्त्योदय
अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित पहुंच

राज्य सरकार ने यह सिद्ध कर दिया है कि उसका दृष्टिकोण केवल नीतिगत नहीं, बल्कि जनहित केंद्रित और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर उसे लाभ पहुंचाने वाला है। मात्र 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना, अन्नपूर्णा रसोई योजना के तहत भोजन की करोड़ों थालियां वितरित करना, सामाजिक पेंशन में वृद्धि और प्रधानमंत्री आवास योजना के व्यापक क्रियान्वयन ने स्पष्ट किया है कि सरकार की प्राथमिकता समाज की सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति हैं। किसानों के लिए सम्मान निधि में राज्य का अतिरिक्त योगदान, ब्याज मुक्त फसली ऋण, सोलर पंप और पीएम कुसुम योजना के तहत अनुदान, साथ ही मंगला पशु बीमा योजना और गौशालाओं के लिए बढ़ाए गए अनुदान–ये सभी उपाय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में निर्णायक साबित हुए हैं। सरकार का ध्येय वाक्य 'लक्ष्य अन्त्योदय–विचार अन्त्योदय' अब वास्तव में साकार होता दिख रहा है।

जल, ऊर्जा और आधारभूत संरचना
राजस्थान के विकास की रीढ़

राम जल सेतु लिंक परियोजना (संशोधित पार्वती–कालीसिंध–चंबल लिंक परियोजना) प्रदेश की विकास गंगा बनेगी। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में इसे धरातल पर उतारने के लिए 26 हजार करोड़ रुपए के कार्यदिश जारी किए जा चुके हैं। चूरू, झुंझुनूं एवं सीकर को यमुना जल उपलब्ध करवाने की परियोजना की डीपीआर का काम तेजी से किया जा रहा है। जल जीवन मिशन के माध्यम से 13 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों तक नल से स्वच्छ जल पहुंचाया गया, जबकि भूजल संरक्षण, जल संचय और नहरों के पुनर्निर्माण ने जल आत्मनिर्भरता की ठोस नींव रखी है। ऊर्जा क्षेत्र में भी राजस्थान ने अभूतपूर्व प्रगति की है। केवल दो वर्षों में विद्युत उत्पादन क्षमता 30 हजार मेगावाट से अधिक हो गई, जिससे न केवल ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा और निवेश-आधारित विकास की दिशा में भी एक स्पष्ट संकेत मिला। आधारभूत संरचना के क्षेत्र में भी प्रदेश ने नई मिसाल कायम की है। लगभग 40 हजार किलोमीटर सड़कों का विकास, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण और 'अटल प्रगति पथ' जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं ने ग्रामीण संपर्क को मजबूत किया और विकास के लाभ को हर गांव तक पहुंचाया।

मजबूत कानून व्यवस्था विश्वास की भावना का संचार

राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ कर प्रदेशवासियों में सुरक्षा और विश्वास की भावना को मजबूत किया है। डकैती, लूट और महिला अत्याचारों में कमी, साइबर अपराधों पर नियंत्रण और धर्मांतरण विरोधी कानून जैसे निर्णायक कदमों ने समाज में स्थिरता और विश्वास का वातावरण निर्मित किया है। प्रदेश में मजबूत कानून व्यवस्था ने जनता में विश्वास की भावना का संचार किया है। हमारी माता-बहन अब निर्भीक होकर गौरवपूर्ण एवं गरिमापूर्ण जीवन जी रही हैं।

महिला सशक्तीकरण और सामाजिक सुरक्षा

राज्य सरकार ने महिला सशक्तीकरण को अपनी नीति का केंद्र बिंदु बनाया है। 'लखपति दीदी' अभियान, मातृत्व योजनाओं में वित्तीय वृद्धि, बालिकाओं को स्कूटी प्रदान करना और 'लाडो प्रोत्साहन योजना' आदि सभी प्रयासों ने महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक आत्मनिर्भरता को नई दिशा दी है और उनके सामर्थ्य को दृढ़ किया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सरकार ने उल्लेखनीय प्रगति की है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के विस्तार से 35 लाख से अधिक लाभार्थियों को कैशलैस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों के लिए विशेष योजनाओं की शुरुआत न केवल मानवीय दृष्टिकोण का प्रमाण है, बल्कि यह स्पष्ट करती है कि राजस्थान सरकार के शासन का मूल लक्ष्य हर व्यक्ति के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करना है।

विकास रथ – प्रगति का रिपोर्ट कार्ड, जनता के द्वार

राज्य सरकार ने पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी अपने सुशासन का रिपोर्ट कार्ड जनता के समक्ष प्रस्तुत किया। विकास रथ अभियान के माध्यम से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में गांव-गांव और ढाणी-ढाणी तक पहुंच बनाकर आमजन को सरकारी योजनाओं से जोड़ा गया तथा सुझाव पेटिकाओं के माध्यम से प्राप्त जन-सुझावों को आगामी बजट में समाहित करने का निर्णय लिया गया। दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की शृंखला के अंतर्गत प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों, जिलों एवं पंचायत स्तर पर स्वच्छता जागरूकता एवं श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किए गए।

'नव-उत्थान, नई-पहचान' के साथ हमारे बढ़ते राजस्थान के साक्षी बनने के लिए रन फॉर विकसित राजस्थान, राज्य स्तरीय रोजगार मेला, राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन, जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास परियोजनाओं, नवाचारों एवं उपलब्धियों पर आधारित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी, बीकानेर के लूणकरणसर में ग्रामीण समस्या समाधान शिविर, झालावाड़ के दुधालिया में महिला सशक्तीकरण सम्मेलन, मेड़ता में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन, हरयाळो राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव, नवाचार दिवस-स्टार्टअप कॉन्क्लेव, राज्य स्तरीय आरोग्य शिविर एवं रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। इन सभी प्रयासों के माध्यम से सरकार ने सुशासन, सहभागिता और समावेशी विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रभावी रूप से सुदृढ़ किया है।

सांस्कृतिक संरक्षण – विकास भी, विरासत भी

सांस्कृतिक संरक्षण के क्षेत्र में शेखावाटी हवेलियों का संरक्षण, वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ यात्रा योजना और 'पंच गौरव' कार्यक्रम ने न केवल राजस्थान की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित किया है, बल्कि प्रदेश की सांस्कृतिक आत्मा और पहचान को भी सशक्त किया है।

राजस्थान सरकार का यह दो वर्षीय कार्यकाल केवल योजनाओं और आंकड़ों का संग्रह नहीं है, बल्कि स्पष्ट दृष्टि, तीव्र निर्णय क्षमता और जनविश्वास से प्रेरित सशक्त परिवर्तन का साक्ष्य है। बीते दो वर्षों में सरकार ने यह साबित किया है कि विकास और संवेदना साथ-साथ चल सकते हैं और शासन केवल नीति निर्माण नहीं, बल्कि हर नागरिक के जीवन में वास्तविक बदलाव लाने का माध्यम बन सकता है। यह दो वर्ष केवल आंकड़ों का योग नहीं, बल्कि जन-जन के कल्याण, समृद्ध राजस्थान और सशक्त भविष्य की ठोस नींव हैं, जिन पर आने वाली पीढ़ियां गर्व महसूस करेंगी।

जन समृद्धि का प्रकाश पथ हर घर पहुंचा विकास रथ

राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित **"दो साल : नव उत्थान–नई पहचान, बढ़ता राजस्थान–हमारा राजस्थान"** कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत प्रदेशभर में विकास रथों का प्रचालन सफलतापूर्वक किया गया। इस क्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर से 50 विकास रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 200 विकास रथों को भेजा गया, जिनका उद्देश्य राज्य सरकार की बीते दो वर्षों की उपलब्धियों, जनकल्याणकारी योजनाओं एवं नीतिगत सुधारों की जानकारी आमजन तक पहुंचाना रहा।

सुशासन का रिपोर्ट कार्ड

विकास रथों के माध्यम से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में गांव-गांव और ढाणी-ढाणी तक पहुंच बनाकर आमजन को सरकार की योजनाओं से जोड़ा गया। साथ ही, विकास रथों में उपलब्ध सुझाव पेटिकाओं के माध्यम से प्राप्त जन-सुझावों को आगामी बजट में समाहित करने का निर्णय लिया गया। इस पहल से सरकार और नागरिकों के बीच सीधा संवाद स्थापित हुआ, जिससे जन-आकांक्षाओं और स्थानीय आवश्यकताओं को समझने में मदद मिली। यह प्रयास सहभागी शासन की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम सिद्ध हुआ, जिसने योजनाओं को और अधिक जनोपयोगी व प्रभावी बनाने की मजबूत नींव रखी।

विकास रथों से जन–जन तक पहुंची विकास यात्रा

प्रदेश के सभी विधान सभा क्षेत्रों में विकास रथों (एलईडी वैन) के माध्यम से व्यापक जन-जागरूकता अभियान संचालित किया गया। ऑडियो–विजुअल प्रस्तुतियों के जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, बिजली, सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तीकरण एवं किसानों से जुड़े विकास कार्यों की जानकारी सरल भाषा में आमजन तक पहुंचाई गई। योजनाओं की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और लाभों की जानकारी मिलने से ग्रामीणों में विशेष उत्साह देखा गया और विकास रथ ग्रामीण क्षेत्रों में आकर्षण का केंद्र बने। कुल मिलाकर, विकास रथों के माध्यम से संचालित यह अभियान राजस्थान सरकार की विकास यात्रा को पारदर्शिता और सहभागिता के साथ जन–जन तक पहुंचाने का प्रभावी माध्यम सिद्ध हुआ। सरकार की उपलब्धियों, नीतियों और जनकल्याणकारी प्रयासों को सीधे आम नागरिकों से जोड़ने में विकास रथों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई और "बढ़ता राजस्थान–हमारा राजस्थान" की भावना को सशक्त रूप से प्रतिबिंबित किया।

> **"राज्य सरकार जनता की सेवक के रूप में कार्य कर रही है और प्रदेश के विकास का पहिया निरंतर आगे बढ़ रहा है। हमारी सरकार ने पिछले वर्ष की भांति ही इस वर्ष भी अपने सुशासन का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा है।"**
>
> **– मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा**

राजस्थान नवाचारों की खान नवाचार दिवस-स्टार्टअप कॉन्क्लेव

राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 12 दिसंबर को राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत **'नवाचार दिवस – स्टार्टअप कॉन्क्लेव'** का आयोजन किया गया। यह सुखद है कि आज राजस्थान के युवा तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बना रहे हैं। यह समारोह रचनात्मकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नवाचार की असीम संभावनाओं का उत्सव रहा। यह कार्यक्रम युवाओं के अभिनव विचारों, रचनात्मक ऊर्जा और डिजिटल तकनीक के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ते राजस्थान की गौरवशाली यात्रा का प्रभावशाली प्रतिबिंब बना।

आईस्टार्ट राजस्थान से 7 हजार 200 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत

राज्य सरकार द्वारा आईटी क्षेत्र में की गई पहलों, डिजिटल गवर्नेंस से संबंधित सुधारों और हर जिले में नवाचार को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता से आज राजस्थान तकनीकी प्रगति का नया अध्याय लिख रहा है। आईस्टार्ट राजस्थान के माध्यम से अब तक 7 हजार 200 से अधिक स्टार्टअप पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें एक हजार करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आया है। इनमें 42 हजार 500 से अधिक रोजगार सृजित हुए हैं। ये स्टार्टअप न केवल उभरते उद्योगों को प्रोत्साहित करेंगे, बल्कि रोजगार के अवसरों का भी सृजन करेंगे।

2 हजार 600 से अधिक स्टार्टअप्स का नेतृत्व कर रही महिलाएं

स्टार्टअप शुरू करने में महिलाएं बढ़-चढ़कर आगे आ रही हैं। आईस्टार्ट पर पंजीकृत होने वाले स्टार्टअप में से 2 हजार 600 से अधिक स्टार्टअप का नेतृत्व महिलाएं तथा 288 स्टार्टअप का नेतृत्व युवा विद्यार्थी कर रहे हैं। आईस्टार्ट पर पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या बढ़कर 1 लाख 16 हजार से ऊपर पहुंच गई है। सफल स्टार्टअप नवाचार को प्रोत्साहित करने के साथ ही राजस्थान के युवाओं को बड़ी संभावनाओं वाले क्षेत्रों में ग्लोबल लीडर बनने में मददगार साबित होंगे।

एवीजीसी-एक्सआर पॉलिसी 2024

राज्य सरकार ने स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने, इनक्यूबेशन सेंटर्स स्थापित करने और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां और कार्यक्रम शुरू किए हैं। नई तकनीक में अवसर सृजित करने के लिए अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सेलेरेटर स्थापित किए जा रहे हैं एवीजीसी-एक्सआर पॉलिसी के तहत एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और एक्सटेंडेड रियलिटी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खोले गए हैं। स्टार्टअप फाउंडर्स और युवाओं के कौशल संवर्धन के लिए लर्न, अर्न एंड प्रोग्रेस (लीप) प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं।

राइजिंग राजस्थान समिट से प्रदेश निवेश गंतव्य के रूप में उभरा

युवाओं को नई तकनीक में प्रशिक्षित करने के लिए राज्य में तीन सेंटर फॉर एडवांस्ड स्किलिंग स्थापित किए जा रहे हैं। युवाओं का कौशल विकास कर उन्हें रोजगारपरक बनाने के लिए स्टेट स्किल पॉलिसी के तहत 2 साल में डेढ़ लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने पर काम किया जा रहा है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जैसी पहलों से निवेशकों का भरोसा काफी मजबूत हुआ है। गत वर्ष आयोजित इस समिट में 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू हुए और उनमें से 8 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट धरातल पर आने लगे हैं। इस समिट से एक तेजी से उभरते निवेश गंतव्य के रूप में राजस्थान की स्थिति और मजबूत हुई है।

> **"नवाचार की शुरुआत जिज्ञासा से ही होती है और तेज गति से बदलती दुनिया में नवाचार ही हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे समाज के विकास का सच्चा इंजन है।"**
>
> **– मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा**

सामूहिक श्रमदान स्वच्छ राजस्थान का आह्वान

स्वच्छ भारत मिशन

स्वच्छता किसी एक व्यक्ति या सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि यह समाज की सामूहिक चेतना और सहभागिता से जुड़ा विषय है। इसी सोच को साकार रूप देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2 अक्टूबर, 2014 को एक केंद्र प्रायोजित योजना स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का शुभारंभ किया था, जिसका उद्देश्य सभी ग्रामीण परिवारों को शौचालयों तक पहुंच प्रदान करके 2 अक्टूबर 2019 तक देश को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) बनाना था।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वितीय चरण

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वितीय चरण अप्रेल, 2020 में शुरू किया गया था और इसे 2020-21 से 2025-26 तक कार्यान्वित किया जा रहा है, इसके तहत ओडीएफ स्थिरता पर ध्यान दिया गया है और गांवों को ठोस तथा तरल कचरा प्रबंधन कवर दिया गया है और दृश्यगत स्वच्छता सुनिश्चित की गई है अर्थात् गांवों को ओडीएफ से ओडीएफ प्लस (मॉडल) गांवों में परिवर्तित किया जा रहा है। ओडीएफ प्लस का मतलब है एक ऐसा गांव, जो न सिर्फ खुले में शौच से मुक्त है, बल्कि ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन, दृश्य स्वच्छता (कम कूड़ा-कचरा और रुका हुआ पानी नहीं) और प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन पर भी ध्यान केंद्रित करता है, जिससे गांव और भी स्वच्छ और पर्यावरण-अनुकूल बन सकें।

राज्य स्तरीय स्वच्छता जागरूकता एवं श्रमदान कार्यक्रम

स्वच्छ भारत मिशन की भावना को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान स्वच्छता के जन-आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इसी क्रम में जयपुर स्थित जल महल की पाल पर 14 दिसंबर को राज्य स्तरीय **'स्वच्छता जागरूकता एवं श्रमदान कार्यक्रम'** का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने जल महल की पाल पर श्रमदान व पौधारोपण कर स्वच्छता का संदेश दिया। उन्होंने उपस्थित जनसमूह को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई।

राजस्थान के 42 हजार 492 गांव ओडीएफ प्लस घोषित

स्वच्छता के जनआंदोलन में राजस्थान प्रमुखता से कार्य कर रहा है। प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत 2 लाख 62 हजार व्यक्तिगत तथा 4 हजार से अधिक सामुदायिक शौचालयों का निर्माण हुआ है। वहीं 42 हजार 492 से अधिक गांवों को ओडीएफ प्लस घोषित किया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर संचालित किए गए 'वंदे गंगा जल संरक्षण–जन अभियान' के तहत जल स्रोतों, राजकीय कार्यालयों, अस्पतालों एवं विद्यालयों आदि की साफ-सफाई में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है।

> **“स्वच्छता समाज और सरकार की साझा जिम्मेदारी है तथा राज्य सरकार प्रदेश को स्वच्छ और सुन्दर बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।”**
>
> **– मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा**

विकास प्रदर्शनी के माध्यम से हर घर तक विकास का संदेश

राज्य सरकार के कार्यकाल के दो वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जयपुर स्थित जवाहर कला केंद्र में आयोजित **राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी** 'नव उत्थान–नई पहचान, बढ़ता राजस्थान–हमारा राजस्थान' प्रदेश की विकास यात्रा, नवाचारों और जनकल्याणकारी योजनाओं का जीवंत प्रतिबिंब बनकर सामने आई। 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस चार दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसमें बड़ी संख्या में युवाओं, विद्यार्थियों और आम नागरिकों ने सहभागिता की।

नवाचारों और डिजिटल पहल का अवलोकन

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों की स्टॉल्स का अवलोकन कर जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास परियोजनाओं, नवाचारों, उपकरणों और उपलब्धियों की जानकारी ली। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की स्टॉल पर स्थापित डिजिटल सेल्फी पॉइंट पर उन्होंने सेल्फी क्लिक करवाई तथा एआई आधारित इंटरएक्टिव पैनल के माध्यम से संचालित प्रश्नोत्तरी क्विज में भी भाग लिया। वहीं गृह विभाग की स्टॉल पर पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कुमार शर्मा ने मुख्यमंत्री को विभागीय नवाचारों से अवगत कराया, जिस पर मुख्यमंत्री ने राजकॉप ऐप के माध्यम से शिकायतों के प्रभावी निस्तारण पर संतोष व्यक्त किया।

नवाचार, स्मार्ट योजनाएं और आवासीय पहलें

प्रदर्शनी के दौरान मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग की स्टॉल पर जयपुर डिस्कॉम के प्रेजेंटेशन के माध्यम से ग्रिड डिजिटलाइजेशन की जानकारी ली और स्वायत्त शासन विभाग की स्टॉल पर सीवरेज मैनहॉल की सफाई के लिए रोबोटिक मशीन की कार्यप्रणाली देखी। नगरीय विकास एवं आवासन मंडल की स्टॉल पर राजस्थान हाउसिंग बोर्ड द्वारा हनुमानगढ़ एवं भिवाड़ी में विभिन्न आय वर्गों के लिए नई आवासीय योजनाओं का शुभारंभ किया गया। साथ ही जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जगतपुरा सेंट्रल स्पाइन योजना ब्लॉक-जी के अंतर्गत प्रतीकात्मक रूप से काश्तकारों को पट्टे वितरित किए गए तथा जेडीए की डिजिटल मार्गदर्शिका का विमोचन भी किया गया।

तकनीक और सहभागिता ने बनाया प्रदर्शनी को विशेष

प्रदर्शनी में विभागीय स्टॉल्स, डिजिटल प्रस्तुतियों और इंटरेक्टिव गतिविधियों के माध्यम से योजनाओं को केवल प्रदर्शित ही नहीं किया गया, बल्कि आमजन से संवाद भी स्थापित किया गया। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित चिलैक्स इंटरेक्टिव गेम युवाओं और नागरिकों के आकर्षण का केंद्र रहा, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से प्रतिभागियों ने योजनाओं और समसामयिक विषयों की जानकारी परखी और पुरस्कार प्राप्त किए। परिवहन विभाग की स्टॉल पर सिम्युलेटेड ड्राइविंग अनुभव के जरिए सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों की व्यावहारिक जानकारी दी गई, जिससे सुरक्षित और जिम्मेदार ड्राइविंग के प्रति जागरूकता बढ़ी।

विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी

प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने सहभागिता कर विभिन्न विभागों की योजनाओं, नागरिक सुविधाओं और तकनीकी पहलों की जानकारी प्राप्त की। इससे विद्यार्थियों में जागरूक नागरिक बनने की समझ विकसित हुई। कुल मिलाकर, यह राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी न केवल सरकार की उपलब्धियों का मंच बनी, बल्कि संवाद, तकनीक और प्रत्यक्ष सहभागिता के माध्यम से आमजन को शासन से जोड़ने का प्रभावी माध्यम भी सिद्ध हुई।

> **आमजन को योजनाओं के प्रति जागरूक किया जाए, जिससे विकसित राजस्थान@2047 के लक्ष्य की प्राप्ति की ओर तेजी से आगे बढ़ा जा सके।**
>
> **– मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा**

ग्रीन एनर्जी और जल संरक्षण की पहल हरियालो राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव

18 दिसंबर को जयपुर में आयोजित **'हरियालो राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव'** में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सरकार की दो वर्ष की पर्यावरण और जल संरक्षण संबंधी उपलब्धियों का अवलोकन किया। इस अवसर पर जल संरक्षण, हरित ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में राज्य की प्रमुख पहलों को आमजन और विशेषज्ञों के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

वंदे गंगा जल संरक्षण–जन अभियान बना आंदोलन

जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण और जल संकट जैसी गंभीर चुनौतियों के दृष्टिगत राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन बनाया है। 'वंदे गंगा जल संरक्षण–जन अभियान' के माध्यम से पारंपरिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन, वर्षा जल संचयन और जलाशयों की स्वच्छता को जनभागीदारी से जोड़ा गया है। वहीं, 'कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान' के माध्यम से प्रवासी राजस्थानियों को जोड़ते हुए 14 हजार से अधिक ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण करवाया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान से प्रेरित हरियालो राजस्थान अभियान के अंतर्गत दो वर्ष में लगभग बीस करोड़ पौधे लगाए गए हैं।

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस

ग्रीन बजट जलवायु परिवर्तन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। क्लाइमेट एक्शन प्लान-2030 और क्लीन और ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। वायु प्रदूषण की चुनौती से निपटने के लिए प्रदेश में सतत् वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों द्वारा मोबाइल वैन के माध्यम से रियल टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा रही है। राज्य सरकार सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव स्कीम- 2025 लेकर आई है। प्रदेश में ई-वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट और बैटरी वेस्ट के सुरक्षित निस्तारण के लिए अधिकृत इकाइयां संचालित की जा रही हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध जन-जागरूकता और रिवर्स वेंडिंग मशीनों के माध्यम से प्लास्टिक संग्रह को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य सरकार प्रदेश को ग्रीन इनोवेशन हब के रूप में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है।

क्लीन और ग्रीन एनर्जी में राजस्थान के बढ़ते कदम

क्लीन और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में राजस्थान तेजी से बढ़ रहा है। आज प्रदेश 22 हजार 860 मेगावाट की सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता के साथ देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत 2 हजार 272 मेगावाट की सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित की जा चुकी है। प्रदेश की सौर ऊर्जा शक्ति का ही परिणाम है कि कोयला आधारित बिजली उत्पादन पर निर्भरता घट रही है।

> **"प्रकृति के सम्मान की भारतीय संस्कृति की परंपराओं को राज्य सरकार ने अपनी नीतियों एवं अभियानों का प्रेरणा स्रोत बनाया है।"**
>
> **– मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा**

आरोग्यम्
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः

राज्य सरकार के दो वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 15 दिसम्बर को आरयूएचएस चिकित्सालय परिसर में **राज्य स्तरीय आरोग्य शिविर**, रक्तदान शिविर और विभिन्न कार्यक्रमों का शुभारंभ समारोह आयोजित किया गया। प्रदेश में विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधाओं का ढांचा तैयार करने के साथ ही गांव-ढाणियों तक गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाओं की पहुंच को सुगम बनाया जा रहा है। राज्य सरकार ने दो वर्ष सेवा और समर्पण के साथ कार्य किया है। इन दो वर्षों में सुशासन की स्थापना, विकास को गति देने और प्रदेशवासियों की खुशहाली के लिए राज्य सरकार ने हर निर्णय, हर प्रयास और हर योजना के केंद्र में जनता को ही रखा।

आरयूएचएस में क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शुभारंभ

राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर प्रदेशभर में स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन के लिए कई महत्त्वपूर्ण सौगातें दी गईं। इसी क्रम में आरयूएचएस में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शुभारंभ कर इसे प्रदेशवासियों को समर्पित किया गया है। यह ब्लॉक 20 करोड़ रुपए की लागत से बना है, जिसमें आईसीयू बेड, इमरजेंसी के लिए विशेष बेड, एडवांस्ड वेंटिलेटर सिस्टम, मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर और डायलिसिस आदि सुविधाएं हैं।

हील इन राजस्थान पॉलिसी, 2025

मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हील इन राजस्थान पॉलिसी, 2025 का विमोचन किया। इस नीति के तहत उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधाएं, विश्वस्तरीय स्वास्थ्य अवसंरचना, प्रशिक्षित मानव संसाधन और निवेश को बढ़ावा देकर न केवल देशवासियों बल्कि विदेश से आने वाले रोगियों को भी सुलभ और विश्वसनीय उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। यह नीति राज्य के स्वास्थ्य, पर्यटन और निवेश क्षेत्र को मजबूती प्रदान करेगी और राजस्थान को गुणवत्ता युक्त चिकित्सा सेवा का एक भरोसेमंद केंद्र बनाएगी।

> **"राजस्थान का हर व्यक्ति निरोगी, स्वस्थ और खुशहाल हो, इस संकल्प को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार 'स्वस्थ राजस्थान' के लक्ष्य पर प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।"**
>
> **– मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा**

दिव्यांगजनों का कल्याण

केन्द्र और राज्य की वर्तमान सरकार दिव्यांगजनों के कल्याण और सम्मान के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। इसी कड़ी में दिव्यांगजनों को व्हील चेयर और उपकरणों का वितरण किया जा रहा है। राज्य सरकार ने अपने दो बजट में डेढ़ लाख दिव्यांगजनों को 20 हजार रुपए तक के कृत्रिम अंग एवं उपकरण उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है, जिसे राज्य सरकार तेजी से पूरा कर रही है।

निःशुल्क जांचों के लिए हब एवं स्पोक मॉडल प्रारंभ

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत निःशुल्क जांचों के लिए हब एवं स्पोक मॉडल लागू किया जा रहा है। इसके तहत राजकीय चिकित्सालयों में मरीजों को ट्रोपोनिन, कैंसर मार्कर, बायोप्सी, विटामिन्स, थैलेसीमिया, हीमोफिलिया, हेपेटाइटिस और थायराइड जैसी 100 से अधिक विशिष्ट जांचें निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएंगी। राज्य में 42 मदर लैब, 137 हब लैब एवं 1 हजार 333 स्पोक चिह्नित किए गए हैं। 11 मदर लैब व 400 स्पोक का शुभारंभ किया गया है। इस मॉडल में सैंपल कलेक्शन से लेकर रिपोर्टिंग तक सभी कार्यों का रिकॉर्ड ऑनलाइन रखा जाएगा और मरीजों को घर बैठे ऑनलाइन रिपोर्ट मिल सकेगी।

नव उत्थान-नई पहचान 'रन फॉर विकसित राजस्थान'

राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित विविध कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत 21 दिसम्बर को **'रन फॉर विकसित राजस्थान'** का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अमर जवान ज्योति से हरी झंडी दिखाकर 'रन फॉर विकसित राजस्थान' को विधिवत रवाना किया। इस आयोजन में युवाओं, खिलाड़ियों, विद्यार्थियों तथा आमजन ने बड़ी संख्या में उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्वस्थ समाज के निर्माण के साथ-साथ विकसित राजस्थान के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाना रहा।

युवाओं के लिए अवसर और कौशल प्रशिक्षण

वर्तमान राज्य सरकार के गठन से पूर्व पेपर लीक जैसी घटनाओं ने युवाओं के विश्वास और मनोबल को गंभीर रूप से प्रभावित किया था। किंतु वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक आयोजित की गई 296 भर्ती परीक्षाओं में एक भी पेपर लीक की घटना सामने नहीं आई है, जो पारदर्शिता, निष्पक्षता और सुशासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राज्य सरकार का लक्ष्य आगामी वर्षों में युवाओं को चार लाख सरकारी नौकरियां प्रदान करना है। इसी दिशा में सरकार ने अपने दो वर्षों के कार्यकाल में अब तक एक लाख से अधिक नियुक्तियां प्रदान की हैं, जबकि 1.56 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रगतिरत है। इसके साथ ही राज्य सरकार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है, जिससे वे रोजगार प्राप्त करने के साथ-साथ रोजगार सृजनकर्ता भी बन रहे हैं। निजी क्षेत्र में 2 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है।

खेल प्रतिभाओं का सम्मान

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने स्वयं प्रतिभागियों के साथ दौड़ में शामिल होकर उनका उत्साहवर्धन किया। इससे पूर्व उन्होंने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का सम्मान कर उनकी उपलब्धियों की सराहना की तथा खेलों के क्षेत्र में युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने युवाओं को खेलों को करियर के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया तथा आश्वस्त किया कि राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक संसाधन, प्रशिक्षण और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।

> **"राज्य सरकार ने समाज के प्रत्येक वर्ग और हर क्षेत्र के समग्र उत्थान के लिए दूरदर्शी निर्णय लिए हैं। विशेष रूप से युवाओं के सशक्तीकरण को केंद्र में रखते हुए शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास और खेल के क्षेत्र में ठोस एवं प्रभावी कदम उठाए गए हैं।"**
>
> **– मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा**

महिला सशक्तीकरण
आधी आबादी को लगे समृद्धि के पंख

यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश की नारी शक्ति को सम्मान, सुरक्षा और गरिमा प्रदान करने के लिए अनेक दूरदर्शी पहलें की हैं। उन्होंने महिलाओं को राष्ट्रीय प्रगति का सशक्त आधार मानते हुए स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और नेतृत्व जैसे क्षेत्रों में महिला सशक्तीकरण को केंद्र में रखकर प्रभावी नीतियां लागू की हैं।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से बालिकाओं के प्रति भेदभावपूर्ण सोच को समाप्त करने की दिशा में सार्थक प्रयास किए गए हैं। इसके साथ ही उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, लखपति दीदी अभियान तथा महिलाओं के जन-धन खाते खोलने जैसी योजनाओं के जरिए महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को नई मजबूती मिली है।

राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन

इसी क्रम में महिलाओं के सशक्तीकरण और उनकी भागीदारी को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 19 दिसम्बर को धौलपुर जिले के पचगांव में और 22 दिसम्बर को झालावाड़ के दुधालिया में **राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन** का आयोजन किया गया। पचगांव में आयोजित कार्यक्रम में श्री शर्मा ने विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से राशि हस्तानांतरित की। श्री शर्मा ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 91 लाख पेंशनधारियों को 1100 करोड़ रुपए, पालनहार योजना के अंतर्गत 5 लाख 95 हजार लाभार्थियों को 103 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के तहत 5 हजार विद्यार्थियों को 2.5 करोड़ रुपए तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 1 लाख 55 हजार विद्यार्थियों को 15 करोड़ रुपए की राशि हस्तानांतरित की।

कार्यक्रम में श्री शर्मा ने राजस्थान महिला निधि द्वारा 5 हजार लखपति दीदी को 100 करोड़ रुपए की ऋण सहायता का चैक तथा लखपति दीदी, कृषि सखियों व पशु सखियों को टैबलेट का वितरण किया। मुख्यमंत्री ने स्कूली छात्राओं को साइकिल एवं दिव्यांगजन को स्कूटी भी वितरित की। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत 'आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी' का भी शुभारंभ किया। ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। इस योजना के तहत प्रदेश के लोग दूसरे राज्यों में भी कैशलेस इलाज करा सकेंगे।

लखपति दीदी योजना से 19 लाख से अधिक महिलाओं को मिला प्रशिक्षण

राज्य सरकार ने महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रदेश में 19 लाख 45 हजार महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर 12 लाख से अधिक लखपति दीदी बनाई गईं। साथ ही, लाडो प्रोत्साहन योजना से अब तक 4 लाख 60 हजार बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। इसी तरह 10 लाख 51 हजार साइकिलें और 39 हजार 586 स्कूटियां देकर बालिका शिक्षा को गति दी गई है। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत दी जाने वाली 5 हजार रुपए की राशि को बढ़ाकर 6 हजार 500 रुपए किया है। मा वाउचर योजना से अब तक 2 लाख 26 हजार महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। महिला सुरक्षा के लिए 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट तथा 65 एंटी रोमियो स्क्वॉड का गठन किया गया है। राज्य सरकार के कार्यकाल में महिला अत्याचार के मामलों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है।

> **"राज्य सरकार ने अपने दो वर्ष के कार्यकाल में महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। 'विकसित राजस्थान@2047' के संकल्प को साकार करने में हमारी आधी आबादी की महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेगी।"**
>
> **– मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा**

खुशहाल किसान उन्नत राजस्थान

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सशक्त, विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। उनके मार्गदर्शन में सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को लाभकारी बनाने तथा आधुनिक तकनीक और नवाचार को खेती से जोड़ने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। कृषि क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, फसल बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसान कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से किसानों के जीवन स्तर को सुदृढ़ किया जा रहा है।

इसी क्रम में राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 23 दिसम्बर को मेड़ता में **राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन** का आयोजन किया गया। सम्मेलन के माध्यम से किसानों को सरकार की विभिन्न योजनाओं, उपलब्धियों और भावी नीतियों की जानकारी दी गई तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रेरित किया गया।

किसानों के हित में ऐतिहासिक फैसले

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों को दी जाने वाली सहायता राशि बढ़ाकर 9 हजार रुपए कर दी गई है, जिससे किसानों को सीधा आर्थिक संबल मिला है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से भी राजस्थान के किसानों को व्यापक लाभ पहुंचाया गया है। अब यदि बीमा कंपनियों द्वारा फसल नुकसान का दावा निपटाने में देरी की जाती है, तो किसानों को उस अवधि का ब्याज भी प्रदान किया जाएगा, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान के किसानों के हित में रिकॉर्ड स्तर पर फसलों की खरीद को स्वीकृति दी गई है, जिसके अंतर्गत मूंग की 3 लाख 5 हजार 750 मीट्रिक टन, मूंगफली की 5 लाख 54 हजार 750 मीट्रिक टन तथा सोयाबीन की 2 लाख 65 हजार 750 मीट्रिक टन खरीद को मंजूरी दी गई है।

'विकसित भारत - जी राम जी' से मजदूर एवं किसानों का होगा कल्याण

'विकसित भारत–जी राम जी योजना' देश के गांवों के समग्र विकास की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण और दूरदर्शी पहल है, जो ग्रामीण क्षेत्रों का कायाकल्प करने में सहायक सिद्ध होगी। इस योजना के माध्यम से मजदूरों और किसानों के कल्याण को प्राथमिकता दी गई है। योजना के अंतर्गत अब श्रमिकों को 100 दिनों के स्थान पर 125 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि होगी। योजना का प्रस्तावित बजट बढ़ाकर 1 लाख 51 हजार 282 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो गांवों को विकसित, गरीबीमुक्त और रोजगारयुक्त बनाने की दिशा में सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

इसके साथ ही केन्द्र सरकार शीघ्र ही सीड एक्ट और पेस्टीसाइड एक्ट लागू करने जा रही है, जिससे नकली कीटनाशकों और महंगे बीजों की बिक्री करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी और किसानों के हितों की रक्षा होगी। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा शीघ्र ही वंचित और पात्र गरीब परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।

युवा उत्थान
हौसलें की उड़ान, आत्मनिर्भर राजस्थान

रोजगार, कौशल और आत्मनिर्भरता को केंद्र में रखते हुए राज्य सरकार युवाओं के सशक्त भविष्य की दिशा में निरंतर ठोस कदम उठा रही है। इसी विजन के तहत राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 25 दिसम्बर को कॉमर्स कॉलेज परिसर में **राज्य स्तरीय रोजगार मेले** का आयोजन किया गया। यह मेला युवाओं को रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता से जोड़ने की दिशा में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण बना। आयोजन में निजी क्षेत्र के 20 से अधिक सेक्टर्स से जुड़े 100 से अधिक नियोक्ताओं ने भाग लिया, जिससे युवाओं को विविध क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्राप्त हुए।

रोजगार के अवसर सृजित

राज्य सरकार ऊर्जा, उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। पांच साल में 4 लाख सरकारी एवं 6 लाख निजी रोजगार के अवसर सृजित करने के क्रम में अब तक लगभग 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं और 1.56 लाख से अधिक पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। वहीं, निजी क्षेत्र में भी 2 लाख से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। रोजगार मेला सरकार की उस सोच का प्रतीक है, जिसमें राज्य सरकार ने रोजगार, कौशल और उद्यमिता को प्राथमिकता दी है। इसमें निजी क्षेत्र के 20 से अधिक सेक्टर्स से जुड़े 100 से अधिक नियोक्ता भाग ले रहे हैं।

रोजगार सहायता शिविरों के माध्यम से अवसरों का विस्तार

राज्य सरकार द्वारा अब तक लगभग 410 रोजगार सहायता शिविरों का आयोजन किया गया है, जिनके माध्यम से 1 लाख 11 हजार से अधिक बेरोजगार अभ्यर्थियों का रोजगार के लिए चयन किया जा चुका है। इन शिविरों के माध्यम से युवाओं को निजी एवं सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों से सीधे जोड़ा गया है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा मिला है।

मुख्यमंत्री युवा संबल योजना – आत्मनिर्भरता की मजबूत नींव

युवाओं को आर्थिक संबल प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा संबल योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 4 लाख से अधिक युवा लाभान्वित हो चुके हैं तथा 1 हजार 156 करोड़ रुपए की राशि बेरोजगारी भत्ते के रूप में वितरित की जा चुकी है, जिससे युवाओं को रोजगार की तलाश के दौरान आवश्यक आर्थिक सहायता मिल रही है।

> **“राज्य सरकार युवाओं के लिए पर्यटन, सौर ऊर्जा, उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।”**
>
> **– मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा**

विकास के नए आयाम
समस्याओं का समाधान

ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास और जनसमस्याओं के त्वरित समाधान को प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार निरंतर जमीनी स्तर पर सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। इसी क्रम में 16 दिसम्बर को बीकानेर जिले के लूणकरणसर में, 17 दिसम्बर को आहोर (जालोर) में, 20 दिसम्बर को बांसवाड़ा जिले की तेजपुर ग्राम पंचायत और भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में ग्रामीण समस्या समाधान शिविर के साथ-साथ जिले के विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो शासन की जनकल्याणकारी प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण बना।

सशक्त किसान, युवा और महिला

राज्य सरकार ने किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीब वर्ग के सशक्तीकरण तथा उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। किसानों के लिए सम्मान निधि को 6 हजार रुपए से बढ़ाकर 9 हजार रुपए किया गया है, जिसे चरणबद्ध रूप से 12 हजार रुपए तक बढ़ाने की योजना है।

युवाओं के लिए सरकारी सेवाओं में अवसर बढ़ाने के क्रम में अब तक लगभग 1 लाख नियुक्तियां प्रदान की गई हैं, जबकि 1 लाख 56 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। वहीं महिलाओं और बच्चों के सशक्तीकरण के लिए प्रदेश में 12 लाख से अधिक 'लखपति दीदी' बनाई गई हैं, 10 लाख 51 हजार साइकिलें और लगभग 40 हजार स्कूटियां वितरित की गई हैं। इसके अलावा, 'लाडो प्रोत्साहन योजना' की पहली किस्त से 4 लाख 60 हजार बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है।

सिंचाई, फार्म पॉण्ड और गोशालाओं में रिकॉर्ड सुधार

राज्य सरकार ने केवल दो वर्षों में कृषि और पशुपालन क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां दर्ज की हैं, जो पूर्ववर्ती सरकार के पांच वर्षों के कार्यों से कहीं अधिक हैं। पिछले पांच वर्षों में 52 हजार हेक्टेयर भूमि को नहरी तंत्र से सिंचाई सुविधा प्रदान की गई थी, जबकि वर्तमान सरकार ने मात्र दो वर्षों में लगभग 85 हजार हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा से जोड़ा है।

वर्तमान सरकार ने मात्र दो वर्षों में 35 हजार से अधिक फार्म पौंड का निर्माण और 299 लाख मीटर तारबंदी कार्य सम्पन्न किया है। गोशालाओं के विकास में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। वर्तमान सरकार ने दो वर्षों में 3 हजार 433 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है।

> **"हमारी सरकार गरीब को गणेश मानकर सेवक के रूप में कार्य कर रही है। हमारी डबल इंजन की सरकार में कथनी और करनी में कोई भेद नहीं है। हम जो कहते हैं, वह करते हैं।"**
>
> **– मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा**

आयोजक
Rajasthan Foundation | BIP RAJASTHAN | RIICO GROW WITH RAJASTHAN
इंडस्ट्री पार्टनर
CII Confederation of Indian Industry

प्रवासी राजस्थानियों का वैश्विक महाकुंभ

प्रवासी राजस्थानी दिवस
10 दिसम्बर 2025 • जयपुर

जहां न पहुंचे बैलगाड़ी, वहां पहुंचे मारवाड़ी

डॉ. गोरधन लाल शर्मा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा

"अपि स्वर्णमयी लङ्का न मे लक्ष्मण रोचते।
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी॥"

(वाल्मीकि रामायण)

(अर्थ : हे लक्ष्मण! चाहे लंका स्वर्ण से बनी क्यों न हो, वह मुझे प्रिय नहीं है; क्योंकि माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी अधिक महान होती हैं।)

वाल्मीकि रामायण की ये पंक्तियां केवल राम-लक्ष्मण संवाद का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि भारतीय सभ्यता की उस मूल चेतना को अभिव्यक्त करती हैं, जिसमें मातृभूमि और जन्मस्थल के प्रति अनुराग सर्वोपरि माना गया है। समृद्धि, वैभव और भौतिक सुविधाओं से युक्त स्वर्णमयी लंका भी श्रीराम को आकर्षित नहीं कर पाती, क्योंकि उनके लिए जन्मभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊपर है। यही भाव भारतीय समाज में प्रवास और मातृभूमि के संबंध को समझने की कुंजी प्रदान करता है।

"प्रदेश के विकास में प्रवासी राजस्थानी समुदाय का सहयोग सदैव अमूल्य रहा है। देश-विदेश में बसे हमारे राजस्थानी भाई-बहन अपनी मातृभूमि के प्रति समर्पित हैं तथा राज्य की प्रगति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।"

– मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा

इसी भावभूमि पर डायस्पोरा की अवधारणा आधारित है। डायस्पोरा (Diaspora) मूल रूप से ग्रीक भाषा का शब्द है। जिसका अर्थ है - बिखरा हुआ, इसका आशय जगह-जगह पर बीज बोना भी होता है। आधुनिक संदर्भों में इसका प्रयोग उन समुदायों के लिए किया जाता है, जो आजीविका, अवसर या ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण अपने मूल स्थान से दूर जाकर अन्य देशों में बस गए हैं, किंतु अपनी जन्मभूमि, संस्कृति और पहचान से भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं। यहूदी, चीनी और भारतीय डायस्पोरा इसके प्रमुख उदाहरण हैं।

भारतीय डायस्पोरा – भारत की वैश्विक उपस्थिति का सशक्त माध्यम

भारतीय डायस्पोरा विश्व के लगभग हर कोने में फैला हुआ है और वह भारत के लिए मात्र एक प्रवासी समुदाय नहीं, बल्कि देश की विदेश नीति, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक धरोहर का एक अनमोल हिस्सा है। यह वैश्विक समुदाय भारत की छवि को व्यापक रूप से मजबूत करता है तथा विभिन्न देशों के साथ भारत के संबंधों को सुदृढ करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्ष 2025 के आंकड़ों के अनुसार, विश्व में भारतीय प्रवासी की संख्या लगभग 3.5 करोड़ के आस-पास है, जो विश्व के सबसे बड़े प्रवासी समुदायों में से एक है। इन लोगों ने जहां आर्थिक क्षेत्रों में अद्भुत योगदान दिया है, वहीं राजनयिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाया है।

संघर्ष से सफलता तक – भारतीय डायस्पोरा की ऐतिहासिक यात्रा

भारतीय डायस्पोरा की यात्रा केवल समृद्धि और सफलता की कहानी नहीं है। इसके पीछे संघर्ष, त्याग, अनुकूलन और निरंतर परिश्रम की लंबी प्रक्रिया निहित है। वैश्वीकरण, उदार आर्थिक नीतियों और रोजगार के अवसरों की तलाश ने भारतीयों को प्रवास के लिए प्रेरित किया। इसके बावजूद भारतीय प्रवासी समुदाय ने अपनी भाषा, संस्कृति, परंपराओं और पारिवारिक मूल्यों को जीवित रखा तथा भारत की 'विविधता में एकता' की अवधारणा को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठित किया।

प्रवासी दिवस की अवधारणा

इसी ऐतिहासिक और भावनात्मक जुड़ाव को औपचारिक पहचान देने के उद्देश्य से भारत सरकार प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाती है। यह दिवस महात्मा गांधी के 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने की स्मृति से जुड़ा हुआ है और प्रवासी भारतीयों के योगदान को राष्ट्र निर्माण से जोड़ता है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रवासी भारतीय दिवस जैसी पहलों ने यह सिद्ध किया कि जब प्रवासी समुदाय को संगठित मंच और संस्थागत संवाद प्रदान किया जाता है, तो उसका प्रभाव देश के समग्र विकास में दिखाई देता है।

राष्ट्रीय दृष्टिकोण से प्रादेशिक पहल तक

इसी राष्ट्रीय अनुभव और दृष्टिकोण ने यह आवश्यकता रेखांकित की कि भारत के वे राज्य, जिनका प्रवासी समुदाय संख्या और प्रभाव दोनों की दृष्टि से व्यापक है, अपने स्तर पर भी ऐसी ही संरचित पहल करें। इस संदर्भ में राजस्थान का नाम विशेष रूप से उभरकर सामने आता है। ऐतिहासिक रूप से राजस्थान के निवासी व्यापार, उद्योग, शिक्षा और सेवा के क्षेत्रों में देश-विदेश तक सक्रिय रहे हैं और प्रवासी राजस्थानी समुदाय ने वैश्विक मंच पर राज्य की पहचान को सुदृढ़ किया है।

प्रवासी राजस्थानी दिवस – अवधारणा और मूल भावना

इसी क्रम में राजस्थान सरकार के समक्ष यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि प्रवासी

राजस्थानियों की यह विशाल सामाजिक और आर्थिक पूंजी तब और अधिक प्रभावी सिद्ध हो सकती है, जब उसे राज्य की विकास योजनाओं, निवेश संभावनाओं और सांस्कृतिक संरक्षण से व्यवस्थित रूप से जोड़ा जाए। इसी पृष्ठभूमि में प्रवासी राजस्थानी दिवस की अवधारणा ने आकार लिया। इसके पीछे मूल भावना यह थी कि प्रवासी राजस्थानियों को केवल सम्मानित ही न किया जाए, बल्कि उन्हें राज्य की विकास यात्रा का सक्रिय सहभागी भी बनाया जाए।

10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में इस विचार को औपचारिक स्वरूप प्रदान किया गया। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के दौरान प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने की घोषणा की गई। यह निर्णय मात्र प्रतीकात्मक नहीं था, बल्कि इसके माध्यम से एक स्थायी संवाद तंत्र, निवेश सहयोग और सांस्कृतिक जुड़ाव की ठोस नींव रखी गई। इस पहल ने स्पष्ट कर दिया कि राजस्थान अपने वैश्विक परिवार के अनुभव, ज्ञान और संसाधनों को राज्य की विकास यात्रा और विकसित राजस्थान के लक्ष्य से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस

इसी पृष्ठभूमि में 10 दिसंबर 2025 को जयपुर स्थित जेईसीसी सभागार में प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन एक स्वाभाविक परिणति के

रूप में सामने आया। यह आयोजन उस दृष्टिकोण का मूर्त रूप था, जिसमें राज्य अपने प्रवासी नागरिकों को केवल अतीत की स्मृति के रूप में नहीं, बल्कि भविष्य के सहभागी के रूप में देखता है। इस ऐतिहासिक समारोह के भव्य उद्घाटन के अवसर पर राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागडे, पंजाब के राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल, केन्द्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव, केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल, केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री श्री भागीरथ चौधरी, वेदांता ग्रुप के चेयरमैन श्री अनिल अग्रवाल और टाटा पावर के सीईओ और एमडी श्री प्रवीर सिन्हा सहित कई नामी उद्योगपति, देश-विदेश से आए प्रवासी राजस्थानी एवं गणमान्यजन उपस्थित रहे।

राजस्थान फाउंडेशन के 14 नए चैप्टर होंगे स्थापित

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर प्रदेश और प्रवासी समुदाय के जुड़ाव को मजबूत करने के उद्देश्य से राजस्थान फाउंडेशन के 14 नए चैप्टर स्थापित करने की घोषणा की। इनमें से 9 विदेशों और 5 देश के विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने अगले वर्ष फिर से राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के आयोजन की घोषणा भी की।

प्रवासी राजस्थानियों के हितों के लिए नए विभाग का गठन

उल्लेखनीय है कि प्रवासी राजस्थानियों के हितों के लिए राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामले विभाग का गठन किया गया है। यह विभाग प्रवासियों और सरकार के बीच संवाद स्थापित करेगा, उनके मुद्दों का समाधान करेगा और नीति निर्माण में सहयोग करेगा। इसके तहत प्रवासी राजस्थानियों के सम्मान समारोह, दिवस और एक्सचेंज प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। प्रवासी एसोसिएशनों का पंजीकरण भी इसी विभाग द्वारा संचालित होगा।

9 प्रवासी विभूतियों को प्रवासी राजस्थानी सम्मान

कार्यक्रम में देश-विदेश में विशिष्ट उपलब्धियां हासिल करने पर प्रवासी राजस्थानियों श्री अनिल अग्रवाल, श्री कुमार मंगलम बिड़ला, श्री विनीत मित्तल, श्री अजय पीरामल, श्री माधव सिंघानिया, श्री पूनमचंद राठी, श्री नरसी कुलरिया, श्री सी.एम. मूंदड़ा और श्री प्रदीप राठौड़ को 'प्रवासी राजस्थानी सम्मान' दिया गया।

प्रवासी राजस्थानी नीति (एनआरआर पॉलिसी)

प्रवासी राजस्थानी दिवस के अवसर पर 'प्रवासी राजस्थानी नीति 2025' जारी की गई, जो विश्वभर में बसे राजस्थानियों को पहचान, सुविधा और निवेश के लिए रोडमैप प्रदान करेगी। राजस्थान सरकार ने प्रवासी राजस्थानियों को उनकी मातृभूमि से जोड़ने और राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष नीति तैयार की है। इस नीति के क्रियान्वयन और समन्वय का जिम्मा राजस्थान फाउंडेशन (RF) को सौंपा गया है।

नीति के पांच प्रमुख स्तंभ

पहला स्तंभ : एक्सीलरेट, प्रवासियों के लिए निवेश और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है। इसके तहत निवेश प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा और निवेश सलाहकार परिषद तथा निवेश सुविधा सेल की मदद से प्रवासियों को मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा।

दूसरा स्तंभ : ब्रिज, डिजिटल और सांस्कृतिक जुड़ाव को मजबूत करता है। इसमें प्रवासियों और राज्य सरकार के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंस, सोशल मीडिया संवाद और 'प्रवासी राजस्थानी दिवस' जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से सीधे संपर्क को बढ़ावा दिया जाएगा। जयपुर में स्थापित 'प्रवासी राजस्थानी केंद्र' प्रवासियों के लिए एक केंद्रीकृत संसाधन स्थल के रूप में कार्य करेगा।

तीसरा स्तंभ : सेलिब्रेट, राजस्थानी कला, संस्कृति और विरासत को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करने पर केंद्रित है। राज्य में प्रमुख त्योहारों का आयोजन ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में किया जाएगा और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रवासियों को सम्मानित किया जाएगा।

चौथा स्तंभ : ड्राइव, प्रवासियों की परोपकारी भागीदारी को राज्य के विकास से जोड़ता है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, पशु कल्याण और धरोहर संरक्षण जैसी पहलों में प्रवासियों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा।

पांचवां और अंतिम स्तंभ : एन्श्योर, प्रवासियों और उनके परिवारों की सहायता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इसके लिए राजस्थान संपर्क पोर्टल पर विशेष व्यवस्था की जाएगी और प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे।

सशक्त सहयोग और सामूहिक विकास

नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार एक समर्पित विभाग की स्थापना करेगी, जबकि राजस्थान फाउंडेशन की कार्यकारी समिति समय-समय पर समीक्षा करके आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करेगी। यह नीति न केवल प्रवासियों को उनकी जड़ों से जोड़ती है, बल्कि राज्य और प्रवासियों के बीच सशक्त सहयोग और सामूहिक विकास को भी बढ़ावा देती है।

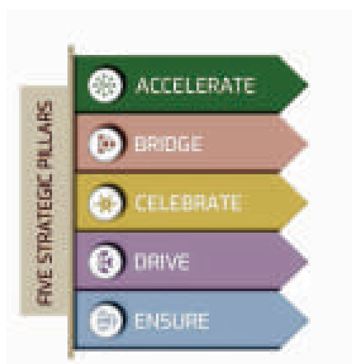

Scan for
NRR Policy 2025

नई राजस्थान पर्यटन नीति एक दूरदर्शी दस्तावेज

राजस्थान सरकार ने राज्य को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर शीर्ष स्थान दिलाने और '**विकसित राजस्थान@2047**' के विजन को साकार करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार प्रवासी राजस्थानी दिवस के अवसर पर राज्य की महत्वाकांक्षी **राजस्थान पर्यटन नीति–2025** औपचारिक रूप से जारी की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सीतापुरा स्थित जेईसीसी परिसर में आयोजित पर्यटन सत्र के दौरान इस नीति का विमोचन किया। यह नीति राजस्थान के पर्यटन विकास को नई दिशा देने वाला एक दूरदर्शी दस्तावेज़ है, जो राज्य को राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर अग्रणी स्थान दिलाने में सहायक सिद्ध होगी। नई पर्यटन नीति निवेश, नवाचार, रोजगार और सामुदायिक सहभागिता को नई गति देगी।

राजस्थान पर्यटन नीति–2025 के मुख्य बिंदु

- अंतरराज्यीय धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के सहयोग से **कृष्ण गमन पथ** (मथुरा से संदीपनी आश्रम, उज्जैन, मध्य प्रदेश) और **बृज-द्वारका तीर्थ मार्ग** (मथुरा से द्वारका, गुजरात) से संबंधित राजस्थान के मंदिरों और आध्यात्मिक स्थानों पर तीर्थयात्री सुविधाओं का निर्माण करवाया जाएगा। **कृष्ण गमन पथ** के अंतर्गत भरतपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, बूंदी, कोटा, झालावाड़ आदि के मंदिरों/तीर्थ स्थलों को शामिल करने का प्रस्ताव है। **बृज-द्वारका तीर्थ मार्ग** के अंतर्गत भरतपुर, मेहंदीपुर बालाजी, गोविंद देव जी (जयपुर), पुष्कर (अजमेर), चारभुजा (राजसमंद), श्रीनाथ जी (नाथद्वारा, राजसमंद), जगदीश मंदिर (उदयपुर), दत्तात्रेय मंदिर (माउंट आबू) आदि के मंदिरों/तीर्थ स्थलों को शामिल करने का प्रस्ताव है।
- वन विभाग, देवस्थान विभाग एवं अन्य विभागों के समन्वय कर वन्यजीव अभयारण्य एवं धार्मिक पर्यटन क्षेत्रों के आस पास **पर्यटन हब** विकसित कर पर्यटकों हेतु विभिन्न सुविधाओं का विकास किया जाएगा।
- प्रदेश **शौर्य पर्यटन सर्किट** विकसित करने हेतु तनोट माता, लोंगेवाला, आदि को शामिल करते हुए वॉर मेमोरियल एवं विभिन्न प्रकार के टूरिज्म प्रोजेक्ट्स विकसित किए जाएंगे।
- केवलादेव, ताल-छापर, सांभर आदि पर स्थान चिन्हित कर **बर्ड-वाचिंग सर्किट** विकसित किए जाएंगे।
- पिछोला लेक, चम्बल रिवर फ्रंट, आनासागर आदि पर प्रोजेक्शन मैपिंग, लाइट एन्ड साउंड शो आदि विकसित किए जाएंगे।
- मुख्य ट्रांजिट स्थानों जैसे की एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, आदि पर प्रीपेड टैक्सी बूथ शुरू किए जाएंगे।
- परकोटा पर्यटन क्षेत्रों, **ईको-सेंसिटिव क्षेत्रों** एवं बड़े पर्यटन मोनुमेंट्स में battery-powered सेगवेज, रेंटल साइकिल, गाईडेड ई-व्हीकल टूर अनुमत किए जाएंगे।
- पर्यटकों हेतु **राजस्थान ट्रेवल कार्ड** लांच किया जायेगा, ताकि पर्यटक ट्रांसपोर्ट के उपलब्ध विभिन्न साधनों (बस, मेट्रो, रेल, टैक्सी आदि) में एक सिंगल कार्ड से यात्रा कर सके।
- **होम-स्टे एवं पेइंग गेस्ट आवास सुविधाएं** aggregator-based ऑनलाइन प्लेटफार्म पर विकसित की जाएंगी।
- राज्य में चयनित विरासत स्मारकों जैसे जंतर मंतर, अल्बर्ट हॉल, हवा महल, आदि के 3-डी लिडार स्कैनिंग और 3-डी मॉडलिंग उपलब्ध है, जिनका उपयोग कर निजी क्षेत्र की भागीदारी से वी-आर शो, 3-डी वॉकथ्रू, **डिजिटल संग्रहालय, लाइट एंड साउंड शो** आदि विकसित किए जाएगे।

- प्रदेश में कार्यरत सभी टूरिज्म व्यवसायों की लिस्टिंग एवं ग्रेडिंग हेतु एक सिंगल वेब पोर्टल बनाया जाएगा। **राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट** (आरडीटीएम) एवं **ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार** (जीआईटीबी) जैसे पर्यटन इवेंट्स/कांफ्रेंस मुख्य जिला स्तरों पर भी आयोजित की जाएंगी।
- पर्यटन व्यवसाय के प्रमोशन एवं पर्यटन क्षेत्र में नवाचारों को बढ़ावा देने हेतु प्रतिवर्ष राजस्थान पर्यटन पुरस्कार आयोजित किए जाएंगे, जिसके तहत पर्यटन क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे पर्यटन व्यवसायियों को पुरस्कार दिए जाएंगे। पर्यटन मार्केटिंग हेतु नई पर्यटन फ़िल्में, शार्ट क्लिप्स आदि का निर्माण कर मार्केटिंग के सभी माध्यमों पर प्रचारित किया जाएगा।
- चयनित जिलों में **विशेष पर्यटन क्षेत्र** (STZ) प्लग-एंड-प्ले मॉडल पर विकसित किए जाएंगे। इन क्षेत्रों में आधारभूत ढांचा राज्य सरकार द्वारा और पर्यटन व आतिथ्य सुविधाएं निजी क्षेत्र द्वारा विकसित की जाएंगी। ये क्षेत्र नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्व विभाग, RIICO आदि द्वारा चिन्हित भूमि पर सभी आवश्यक अनुमतियों के साथ बनाए जाएंगे।
- **ईज ऑफ डूइंग** को बढ़ावा देने हेतु पर्यटन की विभिन्न नीतियों एवं स्कीम्स के अंतर्गत सभी प्रोजेक्ट्स की अनुमति और अनुमोदन हेतु सिंगल वेब पोर्टल बनाया जाएगा।
- नीति के तहत निजी सार्वजानिक सहभागिता एवं स्विस चैलेंज मॉडल पर पर्यटन प्रोजेक्ट्स विकसित किए जाएंगे।
- विद्यार्थियों को पर्यटन कोर्सेज एवं स्किलिंग प्रोग्राम हेतु स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। RIPS - 2024 के अंतगर्त उपलब्ध प्रावधानों के तहत पर्यटन व्यवसायियों को ट्रेनिगं एवं स्किलिंग इंसेंटिव दिए जाएंगे।
- पर्यटन सरंचना को सुदृढ़ करने एवं पर्यटन स्थलों के बेहतर प्रबंधन हेतु विभिन्न कार्य जैसे की टूरिज्म मास्टर प्लान, **अडॉप्ट-अ-टूरिज्म साइट**, डिजिटल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, आदि कार्य करवाए जाएंगे।
- जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में प्रत्येक जिले में गठित जिला पर्यटन विकास समिति (DTDC), जिला स्तर पर पर्यटन स्थलों के विकास, संचालन और प्रबंधन हेतु **डेस्टिनेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन** (DMO) के रूप में भी कार्य करेगी। पीक पर्यटन सीजन के दौरान इस समिति द्वारा समस्याओं के समाधान हेतु माह में कम से कम एक बार बैठक आयोजित की जाएगी।
- **कल्चरल हेरिटेज** को संवर्धित करने हेतु मैनुस्क्रिप्ट, फॉसिल्स, ट्राइबल हेरिटेज, टेक्सटाइल्स आदि के इको सिस्टम को मजबूत किया जायेगा।
- **क्राफ्ट म्यूजियम** को बढ़ावा देने हेतु ब्लू पॉटरी, बाड़मेर एवं जोधपुर के लकड़ी के फर्नीचर, कोटा एवं उदयपुर की मिनिएचर आर्ट एवं नाथद्वारा की पिछवाई पेंटिंग पर क्राफ्ट म्यूजियम विकसित किए जाएंगे।
- राजस्थान पर्यटन के **डिजिटल टचपॉइंट** बढ़ाने हेतु नया राजस्थान टूरिज्म वेब पोर्टल, टूरिज्म एप, चैटबॉट, डिजिटल मैप्स एवं गाइडबुक्स, **डिजिटल म्यूजियम** आदि विकसित किए जाएंगे।
- पर्यटन स्थलों की एयर-कनेक्टिविटी बेहतर बनाने हेतु वायबिलिटी गैप फंडिंग के तहत इंसेंटिव दिए जाएंगे। प्रदेश के मुख्य पर्यटन शहरों हेतु हॉप ऑन हॉप ऑफ बस सर्विस चलाई जाएगी।
- प्रदेश में वर्तमान पर्यटन मेलों और त्योहारों यथा मरु महोत्सव, पुष्कर मेला, झील महोत्सव, माही महोत्सव आदि को वृहद् स्तर पर आयोजित किया जाएगा। साथ ही निजी भागीदारी से नई थीम्स जैसे की कॉन्सर्ट टूरिज्म, इको एडवेंचर, आदि पर पर्यटन मेले एवं महोत्सव का आयोजन किया जाएगा।
- राजस्थान के प्रमुख मेलों (जैसे की पुष्कर फेस्टिवल, डेजर्ट फेस्टिवल, तीज फेस्टिवल) के दौरान पर्यटकों के आगमन में वृद्धि हेतु विभिन्न पैकेज टूर विकसित किए जाएंगे।
- बड़े कॉन्सर्ट, इवेंट्स एवं **टूरिज्म फेस्टिवल्स** आयोजित करने हेतु multi-purpose स्टेडियम के विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।
- प्रदेश में **एस्ट्रो टूरिज्म** को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न स्थानों जैसे की अलवर, जयपुर, जैसलमेर, माउंट आबू, उदयपुर में नाईट स्काई ऑब्जरवेटरीज, स्टार गेजिंग डेक आदि का विकास किया जाएगा।
- **कलनरी टूरिज्म** को बढ़ावा देने हेतु ख्याति प्राप्त शेफ के साथ विभिन्न स्थानों पर **फूड फेस्टिवल** का आयोजन किया जाएगा। एम्यूजमेंट पार्क, **फार्मूला- 1 ट्रैक, इमर्सिव एंटरटेनमेंट** हब आदि बड़े पर्यटन प्रोजेक्ट्स हेतु सरकार द्वारा सपोर्ट किए जाने के प्रयास किए जाएंगे।
- प्रदेश में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु हॉट एयर बैलूनिंग, ज़िप लाइनिंग, पैरा-ग्लाइडिंग आदि हेतु प्री-नोटिफाइड सेफ्टी ज़ोन्स एवं फ़ास्ट ट्रैक क्लीयरेंस आदि की सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
- गोल्फ कोर्स, रिसॉर्ट्स, एस्ट्रो साइट्स, रोपवे प्रोजेक्ट्स हेतु साइट्स चिन्हित कर पर्यटकों हेतु सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
- प्रदेश में फिल्म सिटी एवं संबंधित पर्यटन सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
- आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, योगा आदि को शामिल करते हुए प्रदेश में **वैलनेस टूरिज्म हब** एवं इको-सर्टिफाइड वैलनेस रिसोर्ट आदि के विकास को बढ़ावा दिया जाएगा।
- राजस्थान को प्रमुख वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु जयपुर, उदयपुर जैसे प्रमुख शहरों के चुनिंदा क्षेत्रों को 24x7 नाइटलाइफ/लेट-नाइट टूरिज्म जोन के रूप में विकसित किया जाएगा। ये विकास कार्य सभी पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किए जाएंगे।
- **टूरिज्म सेफ्टी** हेतु एक 24X7 कॉल सेंटर की स्थापना की जाएगी, **टूरिस्ट असिस्टेंस फोर्स** (टेफ) को अधिक सुदृढ़ बनाया जाएगा, टूरिस्ट व्हीकल्स में पैनिक बटन, क्यू-आर बेस्ड फीडबैक सिस्टम, सीसीटीवी, IEC एक्टिविटीज आदि कार्य किए जाएंगे।
- **राजस्थान पर्यटन नीति - 2025** राजस्थान में पर्यटन के विकास एवं मार्केटिंग हेतु एक मार्गदर्शक डॉक्यूमेंट के रूप में रहेगी। पर्यटन से संबंधित समस्त नीतियां, स्कीम्स, गाइडलाइन्स राजस्थान पर्यटन नीति 2025 के अंतर्गत रहेगी।

राजस्थान पर्यटन, कला व संस्कृति विभाग की भव्य सांस्कृतिक संध्या

प्रवासी राजस्थानी दिवस-2025 की शाम लोक नृत्य और संगीत के नाम रही। पर्यटन, कला व संस्कृति विभाग द्वारा जेईसीसी परिसर में भव्य और गरिमामयी सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया।

सांस्कृतिक संध्या में प्रसिद्ध लोक कलाकार पद्मश्री गुलाबो सपेरा और उनकी टीम ने अद्वितीय कालबेलिया नृत्य की प्रस्तुति दी। उनके नृत्य ने प्रवासी राजस्थानियों के मन में अपनी मिट्टी की खुशबु और लोक–नृत्य की परम्परा को पुन: जीवित कर दिया।

राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य

घूमर (Ghoomar) – राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य, जो महिलाओं द्वारा घूंघट निकालकर गोलाकार नृत्य के रूप में किया जाता है, इसे 'नृत्यों का सिरमौर' भी कहा जाता है।

कालबेलिया (Kalbeliya) – सपेरा समुदाय द्वारा किया जाने वाला यह नृत्य, अपनी सम्मोहक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है।

तेरहताली (Terah Tali) – कामड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला,जिसमें शरीर पर 13 मंजीरे बांधकर बैठकर प्रदर्शन किया जाता है।

चरी नृत्य (Chari Dance) – किशनगढ़ का प्रसिद्ध नृत्य, जिसमें महिलाएं सिर पर चरी (मटका) लेकर नृत्य करती हैं, जिसे फलकू बाई ने प्रसिद्ध किया।

भवई (Bhavai) – सिर पर कई मटके रखकर तलवार या कांच के टुकड़ों पर किया जाने वाला एक चुनौतीपूर्ण नृत्य।

गैर (Gair) – होली के अवसर पर भील समुदाय के पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य।

कच्छी घोड़ी (Kachchi Ghodi) – शेखावाटी क्षेत्र में विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य, जिसमें नर्तक बांस और कागज से बनी घोड़ी पहनते हैं।

अग्नि नृत्य (Agni Dance) – बीकानेर के जसनाथी संप्रदाय द्वारा धधकते अंगारों पर किया जाने वाला एक रोमांचित नृत्य।

गवरी (Gavari) – मेवाड़ में भील आदिवासियों द्वारा किया जाने वाला नाट्य।

चकरी नृत्य (Chakri Dance) – हाड़ौती क्षेत्र में कंजर जनजाति की महिलाओं द्वारा तेज गति से किया जाता है।

ढोल नृत्य (Dhol Dance) – जालौर का प्रसिद्ध नृत्य। यह विवाह के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है।

पणिहारी (Panihari) – यह एक प्रेम-आधारित राजस्थानी नृत्य है। इसमें स्त्रियां अपने सिर पर मटके रखकर नृत्य करती हैं।

प्रवासी राजस्थानी दिवस के अवसर पर

बैटरी एनर्जी स्टोरेज, शिक्षा, चिकित्सा और माइनिंग पर विशेष सत्र आयोजित

प्रदेश के अन्नदाता बन रहे ऊर्जा दाता

बैटरी एनर्जी स्टोरेज पर सत्र

राजस्थान न केवल देश के, बल्कि वैश्विक अक्षय ऊर्जा मानचित्र पर अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आज राजस्थान सौर ऊर्जा और समग्र अक्षय ऊर्जा क्षमता, दोनों में देश में प्रथम स्थान पर है। इस परिवर्तन में प्रवासी राजस्थानियों का ज्ञान, पूंजी और ग्लोबल नेटवर्क अत्यंत मूल्यवान है। राज्य सरकार राजस्थान को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश को ऊर्जा लेने वाले के स्थान पर देने वाले राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए कई महत्त्वपूर्ण निर्णय किए गए हैं। राज्य सरकार ने अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं और पार्कों के लिए 23,386 हेक्टेयर भूमि आवंटित की है, जिसके माध्यम से लगभग 10,202 मेगावाट क्षमता विकसित होने जा रही है।

पीएम-कुसुम योजना में राजस्थान की अग्रणी भूमिका

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश के किसानों को सशक्त बनाने और उन्हें अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता बनाने के लिए पीएम कुसुम जैसी अनुपम योजना चलाई है। इसमें राजस्थान पूरे देश के लिए मार्गदर्शक राज्य बनकर उभरा है। राज्य सरकार ने पीएम-कुसुम (कम्पोनेंट ए और सी) के अंतर्गत 10,533 मेगावाट क्षमता की 5,002 सौर परियोजनाओं के लिए कार्यदेश जारी किए हैं और 2,272 मेगावाट की 1,019 परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं। कम्पोनेंट-ए में तो राजस्थान पूरे देश में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है।

ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर राजस्थान

अक्षय ऊर्जा निगम एवं विद्युत उत्पादन निगम को 26,784 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्कों के लिए 51,808 हेक्टेयर भूमि का अतिरिक्त आवंटन किया गया है, जो आने वाले वर्षों में गीगावाट स्तर की परियोजनाओं का मजबूत आधार बनेगा। वहीं, 964 मेगावाट सोलर कैप्टिव प्लांटों एवं 1,514 मेगावाट क्षमता वाले सोलर प्लांटों को स्वीकृति दी जा चुकी है, जो उद्योगों और बड़े उपभोक्ताओं को स्वच्छ, सस्ती और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा देंगे। सौर ऊर्जा परियोजनाओं ने पश्चिमी राजस्थान में लोगों का भाग्य बदल दिया है। प्रदेश में पीक ऑवर्स की डिमांड को पूरा करने के लिए बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली को गति दी गई है। राज्य में 6 हजार मेगावाट की भंडारण प्रणाली विकसित की जा रही है।

> राजस्थान न केवल देश के, बल्कि वैश्विक अक्षय ऊर्जा मानचित्र पर अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आज हमारा प्रदेश सौर ऊर्जा और समग्र अक्षय ऊर्जा क्षमता, दोनों में देश में प्रथम स्थान पर है। राज्य सरकार राजस्थान को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
>
> **– मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा**

शिक्षा, कौशल, नवाचार और अनुसंधान

शिक्षा पर सत्र

शिक्षा का देश एवं प्रदेश की प्रगति में बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। 21वीं सदी में ज्ञान ही पूंजी है। यह हमारे युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करती है। शिक्षा, कौशल, नवाचार और अनुसंधान आधुनिक अर्थव्यवस्था के चार प्रमुख स्तंभ हैं और इन्हें मजबूत कर हम अर्थव्यवस्था को अभूतपूर्व गति दे सकते हैं। आज राजस्थान इन सभी क्षेत्रों में अग्रणी बनने की ओर अग्रसर है।

उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा

प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। बारहवीं कक्षा के तुरंत बाद राज्य के युवाओं के लिए कौशल उन्नयन और रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से अर्ली कैरियर प्रोग्राम टेकबी शुरू किया है। साथ ही, स्कूली छात्रों में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आई.स्टार्ट कार्यक्रम का विस्तार किया गया है। राज्य सरकार द्वारा स्टार्टअप पॉलिसी, अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सेलरेटर, एवीजीसी-एक्सआर पॉलिसी, सेंटर फॉर एडवांस्ड स्किलिंग, स्टेट स्किल पॉलिसी जैसे अनेक निर्णयों से युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खोले गए हैं।

स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना

राज्य में शिक्षा क्षेत्र का अभूतपूर्व विस्तार किया गया है, जो ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की नींव तैयार कर रहा है। पिछले दो साल में प्रदेश में 71 नए राजकीय महाविद्यालय और 21 नए राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले गए हैं। 177 नए कॉलेज भवनों का लोकार्पण किया गया है। राजकीय विद्यालयों में व्यापक स्तर पर रोशनी, रंग-रोगन, स्वच्छता और सौंदर्यीकरण का महत्त्वपूर्ण कार्य हुआ है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में विद्यालयों का एक साथ कायाकल्प किया गया है। साथ ही विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम और डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना, विज्ञान-गणित किट का वितरण और सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनें लगाई गई हैं।

> शिक्षा, कौशल, नवाचार और अनुसंधान आधुनिक अर्थव्यवस्था के चार प्रमुख स्तंभ हैं और इन्हें मजबूत कर हम अर्थव्यवस्था को अभूतपूर्व गति दे सकते हैं। आज हमारा प्रदेश इन सभी क्षेत्रों में अग्रणी बनने की ओर अग्रसर है। राज्य सरकार द्वारा स्टार्टअप पॉलिसी, अटल इनोवेशन स्टूडियो एंड एक्सेलरेटर, एवीजीसी- एक्सआर पॉलिसी, सेंटर फॉर एडवांस्ड स्किलिंग, स्टेट स्किल पॉलिसी जैसे अनेक निर्णयों से युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खोले गए हैं।
>
> **– मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा**

स्वस्थ राजस्थान समर्थ राजस्थान

चिकित्सा पर सत्र

राजस्थान में हेल्थ एवं वेलनेस कैपिटल बनने की तमाम संभावनाएं एवं क्षमता मौजूद हैं। राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों के साथ ही प्रवासी राजस्थानियों का सहयोग इस सपने को जल्द साकार कर सकता है। सतत विकास लक्ष्य-3 एवं वर्ष 2030 तक यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज की दिशा में शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने की ओर राजस्थान तेजी से आगे बढ़ रहा है। सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों की स्थापना, मेडिकल टूरिज्म, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, वन हेल्थ रिसर्च सेंटर्स, फार्मा एवं मेडिकल डिवाइस मैन्यूफैक्चरिंग, एआई सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावनाएं राजस्थान में मौजूद हैं। प्रवासी राजस्थानी इन क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

मेडिकल कॉलेजों का विस्तार

प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार बेहतर नीति के साथ काम कर ही है। प्रदेश में निरंतर मेडिकल कॉलेजों का विस्तार हो रहा है। विगत दो वर्ष में 7 नए मेडिकल कॉलेज शुरू किए गए हैं और 15 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की दिशा में कार्य किया जा रहा है। दो वर्षों में करीब 2200 नई एमबीबीएस, पीजी और सुपर स्पेशलिटी कोर्स की सीटें बढ़ाई गई हैं। अब राजस्थान वन हेल्थ यानी मानव, पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य के एकीकृत दृष्टिकोण को लेकर आगे बढ़ रहा है।

जनकल्याणकारी स्वास्थ्य योजनाओं से सशक्त राजस्थान

राज्य सरकार ने हर व्यक्ति के इलाज खर्च की चिंता करते हुए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना प्रारंभ की, जिसमें 25 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिल रहा है। मा योजना के तहत 35 लाख लोगों को नि:शुल्क उपचार मिला है। नि:शुल्क जांच योजना में 30 करोड़ जांच कर 9 करोड़ मरीजों को राहत प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना के तहत 10 करोड़ 34 लाख रोगियों को नि:शुल्क दवाइयां उपलब्ध करवाई गई हैं। गंभीर बीमारियों की दवाएं पूरी तरह नि:शुल्क मिल रही हैं। मा वाउचर योजना के तहत 2 लाख 25 हजार गर्भवती महिलाओं की नि:शुल्क सोनोग्राफी की गई हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से आयुष पद्धति की 100 से अधिक देशों में पहुंच संभव हुई है। राजस्थान सरकार भी आयुष चिकित्सा प्रणालियों को बढ़ावा दे रही है। इस क्षेत्र में निवेशकों के लिए नए अवसर विकसित हो रहे हैं।

यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दिशा में मिसाल पेश कर रहा राजस्थान

राजस्थान का स्वास्थ्य मॉडल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दिशा में मिसाल पेश कर रहा है। आने वाले समय में राज्य में विश्वस्तरीय चिकित्सा संस्थानों की स्थापना के साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत किया जाएगा। राज्य सरकार की 'हील इन राजस्थान' नीति मेडिकल ट्यूरिज्म को आकर्षित करने की दिशा में बड़ा कदम है। गांव-गांव तक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए चिकित्सा संस्थानों को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के रूप में परिवर्तित किया गया है, जहां 12 प्रकार की सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं। टेलीमेडिसिन के माध्यम से गांव-ढाणी में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलना संभव हुई हैं।

मिशन मोड में दूर की मानव संसाधन की कमी

चिकित्सा क्षेत्र में मानव संसाधन की कमी दूर करने के लिए मिशन मोड में काम करते हुए 35 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की है। इनमें से 27 हजार से अधिक पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं एवं 15 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। मा योजना में प्रतिदिन करीब 10 हजार रोगियों को 10 करोड़ रुपए का उपचार निःशुल्क मिल रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में उच्च स्तरीय मानकों की दृष्टि से जयपुर में एम्स की तर्ज पर रिम्स की स्थापना की जा रही है।

क्रिटिकल माइनिंग के रूप में उभर रहा राजस्थान

माइनिंग पर सत्र

राजस्थान में खनन क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, साथ ही वह ऊर्जा और ताकत भी है, जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। राज्य में 82 प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं और 57 खनिजों का दोहन किया जा रहा है। खनन क्षेत्र प्रदेश के जीडीपी में 4.4 प्रतिशत का योगदान देता है और राज्य सरकार ने इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए खनिज नीति-2024 और एम-सैंड नीति-2024 लागू की है। प्रदेश में प्रधान खनिज के 112 ब्लॉक्स की नीलामी की जा चुकी है, जिससे राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। फ्लोराइट, एमराल्ड, गोल्ड, गारनेट, लेड-जिंक, आरईई और पोटाश जैसे खनिजों की पहली बार नीलामी की गई है।

बाड़मेर-सांचौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन में प्राकृतिक गैस का उत्पादन हो रहा है। साथ ही, राजस्थान रिफाइनरी परियोजना का 90 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में पेट्रोलियम विभाग के अंतर्गत 44 हज़ार 784 करोड़ रुपए के निवेश के लिए एमओयू हस्ताक्षर किए गए, जिनका धरातल पर कार्य प्रगति पर है। राजस्थान क्रिटिकल माइनिंग के मुख्य केन्द्र के रूप में उभर रहा है। रक्षा, ऊर्जा, कृषि, सोलर, ऑटोमोबाइल सहित विभिन्न क्षेत्रों में क्रिटिकल मिनरल्स की बढ़ती मांग को पूरा करने का सामर्थ्य राजस्थान में है।

जल संरक्षण से जल सुरक्षा तक हरित राजस्थान

सस्टेनेबल वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर पर सत्र

'प्रवासी राजस्थानी दिवस' 2025 मे जेईसीसी, जयपुर में "राजस्थान में सस्टेनेबल वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास : एक जिम्मेदारी और एक अवसर" विषय पर सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र में राजस्थान की जल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक, बड़े पैमाने पर लागू होने वाले और टेक्नोलॉजी-आधारित समाधानों पर चर्चा करने के लिए प्रमुख विशेषज्ञ और इंडस्ट्री के इनोवेटर एक साथ आए।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार पानी को प्राथमिकता देते हुए अलग-अलग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। राजस्थान के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की गई है, ताकि सिंचाई, उद्योग, पशुधन और घरेलू पानी की जरूरतें पूरी हो सकें। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जैसी बड़ी परियोजनाएं और पानी बचाने के पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल राजस्थान को एक हरा-भरा और ज्यादा सस्टेनेबल राज्य बना रहा है। आर.आर.आर. सिद्धांत 'रियूज, रिड्यूस और रीसायकल' में राजस्थान में बहुत ज्यादा संभावना है। इस सिद्धांत को व्यवहार में लाने के लिए प्रवासी राजस्थानियों के समर्थन की आवश्यकता है। ■

धर्म ध्वजा का आरोहण

ऋषिता मेहरा, स्वतंत्र लेखिका

विकसित भारत की यात्रा को गति देने के लिए ऐसा रथ चाहिए जिसके पहिये वीरता और धैर्य हों, जिसका ध्वज सत्य और परम आचरण हो, जिसके घोड़े शक्ति, विवेक, संयम और परोपकार हों, और जिसकी लगाम क्षमा, करुणा और समता हो।

– प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण तब जुड़ गया, जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर पवित्र भगवा धर्मध्वजा फहराई। यह अवसर न केवल मंदिर निर्माण की पूर्णता का प्रतीक बना, बल्कि भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण और राष्ट्रीय एकता के नए अध्याय की शुरुआत भी बना।

धर्म ध्वजा – सभ्यता का उद्घोष

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि यह भगवा ध्वज मात्र एक प्रतीक नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। केसरिया रंग, सूर्यवंश का प्रतीक, पवित्र 'ॐ' और कोविदार वृक्ष–ये सभी रामराज्य के आदर्शों, सत्य, धर्म और कर्तव्य की भावना को दर्शाते हैं। यह ध्वज संघर्ष से सिद्धि तक की यात्रा और सदियों पुराने संकल्प की परिणति का प्रतीक है।

सदियों की प्रतीक्षा का अंत

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज सदियों पुराने घाव भर रहे हैं और 500 वर्षों से प्रज्वलित आस्था का यज्ञ अपने पूर्णत्व को प्राप्त कर रहा है। रामभक्तों के हृदय में संतोष, कृतज्ञता और दिव्य आनंद का भाव है। राम मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि सत्य की विजय और धर्म की स्थापना का संदेशवाहक है।

सामूहिक शक्ति और सामाजिक समरसता

राम मंदिर परिसर को भारत की सामूहिक शक्ति का प्रतीक बताते हुए प्रधानमंत्री ने सप्त मंदिरों का उल्लेख किया, जिनमें माता शबरी, निषादराज,

महर्षि वाल्मीकि सहित अनेक महान विभूतियों के मंदिर शामिल हैं। जटायु और गिलहरी की मूर्तियां यह संदेश देती हैं कि बड़े संकल्पों की सिद्धि में हर छोटा प्रयास भी महत्त्वपूर्ण होता है।

राम भेद नहीं, भाव से जोड़ने वाला मूल्य

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि राम व्यक्ति नहीं, बल्कि मूल्य, मर्यादा और दिशा हैं। उनके लिए भक्ति वंश से बड़ी है और संस्कार शक्ति से अधिक मूल्यवान हैं। इसी भावना के साथ सरकार ने पिछले 11 वर्षों में समाज के हर वर्ग को विकास के केंद्र में रखा है, ताकि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य साकार हो सके।

विरासत पर गर्व और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति

श्री मोदी ने गुलामी की मानसिकता की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि भारतवासियों को अपनी जड़ों, परंपराओं और लोकतांत्रिक विरासत पर गर्व करना होगा। उन्होंने मैकाले की सोच को मानसिक गुलामी का कारण बताया और अगले दस वर्षों को इससे पूर्ण मुक्ति का दशक बनाने का आह्वान किया।

अयोध्या में फहराई गई धर्म ध्वजा केवल मंदिर के शिखर पर नहीं, बल्कि भारत की चेतना में प्रतिष्ठित हुई है। यह आस्था, संस्कृति, आत्मविश्वास और विकसित भारत के संकल्प का उद्घोष है–जो आने वाली सदियों तक राष्ट्र को सत्य, धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर प्रेरित करता रहेगा। ■

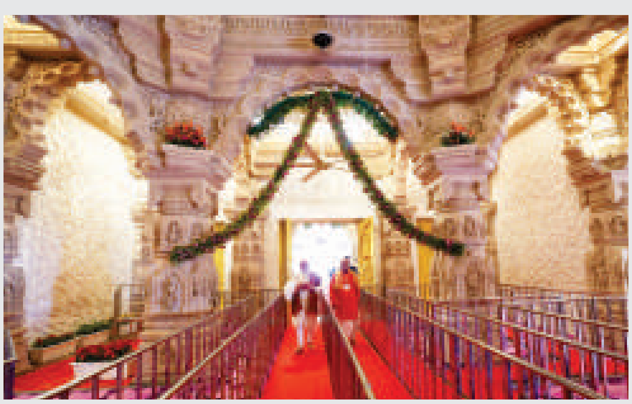

गौमाता की महिमा

शास्त्रीय संदर्भ एवं राजस्थान में गौसेवा के प्रयास

पंकज ओझा, निदेशक, गोपालन विभाग

भारतीय ज्ञान-परंपरा में गौ-माता को केवल उपयोगिता के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि धार्मिक, नैतिक, दार्शनिक, सामाजिक और चिकित्सकीय दृष्टि से सर्वोच्च स्थान प्राप्त है।

वेदों से लेकर श्रीमद्भागवत महापुराण, वाल्मीकि रामायण, भगवद्गीता, धर्मशास्त्र, नीतियोग ग्रंथ तथा आयुर्वेद तक गौ को लोकमाता, करुणा की प्राणप्रतिमा और जीवन-संरक्षण का आधार कहा गया है। ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है- "अघ्न्या या गौ:", अर्थात गाय ऐसी है, जिसका वध नहीं किया जाना चाहिए। यह वक्तव्य केवल करुणा या धर्म की दृष्टि से नहीं, बल्कि जीवनरक्षा के सार्वभौमिक सिद्धांत का प्रतीक है।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा स्वयं एक बहुत बड़े गौ-भक्त हैं। उनके द्वारा गौसेवा के क्षेत्र में अत्यंत विशिष्ट कार्य किए जा रहे हैं। गोपाष्टमी पर एवं 15 दिसम्बर, 2025 को राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने पर राज्य की संपूर्ण गौशालाओं में गौसेवा एवं गौपूजन के कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आयोजित किए गए एवं पिंजरापोल गौशाला, सांगानेर में गौसेवा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित कर गौसेवा एवं गौ-पूजन किया गया।

राज्य में गौ-संवर्धन एवं गौ-संरक्षण हेतु अनेक प्रयास किये जा रहे हैं। राजस्थान में सड़कों पर भटकते निराश्रित गौवंश को गौशाला में पहुंचाया गया, जिससे उनका एवं फसलों का संरक्षण हुआ एवं सड़कों पर दुर्घटनाओं में कमी आई।

गौशालाओं को दिसम्बर, 2025 तक 827.55 करोड़ रुपए का अनुदान वितरित किया गया है, नंदीशालाओं के लिए 16.55 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। वध से बचाये गये गौवंश को 0.19 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई है।

गौ सेवा और गौ संरक्षण की विशद परंपरा हमारी संस्कृति में अमिट रूप से दिखाई देती है, इस हेतु राजस्थान में मंदिरों के साथ गावों में औरण भूमि रखी जाती है एवं घर की पहली रोटी भी गौ माता को ही देने की परंपरा है। साथ ही राम राज्य के नीति दर्शन एवं राजत्व के तत्वों के साथ आयुर्वेद में पंचगव्य और औषधि विज्ञान तक यह परंपरा विस्तारित है। श्री कृष्ण भगवान के गोविंद, गोपाल, गोचारण, गोवर्धनधारी स्वरूप एवं गोपाष्टमी पर्व और बछ बारस आदि गौ संरक्षण के साथ धर्म के संरक्षण के ही परिचायक हैं।

श्रीमद् भागवत में गौ माता द्वारा धर्म के संरक्षण का भी वर्णन प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण का संपूर्ण बाल्य जीवन गोधन-पोषण के साथ जुड़ा है, जो "संपूर्ण सृष्टि के लोकसंग्रह" का व्यावहारिक रूपक है।

रामराज्ये न दु:खं कश्चित् पश्यति।
गावो न दु:खिता लोके ॥

अर्थ – श्रीराम के राज्य में न कोई मनुष्य दु:खी था, न कोई गौ पीड़ित। रामराज्य का अर्थ प्रशासनिक व्यवस्था से अधिक है यह ऐसी सामाजिक-सांस्कृतिक संरचना है, जिसमें गौ, ग्राम और धर्म एक-दूसरे के पूरक हैं।

राजा दशरथ प्रतिदिन गौ-दान और ब्राह्मण सेवा से सुराज्य का उदाहरण स्थापित करते हैं। यह आदर्श शासनमूल्य आज भी नीति-निर्माण का प्रेरणास्रोत है। भगवद्गीता में गौ-माता का दार्शनिक संकेत भगवद्गीता धर्म, विज्ञान और नीति का समन्वय करती है। भगवान श्रीकृष्ण "कर्मयोग" और "लोकसंग्रह" का जो सिद्धांत देते हैं, उसमें प्रकृति-चक्र और गौ-आधारित जीवन का अपूर्व समन्वय है।

अन्नाद्भवन्ति भूतानि, पर्जन्यादन्नसम्भव: ।
यज्ञाद्भवति पर्जन्यो, यज्ञ: कर्मसमुद्भव: ॥ (3.14)

अर्थ – अन्न से प्राणी बनते हैं, अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से, और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। यह यज्ञचक्र गौ के बिना अधूरा है, क्योंकि यज्ञ के लिए गौ-घृत और गौ-उत्पाद आवश्यक माने गए हैं। अत: गीता का कर्मयोग केवल आचार नहीं, बल्कि गौ-केन्द्रित लोककल्याण व्यवस्था का भी प्रतीक है।

अन्य संस्कृत ग्रंथों में

गौ-महिमा मनुस्मृति – "गाव: पवित्रं परमं।" गाय को परम पवित्र कहा गया है।

महाभारत (अनुशासन पर्व) – "न गवादधिकं दानं।" गौदान से बड़ा कोई दान नहीं।

गरुड़ पुराण – "यो गाम् रक्षति तं धर्म: रक्षति।" जो गो-रक्षा करता है, उसकी रक्षा धर्म स्वयं करता है।

नीतिग्रंथ – "गवां पूजनमात्मन: आशिषां हेतु:" गायों की पूजा करना मनुष्य के शुभफल का कारण है।

इन सभी ग्रंथों में गौ को केवल जीव के रूप में नहीं बल्कि धर्म, धन और दया के एकीकृत तत्त्व के रूप में देखा गया है। संस्कृत श्लोकों में गौ-माता की आध्यात्मिक अभिव्यक्ति –

गावो विश्वस्य मातर:, सर्वदेवमयी गौ: ॥

अर्थ – गौ में समस्त देवताओं का वास है, उसकी सेवा देवसेवा तुल्य है।

आयुर्वेद में गौ-माता का स्थान – आयुर्वेद ने गौ को जीवित औषधालय कहा है।

चरक संहिता – गौ-दूध को "ओजवर्धक, बलवर्धक रसायन" बताया गया है।

सुश्रुत संहिता – गोघृत को "स्मृति-वर्धक, घाव भरने वाला तथा मानसिक रोग नाशक" कहा गया है।

पंचगव्य चिकित्सा – गौ-दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर को सम्मिलित रूप से "पंचगव्य" कहा गया है। इनका सेवन और प्रयोग शोधन, रसायन, प्रतिरक्षा-वर्धन एवं मानसिक शांति में लाभकारी है। आयुष मंत्रालय एवं वैज्ञानिक अध्ययन (CSIR, CCRAS) ने भी पुष्टि की है कि इन पंचगव्य तत्वों में एंटी-टॉक्सिक, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एवं एण्टी-कैंसर गुण निहित हैं। यह सिद्ध करता है कि आयुर्वेद का गौ-विज्ञान आधुनिक चिकित्सा के अनुरूप है।

समकालीन नीति दृष्टिकोण (Policy Perspective)

आज की नीति व्यवस्था में गौ-संरक्षण का महत्व अधिक वैज्ञानिक रूप में प्रकट हुआ है। आधुनिक अनुसंधान यह सिद्ध कर चुके हैं कि गौ-आधारित कृषि और जैविक पद्धति से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होती है, मृदा की उर्वरता बढ़ती है, पर्यावरण संरक्षण संभव होता है और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित होती है। भारत सरकार की राष्ट्रीय गोकुल मिशन, पशुधन संवर्धन योजना, पंचगव्य अनुसंधान परियोजनाएं और जैविक खेती योजनाएं, इन सभी में यह दर्शन सक्रिय है कि "गौ-संरक्षण = सतत विकास"।

गौ-माता भारतीय धर्म, दर्शन, चिकित्सा और संस्कृति की केंद्रस्थ आत्मा हैं। श्रीमद्भागवत की करुणा, रामायण का राजधर्म, गीता का लोकसंग्रह और आयुर्वेद का विज्ञान ये सभी एक ही विषय पर अभिसरित होते हैं।

गौ ही भारतीय जीवन की नैतिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक जड़ है। अत: - गौ-रक्षा = धर्म-रक्षा, गौ-सेवा = मानवता-सेवा, गौ-पालन = राष्ट्र-सशक्तीकरण

राजस्थान में पाई जाने वाली गायों की प्रमुख नस्लें

1. **थारपारकर नस्ल** – रोग-प्रतिरोधक और अनुकूलनीय मानी जाने वाली यह नस्ल मरुस्थलीय जलवायु में आसानी से जीवित रहती है।
2. **राठी नस्ल** – राजस्थान की यह सर्वाधिक प्रसिद्ध दुग्धदायिनी नस्ल है, जिसे "राजस्थान की कामधेनु" भी कहा जाता है।
3. **कांकरेज नस्ल** – मजबूत शारीरिक बनावट, लंबे और मोड़दार सींग वाली यह राजस्थान की सबसे भारी देह वाली नस्लों में से एक है।
4. **गिर (रेंडा)** – लाल-भूरा या चित्तीदार रंग वाली यह गुजरात मूल की नस्ल, दक्षिण-पश्चिम राजस्थान में भी पाई जाती है।
5. **मालवी नस्ल** – यह मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से संबंधित नस्ल है। यह अधिकतर भारवाही कार्यों में उपयोगी मानी जाती है।
6. **नागौरी नस्ल** – गाय का दूध उत्पादन कम होता है, किंतु बैल कृषि कार्य के लिए श्रेष्ठ माने जाते हैं।
7. **हरियाणवी नस्ल** – यह दूध और श्रम-दोनों के दृष्टिकोण से उपयोगी है। इस नस्ल के बैल हल और बैलगाड़ी में प्रयोग किए जाते हैं।
8. **मेवाती (कोठी) नस्ल** – यह पुरानी देशी नस्ल मुख्यत: हल-जोताई और गाड़ी चलाने के कार्यों में प्रयुक्त होती है।
9. **सांचौरी नस्ल** – यह स्थानीय स्तर पर विकसित नस्ल है। सामान्य काया, संयमित स्वभाव और मध्यम दूध उत्पादन इसकी पहचान है। ■

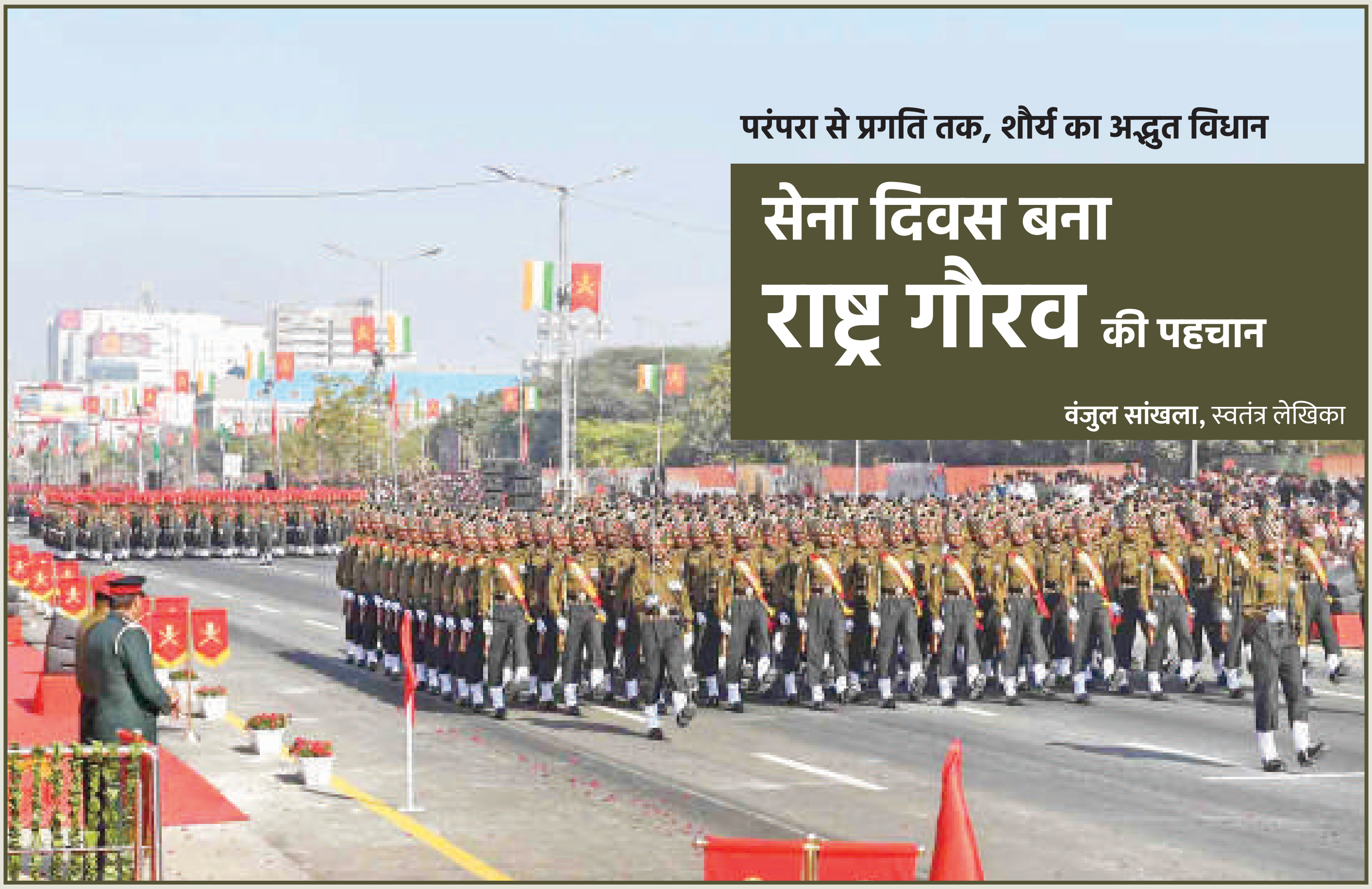

परंपरा से प्रगति तक, शौर्य का अद्भुत विधान

सेना दिवस बना राष्ट्र गौरव की पहचान

वंजुल सांखला, स्वतंत्र लेखिका

भारतीय सेना ने 78वां सेना दिवस जयपुर के जगतपुरा स्थित महल रोड पर पूरे सैन्य गौरव व अनुशासन के साथ मनाया। यह चौथी बार था, जब सेना दिवस परेड दिल्ली के बाहर आयोजित हुई और पहली बार किसी असैन्य क्षेत्र में आयोजित की गई। राजस्थान को पहली बार इस ऐतिहासिक आयोजन की मेजबानी का गौरव प्राप्त हुआ। सैन्य उत्कृष्टता, गौरवशाली परंपराओं और राष्ट्रीय गौरव के भव्य एवं ऐतिहासिक प्रदर्शन को देखने के लिए राज्यपाल श्री हरिभाऊ किसनराव बागडे, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, मिजोरम के राज्यपाल जनरल (रि.) वीके सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, सप्तशक्ति कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह सहित अनेक सैन्य व गणमान्य जन उपस्थित रहे।

स्वदेशी हथियारों और नई तकनीक का प्रदर्शन

थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। दक्षिण पश्चिम कमान के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हरविंदर सिंह ने भव्य परेड का नेतृत्व किया। सेना दिवस परेड में भारतीय सेना ने अपने शौर्य, साहस और अजेय शक्ति का प्रदर्शन किया। स्वदेशी सैन्य क्षमता, आधुनिक आयुध और उभरती तकनीक को देखकर विशिष्ट से लेकर आमजन तक कोई भी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। इस वर्ष की थीम **'भारतीय सेना-शौर्य और बलिदान'** रखी गई। परेड में परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र एवं वीर चक्र विजेता भी विशेष मेहमान के रूप में शामिल हुए। स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल, भीष्म एवं अर्जुन टैंक, के-9 वज्र तोप, बीएमपी वाहन, 155 एमएम अमोघ, नामिस (नाग मिसाइल सिस्टम), पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, शिल्का हथियार प्रणाली, ड्रोन शक्ति, ड्रोन जैमर तकनीक, इलेक्ट्रिक ऑल टैरेन व्हीकल का प्रदर्शन आकर्षण का विशेष केंद्र रहा। नव गठित भैरव बटालियन सहित भारतीय सेना की 7 रेजीमेंट की टुकड़ियों ने मार्च पास्ट किया।

"राजस्थान शौर्य, भक्ति और शक्ति की भूमि है। राजस्थान को वीर सपूतों के लिए जाना जाता है। राजस्थान की धरती मां भारती की रक्षा करने में सदा तत्पर रही है। हमें गर्व है कि हमारे वीर योद्धाओं ने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है।"

– मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा

अभिनव सैन्य प्रणालियों में रोबोटिक म्यूल, स्वाथी वेपन लोकेटिंग राडार, मॉड्युलर ब्रिजिंग सिस्टम, मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम, वाहन आधारित इन्फेंट्री मोर्टार सिस्टम, ड्रोन जैमर सिस्टम, मोबाइल कम्युनिकेशन नोड तथा अजय केतु ऑल-टेरेन व्हीकल जैसी अत्याधुनिक प्रणालियां प्रदर्शित की गईं।भारतीय सेना के विभिन्न बैंड्स के साथ-साथ नेपाल आर्मी बैंड की भागीदारी ने भारत-नेपाल के विशेष सैन्य संबंधों को रेखांकित किया।महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को रेखांकित करने के लिए गर्ल्स एनसीसी टुकड़ी ने भी मार्च पास्ट किया।

5 शूरवीरों को मरणोपरांत सेना मेडल

परेड से पहले ऑपरेशन 'सिंदूर' एवं अन्य अभियानों में अदम्य साहस और वीरता के लिए शूरवीरों सूबेदार मेजर पवन कुमार, हवलदार सुनील कुमार सिंह, लांस नायक दिनेश कुमार, लांस नायक सुभाष कुमार और लांस नायक प्रदीप कुमार को मरणोपरांत 'सेना मेडल (गैलेंट्री)' से सम्मानित किया गया। आत्मनिर्भर एवं नए भारत की तस्वीर पेश करती भारतीय सेना, राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और भरतपुर की फूलों की होली की रंग-बिरंगी झांकियां भी आयोजन में शामिल रहीं। राजस्थान के कच्छी घोड़ी, दंगल, गैर, कालबेलिया जैसे मनोहारी लोक नृत्यों ने सभी आम एवं खास मेहमानों का ध्यान खींचा।

तीन चेतक हेलीकॉप्टरों ने तिरंगा एवं संयुक्त सेनाध्वज के साथ पुष्प वर्षा कर और अपाचे सहित विभिन्न हैलीकॉप्टर्स ने एयरोहेड व अन्य फॉर्मेशन से परेड को भव्य रूप दिया। सेना सेवा कोर के टॉरनैडो के बाइक्स पर व पैराट्रूपर्स के आसमान में हैरतअंगेज करतबों और परेड के समापन पर नाल एयरबेस से आए तीन जगुआर लड़ाकू विमानों की गर्जना ने सभी को रोमांचित कर दिया। बड़ी संख्या में गणमान्य जन, नागरिक, वेटरन्स, युवा और छात्र-छात्राएं इस ऐतिहासिक आयोजन के साक्षी बने। ■

भारतीय सेना :
शौर्य और बलिदान की परंपरा
78th
ARMY DAY

स्वदेशी शान, आधुनिक विज्ञान अदम्य निष्ठा, सशक्त भारत की सेना महान

'Know Your Army' प्रदर्शनी

78वें सेना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किए गए कार्यक्रमों के अन्तर्गत भवानी निकेतन शिक्षा समिति परिसर में 'Know Your Army' प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में ब्रह्मोस, आकाश, मीडियम रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल, स्काई स्ट्राइक, क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल, टैंकर्स सहित भारतीय सेना के विभिन्न आधुनिक उपकरणों को प्रदर्शित किया गया। उल्लेखनीय है कि आज भारतीय सेना आधुनिक हथियारों, अत्याधुनिक तकनीक और विश्वस्तरीय प्रशिक्षण से सुसज्जित एक सशक्त सैन्य शक्ति है। लेकिन, इन सब से ऊपर है भारतीय सेना का अनुशासन, समर्पण और देश के प्रति अटूट निष्ठा। यही गुण भारतीय सेना को विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में शामिल करते हैं।

एरियल टारगेटिंग सिस्टम (स्काई स्ट्राइक)

स्काई स्ट्राइक उन्नत और मानव रहित हवाई प्रणाली है। इस यूएवी की लंबाई 2.3 मीटर और विंगस्पैन 3.2 मीटर है, जिससे यह संतुलित और स्थिर उड़ान भरने में सक्षम होता है। यह अधिकतम 15,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। वजन के अनुसार इसकी उड़ान क्षमता अलग-अलग है। 5 किलोग्राम संस्करण लगभग 2 घंटे तक और 10 किलोग्राम संस्करण लगभग

1 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। यह प्रणाली कठिन से कठिन मौसम में भी प्रभावी रूप से कार्य कर सकती है। स्काई स्ट्राइक +60 डिग्री सेल्सियस तक के उच्च तापमान और टेकऑफ के समय माइनस 20 डिग्री, तथा उड़ान के दौरान माइनस 60 डिग्री सेल्सियस तक के न्यूनतम तापमान को सहन करने में सक्षम है। इसकी अधिकतम गति 176 किलोमीटर प्रति घंटा है। हवा की सीमा के अनुसार यह यूएवी टेकऑफ के समय अधिकतम 25 नॉट्स, उड़ान के दौरान 30 नॉट्स तक की हवा में सुरक्षित रूप से कार्य कर सकता है।

ब्रह्मोस

ब्रह्मोस मिसाइल एक अत्याधुनिक सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है, जिसे तेज़ गति और लंबी दूरी तक लक्ष्य भेदने के लिए विकसित किया गया है। इसकी अधिकतम मारक दूरी लगभग 450 किलोमीटर है। इस मिसाइल का वजन करीब 3000 किलोग्राम है और यह मैक 3 की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है, यानी यह ध्वनि की गति से तीन गुना तेज़ चलती है। अपनी तेज़ गति के कारण दुश्मन के लिए इसे रोक पाना बेहद कठिन हो जाता है।

आकाश

आकाश मिसाइल प्रणाली भारत की एक स्वदेशी और प्रभावी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। यह प्रणाली टाट्रा 8×8 वाहन पर आधारित है, जो इसे मजबूत संचालन क्षमता देता है। इसका लांचर स्थानीय तथा दूरस्थ दोनों मोड में संचालित किया जा सकता है। इसकी प्रभावी मारक दूरी लगभग 25 किलोमीटर है और यह 2.5 मैक तक की गति से उड़ान भरने में सक्षम है। यह प्रणाली 18 किलोमीटर की ऊँचाई तक लक्ष्यों को भेद सकती है।

भविष्य का 'डिजिटल सिपाही' रोबोटिक म्यूल

प्रदर्शनी में चार पैरों वाले रोबोट की क्षमताओं को आमजन ने देखा यह दिखने में किसी मेटल डॉग जैसा लगता है, जो दुर्गम पहाड़ों, घने जंगलों या रेगिस्तान की तपती रेत और युद्ध के मैदान जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में सैनिकों का साथी बनता है। सैनिकों की सबसे बड़ी चुनौती उनके सामान का वजन और दुर्गम रास्ता होती है। लेकिन अब, भारतीय सेना में एक नया 'साथी' शामिल हो रहा है, जिसके न फेफड़े थकते हैं और न ही पैर डगमगाते हैं। इसे दुनिया (म्यूल) MULE (Multi-Utility Legged Equipment) के नाम से जानती है। यह एक स्वायत्त (autonomous) रोबोट है, जिसे विशेष रूप से उन जगहों पर काम करने के लिए बनाया गया है, जहां पहिये वाले वाहन नहीं जा सकते।

युद्ध के मैदान में इसकी भूमिका

रोबोटिक म्यूल सामान ढोने के साथ इसके मल्टी-यूटिलिटी फीचर्स इसे एक घातक हथियार भी बनाते हैं। इसमें लगे थर्मल कैमरे और सेंसर रात के अंधेरे में भी दुश्मन की हलचल को पकड़ सकते हैं। यह लैंडमाइंस और आईईडी (IED) का पता लगाने के लिए सैनिकों से आगे भेजा जा सकता है, जिससे इंसानी जान का जोखिम कम होता है। जरूरत पड़ने पर इन पर हल्की मशीनगन या मिसाइल लॉन्चर भी फिट किए जा सकते हैं। रोबोटिक म्यूल तकनीक और ताकत का वो मेल है, जो भविष्य के युद्धों में सैनिकों की जान बचाने और ऑपरेशन की सफलता सुनिश्चित करने में गेम-चेंजर साबित होगा।

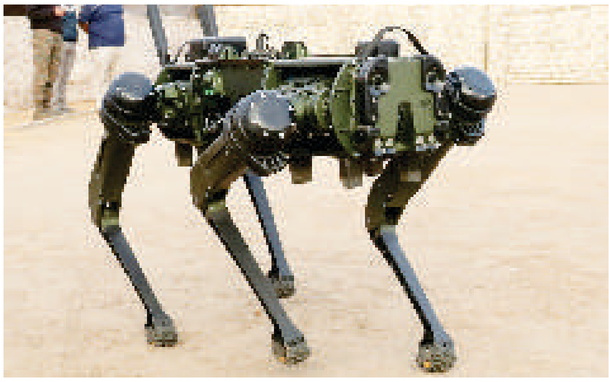

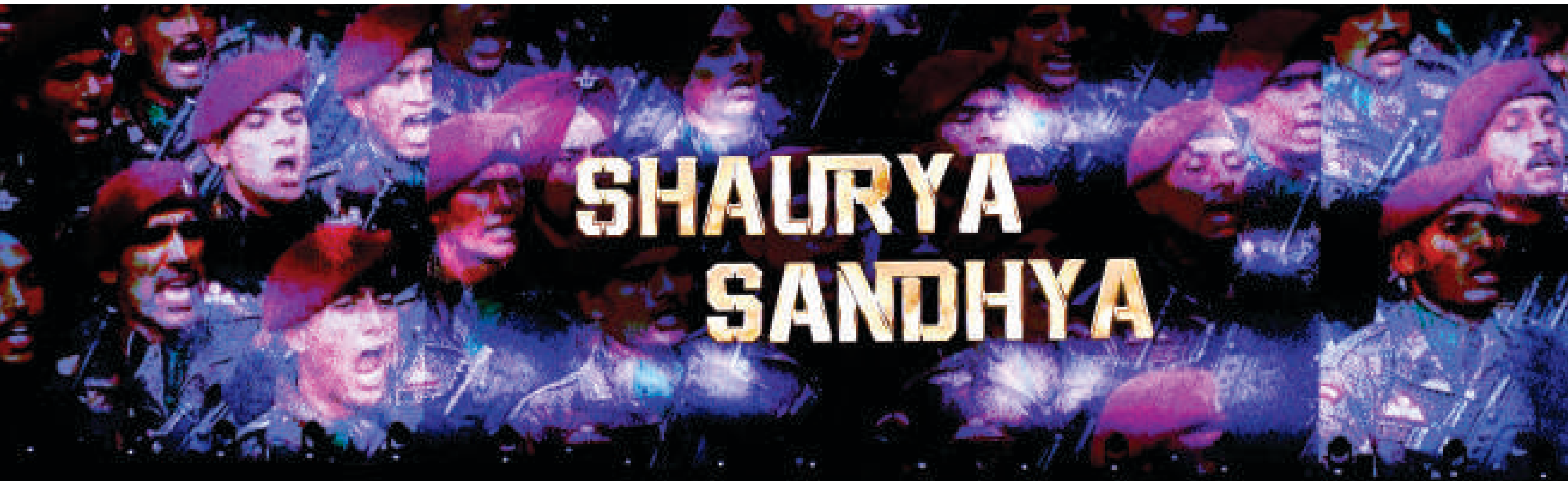

शौर्य संध्या

शौर्य, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति की उज्ज्वल गाथा

भारत की आत्मा उसकी सीमाओं पर तैनात उन वीर सपूतों में बसती है, जो निःस्वार्थ भाव से मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वस्व अर्पित कर देते हैं। भारतीय सेना केवल एक सैन्य शक्ति नहीं, बल्कि राष्ट्र की अस्मिता, स्वाभिमान और एकता की प्रहरी है। 78वें सेना दिवस के अवसर पर राजस्थान की वीर भूमि जयपुर में आयोजित शौर्य संध्या कार्यक्रम ने देश को एक बार फिर अपने सैनिकों के अदम्य साहस, त्याग और अनुशासन की गौरवगाथा से परिचित कराया। इस अवसर पर केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के विचारों ने राष्ट्रभक्ति, सैन्य परंपरा और भविष्य की सुरक्षा रणनीति को नई दिशा दी।

शौर्य और बलिदान की अमर भूमि

राजस्थान के कण-कण में वीरता की गाथाएं समाई हुई हैं। महाराणा प्रताप का पराक्रम, राणा सांगा का साहस, पन्नाधाय का त्याग, मीराबाई की भक्ति और भामाशाह का समर्पण—यह भूमि हर युग में राष्ट्र को प्रेरणा देती रही है। राजस्थान ने न केवल भारत की सैन्य परंपरा को आगे बढ़ाया है, बल्कि उसे शक्ति और गरिमा भी प्रदान की है। ऐसी शौर्य भूमि पर शौर्य संध्या का आयोजन वीर सैनिकों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है।

स्वाभिमान और स्वाधीनता का प्रतीक

15 जनवरी 1949 का दिन भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है, जब जनरल के.एम. करियप्पा ने स्वतंत्र भारत के पहले सेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। यह घटना औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक बनी। सेना दिवस केवल उत्सव नहीं, बल्कि संकल्प और आत्ममंथन का भी अवसर है।

ऑपरेशन सिंदूर – साहस और संतुलन का प्रतीक

अपने संबोधन में श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत की सैन्य क्षमता के साथ-साथ राष्ट्रीय स्वभाव का परिचायक बताया। यह अभियान केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं था, बल्कि सोच-समझकर, मानवीय मूल्यों के अनुरूप की गई निर्णायक कार्रवाई थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि आतंकवादी सोच के समाप्त होने तक शांति के लिए भारत का प्रयास जारी रहेगा।

राजस्थान और सेना का अटूट रिश्ता

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान शौर्य, भक्ति और शक्ति की भूमि है। यहां का हर घर सेना के प्रति समर्पण से भरा है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को भारत की ताकत का जीवंत उदाहरण बताते हुए कहा कि यह सेना दिवस परेड हमारी सैन्य विजय का उत्सव है। राज्य सरकार पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं के सम्मान व कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

शौर्य संध्या – गर्व और रोमांच का अद्भुत संगम

आर्मी डे परेड में ऑपरेशन 'सिंदूर' एवं अन्य सैन्य अभियानों में अदम्य साहस और वीरता का प्रदर्शन करने वाले सूबेदार मेजर पवन कुमार, हवलदार सुनील कुमार सिंह, लांस नायक दिनेश कुमार, लांस नायक सुभाष कुमार और लांस नायक प्रदीप कुमार को मरणोपरांत 'सेना मेडल (गैलेंट्री)' से सम्मानित किया गया। शौर्य संध्या कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने इन वीर शहीदों की वीरांगनाओं का सम्मान किया। भारतीय सेना-शौर्य एवं बलिदान की परंपरा की थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने स्पेशल कवर का भी अनावरण कर डिजिटल हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्री श्री सिंह ने प्रोजेक्ट नमन के तहत सूरतगढ़ में 100वें नमन सेंटर का भी वर्चुअल उद्घाटन किया। 78वें सेना दिवस के अवसर पर आयोजित शौर्य संध्या में भारतीय सेना की शौर्य गाथा ने दर्शकों को रोमांच और गर्व से अभिभूत कर दिया। कार्यक्रम में नेपाल सेना के बैंड, पैरामोटर फ्लाईपास्ट तथा कलरीपयट्टु और मल्लखंब की प्रभावशाली प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। वहीं, ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित प्रस्तुति भी कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रही। साथ ही, भव्य ड्रोन शो में राष्ट्रीय और ऐतिहासिक विषयों पर आधारित मनमोहक आकृतियों को भी लोग एकटक निहारते रहे। आकाश में सजीव आकृतियों के माध्यम से राष्ट्रगान की अद्भुत प्रस्तुति के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

शौर्य संध्या कार्यक्रम को देखने के लिए राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े, मिजोरम के राज्यपाल जनरल (रि.) वीके सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, सप्तशक्ति कमान के सेना कमाण्डर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह, विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी, उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी व डॉ. प्रेमचंद बैरवा, मंत्रिपरिषद के सदस्यगण, सांसद श्री मदन राठौड़, विधायकगण सहित भूतपूर्व सेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष, केन्द्र व राज्य सरकार के अधिकारीगण, भूतपूर्व सैनिक, वीर नारियों सहित बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। ■

भारतीय संविधान
ऐतिहासिक सांस्कृतिक चित्रण

सूर्य प्रताप सिंह राजावत,
मेंबर, एक्सपर्ट कमेटी, डिजिटल म्यूज़ियम राजस्थान विधानसभा

भारतीय संविधान, जो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, में अनूठी चित्रकलाएं शामिल हैं। इन चित्रों को प्रसिद्ध कलाकार नंदलाल बोस और उनकी टीम ने बनाया। ये चित्र भारत के इतिहास को दर्शाते हैं, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तक की झलक शामिल है। रामायण और महाभारत जैसे हिंदू महाकाव्यों के दृश्यों को भी चित्रित किया गया है। इन कलाकृतियों का उद्देश्य भारत की ऐतिहासिक यात्रा को रेखांकित करना था।

चित्रण की कलात्मक प्रक्रिया

नंदलाल बोस को अक्टूबर 1949 में इन चित्रों को बनाने की जिम्मेदारी दी गई। उनकी टीम में कृपाल सिंह शेखावत और ए. पेरुमल जैसे कलाकार शामिल थे। प्रत्येक कलाकार ने अपनी अनूठी शैली और दृष्टिकोण से योगदान दिया। चित्रों को संविधान के पाठ के पूरक के रूप में बनाया गया, लेकिन उनका सीधा संबंध संविधान की सामग्री से नहीं है।

भारतीय संविधान की चित्रकलाओं का विवरण

सिंधु घाटी सभ्यता – मोहनजो-दड़ो के महान स्नानागार को दर्शाता है, जो प्राचीन नगर नियोजन और संस्कृति का प्रतीक है।

गुरुकुल प्रणाली – वैदिक काल के गुरुकुल में शिक्षकों और शिष्यों को प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा प्राप्त करते हुए दिखाया गया है।

रामायण दृश्य – भगवान राम, सीता और लक्ष्मण को पुष्पक विमान में अयोध्या लौटते हुए चित्रित किया गया है।

महाभारत दृश्य – कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए दिखाया गया है।

गौतम बुद्ध – बोधगया में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करते हुए दिखाया गया है, जो बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों का प्रतीक है।

भगवान महावीर – ध्यान मुद्रा में महावीर स्वामी को दर्शाया गया है, जो अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों का प्रतीक है।

भाग ७

सम्राट अशोक – सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है, जो शांति और धर्म के प्रसार को दर्शाता है।

भाग ८

गुप्त काल की कला – हनुमान जी के एक दृश्य के माध्यम से गुप्त काल की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाया गया है।

भाग ९

विक्रमादित्य का दरबार – राजा विक्रमादित्य को सिंहासन बत्तीसी पर विराजमान दिखाया गया है।

भाग १०

नालंदा विश्वविद्यालय – प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की मुहर और दृश्य को प्रदर्शित किया गया है, जो उच्च शिक्षा के स्तर को दर्शाता है।

राजा भरत – राजा भरत को एक घोड़े के साथ दिखाया गया है, जो भारत के नामकरण का प्रतीक है।

नटराज प्रतिमा – भगवान शिव के तांडव नृत्य को दर्शाया गया है, जो सृष्टि, पालन और संहार के चक्र का प्रतीक है।

भगीरथ की तपस्या – राजा भगीरथ की तपस्या को दर्शाया गया है, जिसके फलस्वरूप गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ।

छत्रपति शिवाजी और गुरु गोबिंद सिंह – मराठा शासक छत्रपति शिवाजी और सिखों के दसवें गुरु, गुरु गोबिंद सिंह को दर्शाया गया है।

भाग १६

रानी लक्ष्मीबाई और टीपू सुल्तान – स्वतंत्रता संग्राम के वीरों, रानी लक्ष्मीबाई और टीपू सुल्तान को दर्शाया गया है।

भाग १७

महात्मा गांधी – डांडी मार्च को चित्रित किया गया है।

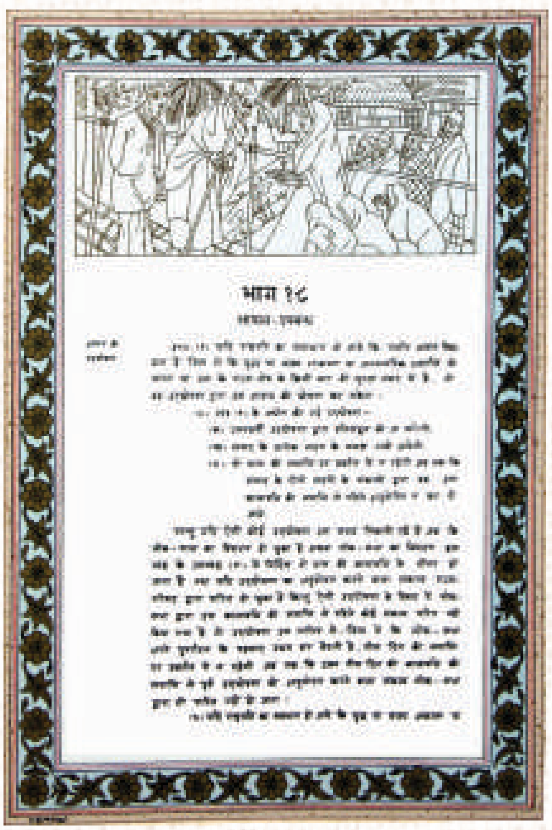
भाग १८

नोआखाली में गांधीजी – महात्मा गांधी को नोआखाली के दंगा पीड़ितों के बीच दिखाया गया है, जो अहिंसा और शांति के संदेश को दर्शाता है।

भाग १९

नेताजी सुभाष चंद्र बोस – नेताजी को आजाद हिंद फौज के साथ दिखाया गया है।

हिमालय का दृश्य – हिमालयी पर्वत श्रृंखला को दर्शाया गया है, जो भारत की भौगोलिक विविधता का प्रतीक है।

रेगिस्तान का दृश्य – थार मरुस्थल को चित्रित किया गया है, जो देश की भौगोलिक विविधता को दर्शाता है।

समुद्र का दृश्य – हिंद महासागर को प्रदर्शित किया गया है, जो भारत की समुद्री सीमाओं और समुद्री संपदा का प्रतीक है।

वर्ष 1976 में अपनाए गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्त्तव्यों को सूचीबद्ध किया गया है।

मौलिक कर्त्तव्यों की सूची

1. संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें।
2. स्वतंत्रता के लिये हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें।
3. भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण रखें।
4. देश की रक्षा करें और आह्वान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करें।
5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा व प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं।
6. हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें।
7. प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव आते हैं, की रक्षा और संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के लिये दया भाव रखें।
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें।
9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें।
10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू लें।
11. यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य के लिये शिक्षा के अवसर प्रदान करे।(इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा गया)।

मौलिक कर्त्तव्यों के 50 वर्ष पूर्ण

सुशासन दिवस – 25 दिसम्बर

सुशासन के पथ पर अटल भारत

अध्यात्म से आधुनिक लोकतांत्रिक आदर्शों की यात्रा

अमन हरसाना, स्वतंत्र लेखक

सुशासन का अर्थ एक मजबूत, लोकतांत्रिक, समावेशी राष्ट्र में निहित है। यह केवल कुशल प्रशासन के बारे में नहीं है, बल्कि सत्ता के नैतिक प्रयोग, निर्णय लेने में पारदर्शिता और सरकारी संस्थाओं द्वारा नागरिकों की जरूरतों के प्रति जवाबदेही के बारे में है। सुशासन की इसी अवधारणा को जीवित करने का काम भारत रत्न श्री अटल विहारी वाजपेयी ने किया है। उनकी इसी सोच को महत्व देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अटल जी की जयंती पर वर्ष 2014 से देश में हर साल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाने की घोषणा की, जो जन-केंद्रित, पारदर्शी और प्रभावी प्रशासन के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह दिन शासन को अहम् (मैं) से वयम् (हम) में बदलने के लिए एक अनुस्मारक और संकल्प दोनों के रूप में कार्य करता है। 'विकसित भारत@2047' के लक्ष्य की ओर अग्रसर भारत के लिए सुशासन न्यायपूर्ण और समावेशी विकास का मूल मंत्र है।

भविष्य के भारत के परिकल्पना पुरुष

अटल बिहारी वाजपेयी (1924-2018) ने तीन बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। ग्वालियर के एक साधारण परिवार से निकल कर भारत के सर्वोच्च पद तक पहुंचने वाले अटलजी को राष्ट्र के प्रति उनकी नि:स्वार्थ सेवा के लिए 1992 में पद्म विभूषण से व 2015 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भारत रत्न से सुशोभित किया गया। साथ ही, उन्हें वर्ष 1994 में भारत का 'सर्वश्रेष्ठ सांसद' भी चुना गया।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लोकतांत्रिक आदर्शों, महिला सशक्तीकरण और सामाजिक समानता का मुखर समर्थन किया। उन्होंने सदैव ही पारदर्शिता, जवाबदेही, सर्वसम्मति निर्माण और राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया। चाहे वह लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करना हो, बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता देना हो या समावेशी विकास को आगे बढ़ाना हो, उनकी शासन शैली दृढ़ता और सहानुभूति के बीच संतुलन को दर्शाती है। अटल जी का मानना था कि शासन को समाज के अंतिम नागरिक तक पहुंचना चाहिए व उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में सुधार करना चाहिए, न कि नीतिगत दस्तावेजों तक सीमित रहना चाहिए।

सुशासन का विकास – धर्मग्रंथों से लोक कल्याण तक

भारत में "सुशासन" की अवधारणा की जड़ें श्रीमद् भगवदगीता, रामायण, महाभारत, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, महात्मा गांधी के विचारों और भारत के संविधान की प्रस्तावना में देखी जा सकती हैं। रामायण "राम राज्य" का आदर्श प्रस्तुत करता है, जो न्याय, निष्पक्षता और सभी के कल्याण का प्रतीक है। महाभारत "राज धर्म" पर प्रकाश डालता है, जहां शासक का सबसे महत्त्वपूर्ण कर्तव्य प्रजा की भलाई है। वही कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रशासन,

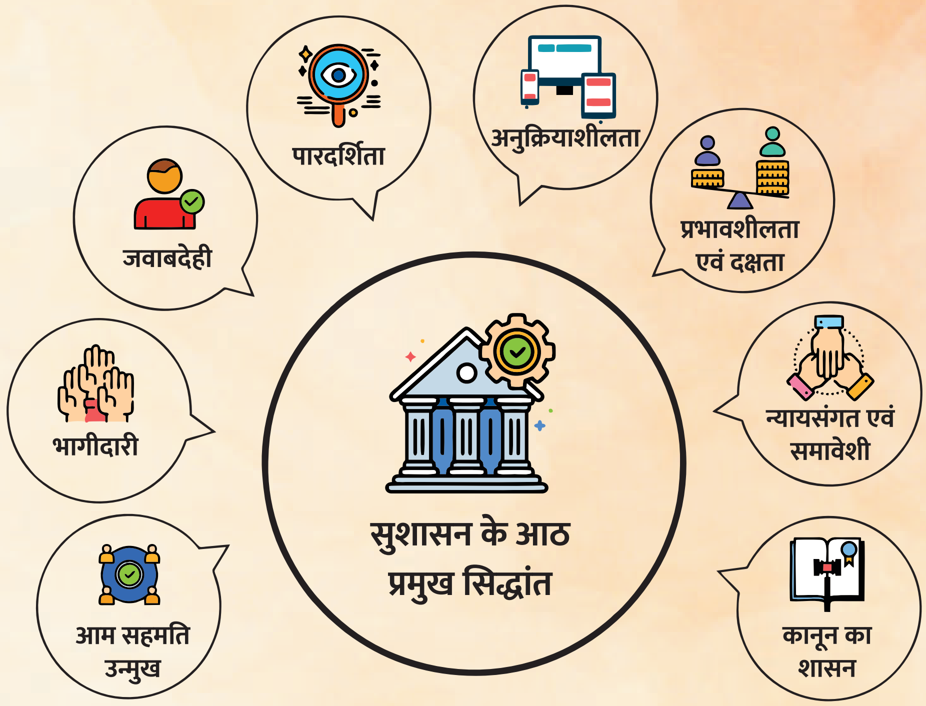

जवाबदेही, आर्थिक प्रबंधन और सार्वजनिक कल्याण के लिए एक व्यवस्थित रूपरेखा प्रदान करता है। "प्रजा की खुशी में ही राजा की खुशी है, उनके कल्याण में ही उसका कल्याण है"।

महात्मा गांधी ने भारत के लिए "राम राज्य" की अवधारणा की वकालत की, जो "सुशासन" के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसका उद्देश्य भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में बदलना है, जहां दबे-कुचले लोगों की ज़रूरतें पूर्ण हो, आम आदमी का कल्याण हो और स्वदेशी उद्योगों के माध्यम से उनकी प्रगति सुनिश्चित हो। 26 नवम्बर, 1949 में अपनाया गया भारतीय संविधान, संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित संवैधानिक शासन के लिए ढांचा स्थापित करता है। यह मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, कानून का शासन, स्वतंत्र न्यायपालिका, लोकतांत्रिक जवाबदेही और संस्थागत वास्तुकला प्रदान करता है।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य में सुशासन

सुशासन की अवधारणा 1990 के दशक में उस समय लोकप्रिय हुई, जब वर्ल्ड बैंक ने अपनी दो रिपोर्ट प्रकाशित कीं, पहली रिपोर्ट "सब - सहारन अफ्रीका : फ्रॉम क्राइसिस टू सस्टेनेबल ग्रोथ"(1989) में, 'शासन' शब्द का पहली बार उप-सहारा देशों में संस्थागत सुधार और अधिक कुशल सार्वजनिक क्षेत्र की आवश्यकता का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया गया तथा शासन को "किसी राष्ट्र के मामलों के प्रबंधन के लिए राजनीतिक शक्ति का प्रयोग" के रूप में परिभाषित किया गया।

वहीं 1992 में वर्ल्ड बैंक ने अपनी दूसरी रिपोर्ट "गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट" में शासन को "वह तरीका जिससे किसी देश के आर्थिक और सामाजिक संसाधनों के विकास के प्रबंधन में शक्ति का प्रयोग किया जाता है" के रूप में परिभाषित किया।

वहीं यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम (UNDP) ने 1997 में शासन को "किसी देश के सभी स्तरों पर मामलों के प्रबंधन हेतु आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक प्राधिकार के प्रयोग और राज्यों द्वारा सामाजिक सामंजस्य, एकीकरण को बढ़ावा देने व अपनी जनसंख्या के कल्याण को सुनिश्चित करने के साधनों" के रूप में परिभाषित किया। इसमें वे तंत्र, प्रक्रियाएं और संस्थाएं शामिल हैं, जिनके माध्यम से नागरिक और समूह अपने हितों को व्यक्त करते हैं, अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग करते हैं, अपने दायित्वों को पूरा करते हैं और अपने मतभेदों का समाधान करते हैं।

सुशासन के आठ प्रमुख सिद्धांत

संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त रूपरेखाओं के अनुसार, सुशासन आठ सिद्धांतों पर आधारित है –

1. **भागीदारी (पार्टिसिपेशन)**

   भागीदारी यह सुनिश्चित करती है कि निर्णय लेने में नागरिकों को सीधे या प्रतिनिधि संस्थानों के माध्यम से अपनी बात कहने का अधिकार है। भारत में, चुनावों, पंचायती राज संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों, सामाजिक लेखापरीक्षा (Social Audit) और MyGov जैसे डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से भागीदारी को मजबूत किया जाता है।

2. **कानून का शासन (रूल ऑफ़ लॉ)**

   सुशासन के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका, कानूनों की समान सुरक्षा और मानवाधिकारों का सम्मान अति महत्त्वपूर्ण हैं। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसे नए आपराधिक कानून औपनिवेशिक कानूनों को प्रतिस्थापित कर नागरिक केंद्रित न्याय प्रणाली को सुदृढ़ करते हैं।

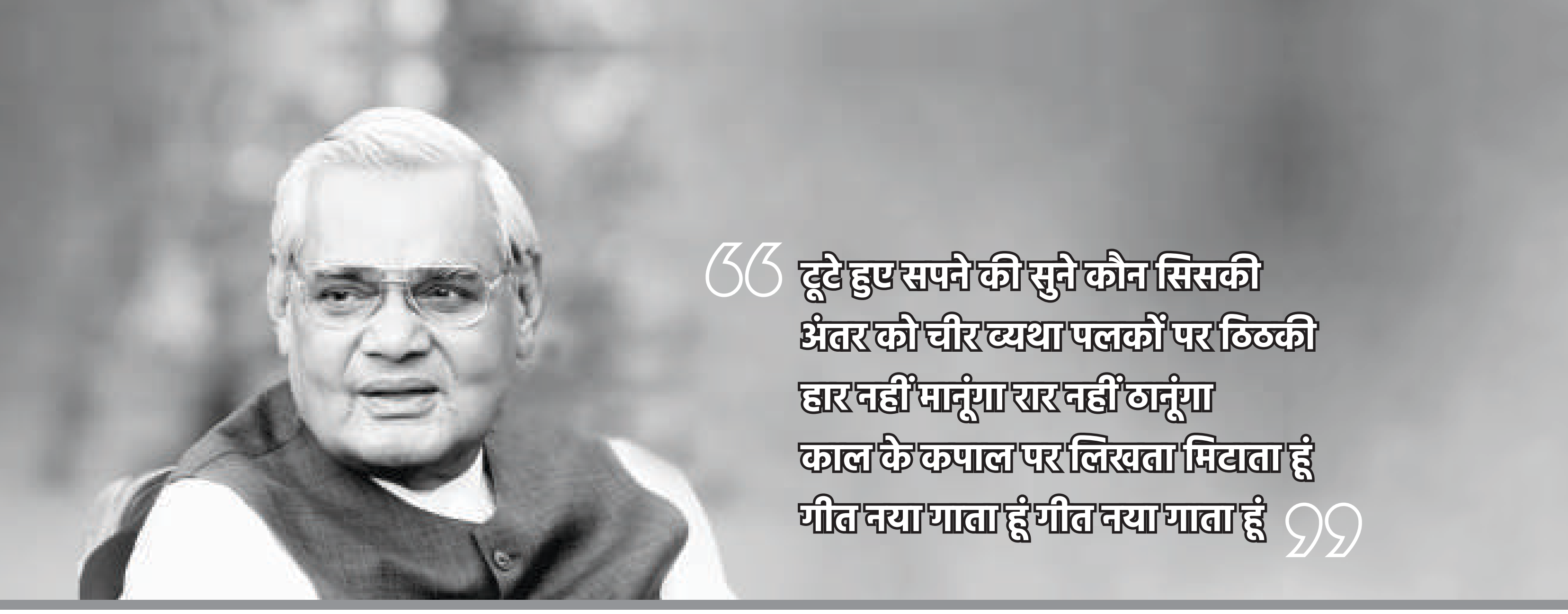

3. **पारदर्शिता (ट्रांसपेरेंसी)**

   पारदर्शिता का अर्थ है शासन प्रक्रियाओं में खुलापन और सूचना तक सुलभ पहुंच। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है। यह शासकीय कार्यों में पारदर्शिता को बढ़ावा देने, उत्तरदायित्व का सुदृढ़ीकरण करने और लोक संस्थानों में सुशासन की अवधारणा को सुनियोजित करता है।

4. **अनुक्रियाशीलता (रिस्पॉन्सिवनेस)**

   संस्थानों को उचित समय सीमा के भीतर नागरिकों की सेवा करनी चाहिए। ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन शिकायत निवारण और समयबद्ध सेवा वितरण जैसी पहलों का उद्देश्य प्रशासन को अधिक उत्तरदायी और कुशल बनाना है।

5. **आम सहमति उन्मुख (कंसेंसस ओरिएंटेड)**

   सुशासन का यह सिद्धांत समावेशी निर्णय लेने, संवाद और संघर्ष समाधान के माध्यम से समाज में विभाजन को कम करने व दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा देने पर जोर देता है। भारत की संसदीय प्रणाली, सहकारी संघवाद और परामर्शी नीति प्रक्रियाएं इस सिद्धांत को दर्शाती हैं।

6. **न्यायसंगत एवं समावेशी (इक्विटेबल और इनक्लूसिव)**

   किसी समाज की भलाई इस बात पर निर्भर करती है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि उसके सभी सदस्यों का समाज में हिस्सा है और वे समाज की मुख्यधारा से खुद को अलग-थलग महसूस न करें। इसके लिए सभी समूहों को, लेकिन खासकर सबसे कमज़ोर समूहों को, अपनी भलाई को बेहतर बनाने या बनाए रखने के अवसर मिलने चाहिए। भारत का संविधान अनुच्छेद 14 से 18 के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को समानता का मौलिक अधिकार सुनिश्चित करता है।

7. **प्रभावशीलता एवं दक्षता (इफेक्टिव और एफिशिएंट)**

   सार्वजनिक संस्थानों को संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए परिणाम देने चाहिए। जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का सतत् इस्तेमाल व पर्यावरण की सुरक्षा भी शामिल है।

8. **जवाबदेही (अकाउंटेबिलिटी)**

   जवाबदेही अच्छे शासन की एक ज़रूरी शर्त है, न सिर्फ सरकारी संस्थाएं बल्कि प्राइवेट सेक्टर और सिविल सोसाइटी संगठनों को भी जनता और अपने संस्थागत स्टेकहोल्डर्स के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। कौन किसके प्रति जवाबदेह है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि लिए गए फैसले किसी संस्था के अंदरूनी हैं या बाहरी। आम तौर पर, कोई संगठन संस्था उन लोगों के प्रति जवाबदेह होती है, जो उसके फैसलों से प्रभावित होंगे। संसदीय निरीक्षण, न्यायिक समीक्षा, स्वतंत्र संस्थानों और सक्रिय मीडिया के माध्यम से जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकती है।

सुशासन का मापन : गुड गवर्नेंस इंडेक्स

देश में सुशासन को मापने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और पब्लिक ग्रीवांस डिपार्टमेंट (DARPG) ने 25 दिसंबर, 2019 को गुड गवर्नेंस इंडेक्स पेश किया। इसका मकसद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गवर्नेंस परफॉर्मेंस को जांचना और सुधार को बढ़ावा देना है। इंडेक्स में कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र, वाणिज्य और उद्योग, मानव संसाधन का विकास, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और सेवाएं, आर्थिक शासन, सामाजिक कल्याण और विकास, न्यायपालिका और जन सुरक्षा, पर्यावरण और नागरिक केंद्रित शासन जैसे 10 महत्त्वपूर्ण सेक्टर के 58 इंडिकेटर्स के आधार पर मापा जाता है, जिन्हें नागरिकों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। नवीनतम 2020-21 इंडेक्स के अनुसार राजस्थान ने बी-श्रेणी के राज्यों के अंतर्गत द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

सुशासन दिवस केवल एक औपचारिक समारोह नहीं है, यह भारत के सभ्यतागत लोकाचार और संवैधानिक प्रतिबद्धता की पुन: पुष्टि है। प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से लेकर संविधान के लोकतांत्रिक आदर्शों और अटलजी के दूरदर्शी नेतृत्व तक, भारत की शासन यात्रा निरंतर सुधार और लचीलेपन को दर्शाती है। जैसे-जैसे भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, सुशासन वह निर्णायक कारक बना रहेगा, जो लोगों की आकांक्षाओं के साथ नीतिगत मंशा को जोड़ता है। सुशासन को मजबूत करना केवल प्रशासन में सुधार के बारे में नहीं है, बल्कि राज्य और उसके नागरिकों के बीच विश्वास को बढ़ावा देते हुए, यह सुनिश्चित करना है कि लोकतंत्र सभी के लिए सम्मान, न्याय और अवसर प्रदान करता है।

देशवासियों के हृदय में बसे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी जयंती पर सादर नमन। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सुशासन और राष्ट्र निर्माण को समर्पित कर दिया। वे एक प्रखर वक्ता के साथ-साथ ओजस्वी कवि के रूप में भी सदैव स्मरणीय रहेंगे। उनका व्यक्तित्व, कृतित्व और नेतृत्व देश के चहुंमुखी विकास के लिए पथ-प्रदर्शक बना रहेगा।

– **श्री नरेन्द्र मोदी**, प्रधानमंत्री

भारत रत्न, पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल जी का जीवन, उनके विचार और उनका आचरण इस बात का सशक्त प्रमाण है कि शासन का उद्देश्य सत्ता का उपभोग नहीं, अपितु लोक कल्याण और समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय एवं विकास का प्रकाश पहुंचाना होना चाहिए। उनके आदर्शों और विचारों को आत्मसात करते हुए हमारी सरकार सुशासन, पारदर्शिता और जनकल्याण के पथ पर निरंतर अग्रसर है।

– **श्री भजनलाल शर्मा**, मुख्यमंत्री

अटल युग – राष्ट्र निर्माण का स्वर्णिम अध्याय

- 4 अक्टूबर 1977 को देश के तत्कालीन विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देकर इतिहास रच दिया था। यह पहला अवसर था, जब किसी भारतीय नेता ने यूएन में हिंदी में संबोधन किया।
- अटल जी के नेतृत्व में, भारत ने 11 से 13 मई, 1998 के बीच पोकरण में दूसरी बार पांच परमाणु परीक्षण किए, जिसे 'ऑपरेशन शक्ति' नाम दिया गया। ये परीक्षण भारत के इतिहास में एक निर्णायक क्षण थे, जिन्होंने भारत को परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया। पोकरण में मिली इस सफलता के बाद से 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता हैं। उल्लेखनीय है कि 18 मई 1974 को पोकरण में पहली बार परमाणु विस्फोट किया गया, जिसे स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था।
- 14 जुलाई 1999 को अटल जी द्वारा ऑपरेशन विजय के तहत कारगिल युद्ध में भारत की पाकिस्तान पर जीत की घोषणा भारतीय सेना के शौर्य के साथ-साथ उनके कुशल कूटनीतिक नेतृत्व का भी उद्धरण है।
- अटल जी ने 1999 में नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी के जरिये सरकार के एकाधिकार को खत्म करते हुए टेलीकॉम सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल दिया। इस पॉलिसी से बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट आया, सर्विस की क्वालिटी बेहतर हुई और पूरे देश में टेलीकॉम कनेक्टिविटी का विस्तार हुआ, जिससे लाखों लोगों के लिए कम्युनिकेशन सस्ता और आसान हो गया।
- दूर-दराज की ग्रामीण बस्तियों के साथ प्रत्येक मौसम में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए अटल जी ने 25 दिसंबर 2000 देश की सबसे प्रभावशाली ग्रामीण अवसंरचना पहलों में से एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) कार्यक्रम की शुरुआत की, जो कि आज कृषि विकास, रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करते हुए गरीबी उन्मूलन का प्रमुख साधन बनकर उभरी है।
- अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2000-2001 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की, जिसने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया। इस अभियान के अंतर्गत खास ज़रूरतों वाले बच्चों को शिक्षा देने के साथ-साथ लड़कियों की शिक्षा पर भी ज़ोर दिया गया। अभियान को लोकप्रिय बनाने का काम दूरदर्शन पर आने वाले 'स्कूल चले हम' गाने ने किया। इस लोकप्रिय विज्ञापन के पीछे अटलजी का ही विज़न था।

- अटल जी द्वारा 2001 में शुरू किए गए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट ने देश के चार महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ते हुए 5,846 किलोमीटर का एक विशाल नेटवर्क खड़ा किया, जिसने ट्रांसपोर्टेशन को बदलते हुए कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ाया। इस प्रोजेक्ट के जरिये देश ने अटल जी की दूरदर्शी सोच और एग्जीक्यूशन की ताकत देखी। यह प्रोजेक्ट आज भारत के विकास का एक स्तंभ बन गया है।
- चंद्रयान-1 मिशन की घोषणा 15 अगस्त, 2003 को अटल जी ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के एक लक्ष्य के तौर पर की थी।
- अटल जी ने अपने कार्यकाल में भारत की जीडीपी को आठ प्रतिशत तक बढ़ाने के अलावा राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम भी पेश किया, जिसका उद्देश्य राजकोषीय घाटे को कम करना और सार्वजनिक क्षेत्र की बचत को बढ़ावा देना था।
- इन प्रयासों से उन्होंने ना सिर्फ आर्थिक प्रगति को नई शक्ति दी, बल्कि दूर-दराज के क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़कर भारत की एकता को भी सशक्त किया। ■

स्वीकारें कोटि-कोटि वन्दन....

हे गिरिराज गोवर्द्धन !

रामानंद राठी, सम्पादक, हिन्दी बुनियाद (राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी)

ब्रज अंचल के पहाड़ और वन-उपवन राजस्थान के भूगोल एवं संस्कृति में विशिष्ट महत्व रखते हैं। इतिहास के विभिन्न कालखण्डों में ब्रज की महान संस्कृति ने भारतीय धर्म, कला, साहित्य और लोक जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। राजस्थान के पूर्वी छोर पर स्थित ब्रज-मंडल श्री राधाकृष्ण की लीला-भूमि होने के कारण सम्पूर्ण विश्व की आस्था का केन्द्र है, जिसका बहुत भावनापूर्ण, मार्मिक चित्रण संस्कृत के पौराणिक ग्रन्थों के साथ-साथ आधुनिक भारतीय साहित्य में भी पढ़ने को मिलता है।

हिन्दी भाषा के मूर्धन्य उपन्यासकार श्री अमृतलाल नागर द्वारा, महाकवि सूरदास के जीवन पर लिखित उपन्यास "खंजन नयन" में ब्रज के अचल गौरव, गोवर्द्धन गिरिराज का उल्लेख कुछ इस तरह किया गया है- "हे पर्वतेन्द्र गोवर्द्धन, आप भक्तों के लिए नगाधिराज हिमालय से भी अधिक उन्नत और पूज्य हैं। आपके चारों ओर भगवान श्रीकृष्ण की लीला भूमियों का भाव-भरा इतिहास भगवदीय दृष्टि के लिए सदा प्रत्यक्ष है। हे गिरिराज, आप गोप-गोपियों और गोविन्द के लिए स्वर्ग से भी अधिक रमणीय हैं। दिन भर और बार-बार आपकी परिक्रमाएं करके भी सन्तों का मन नहीं अघाता। हे पाप पुंजहारी गोवर्द्धन, मैं आपको तथा गोवर्द्धनधारी गोपाल को बारम्बार प्रणाम करता हूँ।"

गोस्वामी तुलसीदास के छोटे भ्राता नन्ददास भी श्रीकृष्ण के अष्टसखाओं में गिने जाते हैं। नागर जी के उक्त उपन्यास में एक जगह वे अपने सह-कीर्तनकार, पितृवत् बाबा सूरदास से संवाद करते हैं-

"रघुनाथ जी के ब्याह में गोकुल नाँय जाओगे बाबा?"

"अब नब्बे-एक इक्कानबे वर्षों की आयु हुई पुत्र, गिरिराज की परिक्रमा ही करता रहूं, मन्दिर की सीढ़ियों पर चढ़ने की शक्ति बनी रहे, यही बहुत है।"

ब्रज चौरासी स्थित श्री गोवर्द्धन गिरिराज की सपरिवार दण्डवत परिक्रमा करते हुए – मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा बचपन से ही अपने माता-पिता के साथ गिरिराज धरण की नियमित परिक्रमा करते रहे हैं। मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के पश्चात् आप के द्वारा गोवर्द्धन गिरिराज सहित ब्रजमंडल के सम्पूर्ण स्थलों के संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु विशेष निर्देश भी जारी किए गए हैं, क्योंकि ये हमारी प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर हैं। आज से पांच सौ वर्ष पूर्व, मुगलकाल के दौरान, गिरिराज पर्वत के शिखर पर महाप्रभु वल्लभाचार्य जी द्वारा प्रकट किए गए श्रीनाथजी के पूर्ण स्वरूप एवं प्राकट्य मन्दिर की अष्टयाम पूजा-अर्चना उनके आठ परमभक्त सेवियों अर्थात् अष्टसखाओं द्वारा की जाती थी। ये सभी आठों श्रीकृष्णसखा ब्रजभाषा एवं हिन्दी की परम्परा के महान कवि एवं संगीतकार माने जाते हैं। इनमें शामिल हैं – कुम्भनदास, सूरदास, कृष्णदास, परमानन्ददास, गोविन्दस्वामी, छीतस्वामी, नन्ददास एवं चतुर्भुजदास।

सोलहवीं सदी के इन मध्यकालीन भक्त-कवियों में, जिन्हें महाप्रभु के सुपुत्र विट्ठलनाथ जी ने अष्टछाप कीर्तनकारों के रूप में संगठित किया, राजस्थान से एकमात्र श्री गोविन्दस्वामी ही शामिल हैं,जिनका जन्म भरतपुर जिले के अटारी गांव में हुआ था। उल्लेखनीय है कि श्री भजनलाल शर्मा इन्हीं महान कृष्णभक्त श्री गोविन्दस्वामी के वंशज हैं।

पुष्टिमार्गीय लिखित साहित्य तथा लोकश्रुति में अष्टसखा गोविन्दस्वामी के पांच सौ से अधिक पद प्राप्त होते हैं, जिनमें श्री राधा-कृष्ण की लीलाओं व ब्रजमंडल के नदी, पर्वतों, वन-उपवनों का अद्भुत वर्णन है। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु रहे श्री गोविन्दस्वामी गांधर्वविद्या के भी महान ज्ञाता थे। बसन्त, शिशिर, फाल्गुन आदि षट्ऋतुओं पर रचे गए इनके चिरस्मरणीय पद गीति-काव्य की अमूल्य सम्पदा हैं, जिन्हें शास्त्रीय रागों में पिरोकर स्वामी जी स्वयं तानपूरे पर गाते थे। अटारी ग्राम में इन दिनों अष्टसखा श्री गोविन्दस्वामी का एक भव्य पैनोरमा भी बन रहा है।

हिन्दी काव्य-जगत के सूर्य और महान कृष्णभक्त सूरदास जी की यही परम आकांक्षा है। वे कहते हैं कि प्रभु नन्दनन्दन बस इतनी शक्ति उन्हें प्रदान करें कि वे जीवन के अन्तिम क्षण तक गोवर्द्धन गिरिराज की परिक्रमा करते रह सकें!

गिरीन्द्र गोवर्द्धन की परिक्रमा का यही अशेष महत्व और पुण्य-प्रताप है।

महर्षि गर्गाचार्य द्वारा प्रणीत श्रीगर्ग –संहिता का तृतीय खण्ड 'गिरिराज–खण्ड' के रूप में अभिहित है। इसके दसवें अध्याय में श्रीमन्महर्षि द्वारा गोवर्द्धन पर्वत के माहात्म्य का यूं वर्णन किया गया है–

"गिरिराजो हरे रूपं श्रीमान् गोवर्धनोगिरिः।
तस्य दर्शनमात्रेण नरो याति कृतार्थताम्।।"

अर्थात् गिरिराज गोवर्द्धन पर्वत साक्षात श्री हरि का रूप हैं। उनके दर्शन मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। और

"ऋष्यमूकस्य सह्यस्य तथा देवगिरेः पुनः।
यात्रायां लभते पुण्यं समस्ताया भुवः फलम्।।

गिरिराजस्य यात्रायां तस्माकोटिगुणं फलम्।
गिरिराजसमं तीर्थं न भूतं न भविष्यति।।"

अर्थात् ऋष्यमूक, सह्यगिरि तथा देवगिरि की एवं सम्पूर्ण पृथ्वी की यात्रा करने पर मनुष्य जिस पुण्यफल को प्राप्त हो पाता है, गिरिराज गोवर्द्धन की यात्रा करने पर उससे भी कोटि गुना अधिक फल उसे प्राप्त हो जाता है। अतः गिरिराज के समान तीर्थ न तो पहले कभी हुआ है और न भविष्य में होगा ही।

गोवर्द्धन पर्वत का अवतरण

"पृथ्वी से पापों का भार उतारने के लिए जब भगवान श्रीकृष्ण भूमि पर मनुष्य रूप में अवतरित होने लगे तो श्री राधारानी के अनुरोध पर उन्होंने सर्वलोकवन्दिता ब्रज भूमि को भी पृथ्वी तल पर उतारने का निश्चय किया। इसमें चौरासी कोस के विस्तार वाली ब्रज भूमि के साथ-साथ यमुना जी व चौबीस वन भी शामिल थे।"

ब्रज के पृथ्वी पर अवतरण से सम्बन्धित उक्त कथा अनेक धर्मग्रन्थों में लिखी मिलती है, साथ ही ब्रज भूमि पर गोवर्द्धन पर्वत को लाने से सम्बंधित एक पौराणिक मिथक मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्यजी से भी जुड़ा है। एक बार तीर्थयात्रा के दौरान मुनिश्री गोवर्द्धन पर्वत की प्राकृतिक सुन्दरता पर मुग्ध हो गए थे और इसे इनके पिता द्रोणाचल गिरि से अनुनयपूर्वक मांग कर अपने साथ काशी नगरी को ले जा रहे थे। किंतु बीच रास्ते में घटनाक्रम ने ऐसा मोड़ लिया कि पर्वत को अपनी हथेली से उन्हें ब्रज भूमि पर उतारना पड़ा। यह तभी से यहां पर स्थापित है।

सप्तकोसी परिक्रमा-सातों जन्म निहाल

गिरिराज गोवर्द्धन की परिक्रमा को लेकर उक्त कहावत जगत प्रसिद्ध है। सप्त कोस यानी 21 किलोमीटर की इस पूर्ण परिक्रमा के दो भाग हैं। चार कोस (12 किमी.) की बड़ी परिक्रमा जो गोवर्द्धन पर्वत के चारों तरफ लगाई जाती है और तीन कोस यानी 9 किमी. की छोटी परिक्रमा, जो श्री राधाकुण्ड की है।

भू-आकृतिक अध्ययन की दृष्टि से यदि देखें, तो गोवर्द्धन पर्वत ब्रजभूमि के उत्तर-पश्चिम दिशा में लगभग 8 किमी. की लम्बाई में विस्तृत है। दक्षिण-पश्चिम दिशा में इसके आखिरी छोर पर पूंछरी नामक गांव बसा हुआ है, जो राजस्थान प्रांत में पड़ता है। पर्वत के उत्तर-पूर्वी दिशा में मथुरा जिले (उत्तर प्रदेश) का गांव गोवर्द्धन स्थित है। पूंछरी ग्राम की सीमा में ही "पूंछरी का लोठा" नामक प्रसिद्ध मन्दिर है। लौठाजी श्रीकृष्ण के घनिष्ठ मित्र थे, जो कृष्ण के द्वारिका जाते समय साथ चलने के उनके अनुरोध के बावजूद यहीं रह गए थे और बिना अन्न-जल ग्रहण किए अब तक अपने मित्र नन्दनन्दन का यहां वापस लौटने का इंतजार कर रहे हैं।

पर्वत परिक्रमा गोवर्द्धन गांव के दानघाटी मन्दिर से आरम्भ होती है, जिसके पथ में आन्यौर गांव, संकर्षण कुण्ड, गौरी कुण्ड, गोविन्द कुण्ड, अप्सरा कुण्ड, सुरभी कुण्ड, इन्द्र कुण्ड, ऐरावत कुण्ड व गोविन्दस्वामी की कदम्बखण्डी आदि प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। परिक्रमा पथ पर सर्वश्री कुम्भनदास, कृष्णदास, गोविन्दस्वामी एवं परमानन्ददास आदि महाकवियों की बैठकें बनी हुई हैं, जिन पर श्रृद्धालुजन धोक लगाते हैं। राजस्थान के पूंछरी गांव में छीतस्वामी जी की बैठक है।

श्री राधाकृष्ण के जमाने का एकमात्र स्थायी चिन्ह

ब्रजभूमि के तीर्थस्थलों के संदर्भ में सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि अकेला गोवर्द्धन गिरिराज ही श्री राधाकृष्ण के जीवनकाल का एक स्थायी और स्थिर चिन्ह है, जिसे स्वयं श्रीकृष्ण भगवान का दर्जा दिया जाता है। यही वजह है कि सम्पूर्ण भारतवर्ष और विदेशों तक से लाखों नर-नारी प्रतिवर्ष इस पर्वत के दर्शन करने व इसकी परिक्रमा लगाने आते हैं। परिक्रमा का यह सिलसिला दिन-रात अबाध चलता रहता है। पर्वत के शिखर पर महाप्रभु वल्लभाचार्यजी द्वारा पांच शताब्दी पूर्व प्रकट किया हुआ श्रीनाथ जी का पूर्ण स्वरूप व मुखारविन्द मन्दिर दर्शनीय हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गोवर्द्धन पर्वत का यह शिखर प्रतिवर्ष तिलभर नीचा होता जाता है, क्योंकि यह पर्वत हर साल भूमि में एक-एक तिल धंसता जा रहा है।

ब्रज चौरासी में अन्य पर्वत

ब्रज चौरासी की परिक्रमा सम्पूर्ण ब्रज मंडल को चारों ओर से घेरती है। गोवर्द्धन पर्वत की भांति ब्रज में अन्य अनेक पहाड़ियां भी यहां-वहां विश्रृंखलित रूप में फैली हुई हैं। धार्मिक आस्था के आधार पर हालांकि इन्हें 'पर्वत' की संज्ञा दी जाती है, लेकिन यथार्थ में ये छोटी-छोटी पहाड़ियां ही हैं। कविवर जगतनंद ने इनमें से पांच प्रमुख पहाड़ियों का "ब्रज वस्तु वर्णन" में निम्नानुसार बखान किया है-

गोबर्धन, नंदगांव में, अरु बरसाना, काम।
चरन पहाड़ी पाँच ये, 'जगतनंद' अभिराम।।

इनमें से गोवर्द्धन पर्वत का विस्तृत वर्णन हम ऊपर दे ही चुके हैं। 'नंदगांव पहाड़ी' ब्रज के नंदगांव नामक ग्राम में स्थित है, जिसे 'नंदीश्वर' अथवा 'रुद्रगिरि' भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग डेढ़ सौ फीट है। इसके शिखर पर नंदराय जी का मंदिर है।

बरसाना ग्राम में स्थित 'बरसाना पहाड़ी' को 'ब्रह्मगिरि' भी कहा जाता है। यह श्री राधाजी के पिता गोप वृषभानु का निवास-स्थल था। इस पहाड़ी पर लाड़ली जी का प्रसिद्ध मन्दिर है। अष्टछाप महाकवियों ने राधा-कृष्ण की लीलाओं के संदर्भ में बरसाना का बहुत सुन्दर वर्णन किया है। यह 'नंदगांव पहाड़ी' से कुछ बड़ी है।

'कामवन पहाड़ी' राजस्थान में स्थित कामबन अथवा कामां नामक स्थल पर है। लगभग चार सौ गज लम्बी ब्रज क्षेत्र की इस पहाड़ी को 'कामगिरि' भी कहा जाता है।

मथुरा जिले की छाता तहसील के 'छोटी बैठन' नामक गांव में 'चरण पहाड़ी' स्थित है। एक दूसरी 'चरण पहाड़ी' कामबन के पास है। यहां भी श्रीकृष्ण के चरण चिन्ह स्थित हैं।

इन पहाड़ियों के अलावा बरसाना के निकट ऊंचा गांव में 'सखी गिरि' नाम की एक छोटी-सी पहाड़ी है। इसी के निकट रणकौली गांव में भी एक पहाड़ी है।

उपर्युक्त वर्णन से यह पूर्णत: स्पष्ट हो जाता है कि राजस्थान का ब्रज क्षेत्र (जिसकी सीमाएं उत्तर प्रदेश में भी विस्तृत हैं) पहाड़ियों से पूर्ण सुशोभित है। श्री राधा-कृष्ण की लीलाभूमि होने के कारण इन पहाड़ियों का मान और माहात्म्य सम्पूर्ण विश्व में गाया जाता है। ■

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में साहित्य के साथ सुशासन की भी गूंज

भव्य राजस्थान पवेलियन बना आकर्षण का केंद्र

आशीष जैन, सहायक निदेशक

15 से 19 जनवरी तक जयपुर के क्लार्क्स आमेर होटल में आयोजित विश्वप्रसिद्ध जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान, जहां देश-विदेश से आए लेखक, विचारक और साहित्यप्रेमी साहित्य, संस्कृति और विचारों पर गंभीर चर्चा करते नजर आए, वहीं दूसरी ओर राजस्थान सरकार की योजनाओं, नीतियों और निर्णयों पर आधारित प्रचार-प्रसार सामग्री में भी आगंतुकों की विशेष रुचि देखने को मिली।

साहित्यिक मंच पर जनकल्याण की झलक

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के इतिहास में पहली बार राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित राजस्थान पवेलियन ने साहित्यिक वातावरण के बीच जनकल्याणकारी योजनाओं को संवाद का हिस्सा बनाया। पवेलियन में प्रस्तुत सामग्री ने यह दर्शाया कि साहित्य और सुशासन, दोनों समाज के निर्माण में समान रूप से महत्त्वपूर्ण हैं।

राजस्थान साहित्य, संगीत और कला की पुण्यभूमि है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल विचारों का उत्सव एवं महासागर है। यहां आमेर के किले से लेकर हवा महल तक हर विरासत में संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। यह आयोजन साहित्य के साथ राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर को और अधिक उजागर करने में मददगार साबित होता है।

- मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा

आधुनिक प्रस्तुति ने खींचा देश-विदेश के आगंतुकों का ध्यान

राजस्थान पवेलियन में राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं, नीतियों और निर्णयों को आधुनिक और रोचक माध्यमों के जरिए प्रस्तुत किया गया। पवेलियन में लगी तीन बड़ी एलईडी स्क्रीन पर ऑडियो-वीडियो प्रेजेंटेशन और डिजिटल स्लाइड्स के माध्यम से योजनाओं की जानकारी दी गई, जिसे देश-विदेश से आए आगंतुकों ने रुचि लेकर देखा और सराहा।

प्रतियोगी युवाओं के साथ विदेशी मेहमान भी रहे उत्सुक

जहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं ने राजस्थान पवेलियन में प्रदर्शित निःशुल्क सूचना सामग्री को उपयोगी माना, वहीं विदेशी मेहमानों और साहित्यप्रेमियों ने भी राजस्थान सरकार की विकास योजनाओं और नीतिगत पहलों को समझने में गहरी रुचि दिखाई। पवेलियन में रखा गया प्रचार साहित्य बड़ी संख्या में आगंतुकों द्वारा लिया गया।

सेल्फी बूथ से बढ़ी सहभागिता

पवेलियन में स्थापित सेल्फी बूथ ने भी आगंतुकों को आकर्षित किया। देश-विदेश से आए मेहमानों और युवाओं ने यहां फोटो खिंचवाकर अपने अनुभव साझा किए, जिससे पवेलियन की पहचान और अधिक मजबूत हुई।

साहित्य और शासन के बीच सशक्त संवाद

कुल मिलाकर 15 से 19 जनवरी तक आयोजित जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में राजस्थान पवेलियन ने यह सिद्ध किया कि साहित्यिक विमर्श के साथ-साथ सुशासन और जनकल्याण भी जनचर्चा का विषय बन सकता है। यह पवेलियन राज्य सरकार और आमजन के बीच संवाद का एक सशक्त और अभिनव मंच बनकर उभरा। ■

गंगनहर

मरुस्थल को हरियाली में बदलने वाली ऐतिहासिक जल क्रांति

अनिल शाक्य, जनसम्पर्क अधिकारी

लगभग सौ वर्ष पूर्व बीकानेर रियासत के दूरदर्शी शासक महाराजा गंगा सिंह ने जल को जीवन और विकास का मूल आधार माना। वर्ष 1899-1900 के भीषण अकाल की विभीषिका से त्रस्त जनता को राहत दिलाने और सीमावर्ती क्षेत्र को स्थायी रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए उन्होंने सतलुज नदी का जल बीकानेर क्षेत्र तक लाने की दूरगामी योजना बनाई। ऐसी विषम परिस्थितियों में उन्होंने दूरदृष्टि और दृढ़ संकल्प का परिचय देते हुए वर्ष 1925 में गंगनहर परियोजना का शुभारंभ किया। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों, सीमित संसाधनों और अनेक बाधाओं के बावजूद मात्र दो वर्षों में (वर्ष 1927) इस ऐतिहासिक नहर का निर्माण पूर्ण किया गया। गंगनहर ने इस क्षेत्र के भाग्य को पूरी तरह बदल दिया। जहां कभी सूखा और वीरान धरती हुआ करती थी, वहां आज हरियाली लहलहाती है, खेतों में फसलें लहराती हैं और जीवन की नई ऊर्जा दिखाई देती है। यह समृद्धि और विकास महाराजा गंगा सिंह के अथक परिश्रम, दूरदर्शिता और त्याग का परिणाम है। गंगनहर न केवल सिंचाई का साधन बनी, बल्कि इस क्षेत्र की जीवनरेखा बनकर लोगों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि लेकर आई।

भारत-पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ श्रीगंगानगर जिला आज राजस्थान के सबसे समृद्ध कृषि क्षेत्रों में गिना जाता है, किंतु यह समृद्धि सहज नहीं मिली। एक समय यह संपूर्ण क्षेत्र थार मरुस्थल का हिस्सा था, जहां पानी का अभाव, बार-बार पड़ने वाले अकाल, सीमित आजीविका और जनसंख्या पलायन आम बात थी। वर्षा अत्यंत अल्प होती थी और खेती केवल कल्पना मात्र थी। ऐसे कठिन हालात में जिस परियोजना ने इस सीमावर्ती क्षेत्र के भाग्य को बदला, वह थी गंगनहर परियोजना–राजस्थान की पहली मानव निर्मित और ऐतिहासिक सिंचाई योजना।

प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान इम्पीरियल वॉर कैबिनेट के सदस्य के रूप में महाराजा गंगा सिंह की भूमिका और उनके योगदान के फलस्वरूप वर्ष 1919 में कृषि संबंधी ऐतिहासिक समझौता हुआ। इस समझौते के अंतर्गत गंगनहर के साथ-साथ रेलवे लाइन निर्माण का भी प्रावधान रखा गया, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों का सामरिक, आर्थिक और प्रशासनिक विकास सुनिश्चित हो सके। यह निर्णय उस समय अत्यंत दूरदर्शी सिद्ध हुआ, विशेषकर भारत-पाकिस्तान सीमा से सटे श्रीगंगानगर जैसे संवेदनशील जिले के लिए।

लगभग 5 से 6 करोड़ रुपये (वर्ष 1920 के मूल्य अनुसार) की लागत से निर्मित गंगनहर परियोजना का शिलान्यास 5 दिसंबर 1925 को किया गया। रेतीली भूमि, कठोर जलवायु और सीमित तकनीकी संसाधनों के बावजूद मात्र दो वर्षों में इस विशाल परियोजना को पूर्ण कर लिया गया। 26 अक्टूबर 1927 को वायसराय लॉर्ड इरविन ने पंडित मदन मोहन मालवीय की उपस्थिति में इसका उद्घाटन किया। यह दिन पश्चिमी राजस्थान, विशेष रूप से श्रीगंगानगर जिले के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज हो गया।

महाराजा गंगा सिंह के सम्मान में इस नहर का नाम गंगनहर रखा गया। इस नहर ने भारत-पाकिस्तान सीमा से सटे श्रीगंगानगर जिले में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। हजारों हेक्टेयर बंजर भूमि उपजाऊ खेतों में बदल गई। गेहूं, कपास, सरसों और धान जैसी फसलों की भरपूर पैदावार होने लगी। सीमावर्ती गांवों में बसावट बढ़ी, रोजगार के अवसर सृजित हुए और किसान आर्थिक रूप से सशक्त बने। आज श्रीगंगानगर जिला 'राजस्थान का अन्न भंडार' कहलाता है, जिसका श्रेय गंगनहर को जाता है।

वर्तमान में गंगनहर प्रणाली श्रीगंगानगर जिले की लगभग 3.14 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचित करती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 1353 किलोमीटर है। यह नहर न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाने का माध्यम बनी, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्र में जनसंख्या स्थायित्व और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुई। खेती और रोजगार के कारण सीमावर्ती गांव मजबूत हुए, जिससे सीमा क्षेत्र में सामाजिक स्थिरता आई।

समय के साथ जल प्रबंधन की नई चुनौतियां सामने आईं। वर्ष 1954 के बाद भाखड़ा एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना के जुड़ने से सिंचाई का दायरा और विस्तृत हुआ। प्रारंभिक दौर में गंगानगर क्षेत्र की नहरें कच्ची थीं, जिससे जल रिसाव और क्षति अधिक होती थी। इसे ध्यान में रखते हुए वर्ष 2000 के बाद नहरों के पक्कीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। वर्ष 1995 के पश्चात विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लगभग 3.14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में नहरों को कच्चे से पक्के स्वरूप में बदला गया, जिससे सिंचाई दक्षता में उल्लेखनीय सुधार हुआ।

वर्तमान समय में माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा गंगनहर प्रणाली के आधुनिकीकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है। सिंचित क्षेत्र विकास विभाग के माध्यम से पिछले दो वर्षों में गंग-भाखड़ा नहर प्रणाली के अंतर्गत 1,11,357 हेक्टेयर क्षेत्र में नहरों के पुनर्स्थापन हेतु 444.44 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। यह कार्य विशेष रूप से श्रीगंगानगर जिले के सीमावर्ती किसानों के लिए राहतकारी सिद्ध हो रहा है।

श्रीगंगानगर जिले के किसानों की वर्षों पुरानी मांग फिरोजपुर फीडर की लाइनिंग को लेकर पंजाब सरकार से निरंतर समन्वय किया जा रहा है। यह फीडर सीमावर्ती क्षेत्र के लिए जीवनरेखा के समान है। इसके पुनर्निर्माण से जल आपूर्ति में निरंतरता आएगी और किसानों को समय पर सिंचाई का लाभ मिलेगा। इसी क्रम में बीकानेर कैनाल की रीलाइनिंग के लिए डीपीआर तैयार करने का कार्य भी प्रगति पर है। जल वितरण को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से गंगनहर प्रणाली में राजस्थान में पहली बार विश्वस्तरीय ऑटोमेशन तकनीक लागू की जा रही है। लगभग 695.16 करोड़ रुपये की लागत से होने वाली यह परियोजना जल की प्रत्येक बूंद का न्यायसंगत उपयोग सुनिश्चित करेगी और सीमावर्ती जिले श्रीगंगानगर में आधुनिक जल प्रबंधन की नई मिसाल बनेगी।

5 दिसंबर 2025 का दिन गंगनहर के इतिहास में विशेष महत्व रखता है। इस दिन वर्ष 1925 में इस ऐतिहासिक परियोजना का शिलान्यास हुआ। गंगनहर के शिलान्यास की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा 5 दिसंबर 2025 को साधुवाली में गंगनहर शताब्दी समारोह में फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण का शिलान्यास किया गया। यह निर्णय महाराजा गंगा सिंह की दूरदर्शिता को सच्ची श्रद्धांजलि है और श्रीगंगानगर जैसे सीमावर्ती जिले के भविष्य को और अधिक सुरक्षित व समृद्ध बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा।

गंगनहर केवल एक सिंचाई परियोजना नहीं, बल्कि भारत-पाकिस्तान सीमा से सटे श्रीगंगानगर जिले के सामाजिक, आर्थिक और रणनीतिक विकास का आधार स्तंभ है। यह परियोजना मरुस्थल में हरियाली, सीमावर्ती किसानों में आत्मविश्वास और क्षेत्र में स्थाई विकास की प्रतीक बन चुकी है। गंगनहर अतीत की दूरदृष्टि, वर्तमान की प्रतिबद्धता और भविष्य की आशा का जीवंत उदाहरण है। ■

राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026

नवाचार, उद्यमिता और तकनीकी क्रांति का महाकुंभ

डॉ. आशीष खण्डेलवाल, उप निदेशक

अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और गौरवशाली इतिहास के लिए विश्वविख्यात राजस्थान ने 4-6 जनवरी 2026 तक एक ऐतिहासिक आयोजन के माध्यम से स्वयं को वैश्विक नवाचार और उद्यमिता के केंद्र के रूप में स्थापित किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व में, राजस्थान सरकार और टाई राजस्थान के सहयोग से जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर (जेईसीसी) में आयोजित राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 प्रदेश में नई तकनीकी क्रांति का संवाहक बना।

यह समिट तकनीक, उद्यमिता और सतत विकास को एक मंच पर लाकर राजस्थान को भारत के प्रमुख आईटी और स्टार्टअप हब के रूप में उभारने का माध्यम बना। इस तीन दिवसीय आयोजन ने न केवल स्थानीय स्टार्टअप्स और युवा उद्यमियों को वैश्विक मंच प्रदान किया, बल्कि निवेश, मेंटरशिप और ज्ञान विनिमय के नए द्वार भी खोले। समिट में 10,000 से ज्यादा प्रतिभागी शामिल हुए, जिनमें स्टार्टअप्स, निवेशक, युवा उद्यमी, आईटी पेशेवर, छात्र, शैक्षणिक संस्थान और विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ आईटी तथा उद्योग अधिकारी शामिल थे। साथ ही सैकड़ों फाउंडर्स, सीईओ और निवेशक, यूनिकॉर्न और सूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के फाउंडर्स ने हिस्सा लिया।

समिट में स्टार्टअप्स के लिए 200 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की राह खुली। साथ ही स्टार्टअप्स में सह-निवेश के लिए राज्य सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए के 'फंड ऑफ फंड्स' की घोषणा की गई। इससे प्रदेश के प्रतिभाशाली स्टार्टअप्स को और प्रोत्साहन मिल सकेगा तथा निवेश एवं रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक ने इस मेगा इवेंट को अपना समर्थन दिया, जो अंतरराज्यीय सहयोग की मिसाल बना।

पहली रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस

राजस्थान में पहली बार आयोजित रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस इस बार समिट का मुख्य आकर्षण रही। यह कॉन्फ्रेंस इंडिया एआई मिशन से जुड़ी थी, जिसका उद्देश्य भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के वैश्विक दिग्गज के रूप में स्थापित करना है। राज्य सरकार ने इस मौके पर 'एआई-एमएल पॉलिसी' की रूपरेखा पेश की, जिसके तहत एआई सिस्टम को पारदर्शी, निष्पक्ष और निजता-संरक्षण के प्रति जवाबदेह बनाया जाएगा। नीति के लागू होने से सार्वजनिक सेवा वितरण अधिक त्वरित, नागरिक-केंद्रित होगा और इससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

स्टार्टअप और शिक्षा के लिए नए अवसर

कॉन्फ्रेंस में यह भी घोषणा की गई कि प्रदेश में 'एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' स्थापित किया जाएगा और स्कूलों, आईटीआई, पॉलिटेक्निक एवं कॉलेजों में एआई शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, उद्योगों, स्टार्टअप्स और रिसर्च संस्थानों को विशेष प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे। इस तरह के आयोजन स्टार्टअप्स को निवेशकों से, विद्यार्थियों को अवसरों से और उद्योग को सरकार से जोड़ने का मंच साबित हो रहे हैं। एआई-एमएल, फिनटेक, एग्रीटेक, एआर-वीआर और प्रॉपटेक जैसे क्षेत्रों में विचार-विमर्श से नए अवसरों के द्वार खुल रहे हैं, जिससे डिजिटल राजस्थान की दिशा और सशक्त हो रही है।

युवाओं की पसंद बना कॉमिक कॉन

इस अवसर पर आयोजित जयपुर कॉमिक कॉन पॉप कल्चर का उत्सव बना। सेलिब्रिटी सेशंस, मर्चेंडाइज, कॉसप्ले, गेमिंग एरिनास और फैन एक्सपीरियंस ने युवाओं को आकर्षित किया। इस इवेंट ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ कॉसप्लेयर्स को मंच दिया। कॉसप्ले प्रतियोगिता में, प्रतिभागियों ने मार्वल और डीसी कैरेक्टर्स को जीवंत किया। गेमिंग जोन में ई-स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स हुए, जहां लोकल गेमर्स ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाई।

हर घर और उद्यम तक पहुंचेगा एआई

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व प्रगति की है, जिससे देश विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। जनधन, मोबाइल कनेक्टिविटी और डिजिटल सेवाओं के जरिए भारत ने एक ऐसा मॉडल पेश किया है, जो विकसित देशों को भी सहयोग के लिए प्रेरित कर रहा है। आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाएगा और हर व्यक्ति, हर घर तथा हर उद्यम तक इसकी पहुंच सुनिश्चित होगी। एआई को समावेशी, सुलभ और जनोपयोगी बनाने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदम देश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति में महत्त्वपूर्ण योगदान देंगे।

राजस्थान में कौशल विकास और डेटा सेंटर पहल

राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए उद्योग संगठनों के सहयोग से नए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इस पहल के तहत 5 हजार युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। साथ ही, राज्य में डेटा सेंटर स्थापित करने की योजना है, जिसके लिए आवश्यक प्रक्रियाएं जल्द ही प्रारंभ होंगी। ये कदम प्रदेश को डिजिटल अवसंरचना और तकनीकी विशेषज्ञता के क्षेत्र में मजबूत बनाएंगे।

राजस्थान में तकनीकी नवाचार और डिजिटल पहुंच

राजस्थान तकनीकी नवाचार और डिजिटलीकरण के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। राज्य में फाइबर ऑप्टिक केबल गांव-गांव तक पहुंच चुकी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के युवा सीधे वैश्विक और आधुनिक प्रौद्योगिकी से जुड़ रहे हैं। इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, रोजगार और स्टार्टअप के अवसर भी बढ़ रहे हैं। साथ ही, इससे स्थानीय उद्यमियों और छोटे व्यवसायों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नए बाजार तक पहुंचने में मदद मिल रही है।

एआई-एमएल पॉलिसी 2026 लॉन्च

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर नेशनल एआई लिटरेसी प्रोग्राम, राजस्थान एआई-एमएल पॉलिसी 2026, आई स्टार्ट एलएमएस, राजस्थान एवीजीसी-एक्सआर पोर्टल तथा राजस्थान एआई पोर्टल को लॉन्च किया। इस दौरान राज्य सरकार द्वारा गूगल, आईआईटी दिल्ली, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर के साथ योजना भवन में हुए विभिन्न द्विपक्षीय एमओयू का होलोग्राफिक तकनीक के माध्यम से जीवंत प्रसारण भी किया गया। उल्लेखनीय है कि जी-20 में भी इसी तकनीक का उपयोग किया गया था।

एआई का नैतिक उपयोग आवश्यक

कॉन्फ्रेंस में विशेषज्ञों ने एआई के विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा की, जैसे हेल्थकेयर में एआई का उपयोग रोग निदान के लिए, कृषि में फसल पूर्वानुमान के लिए और शिक्षा में व्यक्तिगत लर्निंग टूल्स के लिए। एक प्रमुख सत्र में, एआई एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी कि एआई के नैतिक उपयोग पर ध्यान देना आवश्यक है, अन्यथा यह असमानता को बढ़ा सकता है।

सेक्टोरल सेशंस में नए युग की तकनीक पर चर्चा

समिट में सेक्टोरल सेशंस ने विशेषज्ञों की अंतर्दृष्टि प्रदान की, जो फिनटेक, ई-कॉमर्स, एग्रीटेक, हेल्थटेक, प्रॉपटेक, एवीजीसी, मीडियाटेक, स्पोर्ट्सटेक, एआई-एमएल और डीपटेक जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित थे। फिनटेक सेशन में विभिन्न यूनिकॉर्न के फाउंडर्स ने डिजिटल पेमेंट्स की भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा की। वहीं एग्रीटेक सेशन में राजस्थान के किसानों के लिए ड्रोन आधारित फसल मॉनिटरिंग के सफल केस स्टडीज प्रस्तुत की गईं। हेल्थटेक में, टेलीमेडिसिन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच पर जोर दिया गया। इस अवसर पर 100 से अधिक स्टार्टअप स्टॉल्स और विभिन्न राज्यों के आईटी तथा कम्युनिकेशन विभागों के पैविलियंस ने नवाचारों का प्रदर्शन किया, जहां ज्ञान विनिमय और बिजनेस समझौते हुए।

हैकाथॉन में प्रतिभाओं ने विकसित किए नवाचार

राजस्थान डिजिफेस्ट और टाई ग्लोबल हैकाथॉन एक 36 घंटे का राष्ट्रीय नवाचार चुनौती था, जिसने युवा डेवलपर्स, उद्यमियों और क्रिएटर्स को सशक्त बनाया। यह हैकाथॉन टाई ग्लोबल समिट और राजस्थान डिजिफेस्ट के साथ जुड़ा हुआ था, जहां ग्रासरूट टैलेंट को वैश्विक अवसर मिले। प्रतिभागियों ने सुशासन, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, रोजगार सुरक्षा एवं डिजिटल ट्रस्ट जैसे विषयों पर नवाचार मॉडल प्रस्तुत किए। हैकाथॉन में कुल 400 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें 30 स्टार्टअप टीमों के 120 प्रतिभागी एवं आईटी विभाग की 70 टीमों के 280 प्रतिभागी शामिल रहे।

आईएफएफओआर में 50 से अधिक फिल्मों का प्रदर्शन

समिट के समानांतर आयोजनों ने इसे और भी रोचक बना दिया। आईस्टार्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ राजस्थान (आईएफएफओआर) का तीसरा संस्करण, द ओपन स्पेस सोसाइटी (टीओएसएस) द्वारा संचालित किया गया। इस अवसर पर 50 से अधिक विविध फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। सिनेमा, नवाचार और रचनात्मक संवाद आयोजित किए गए। देश-विदेश से चयनित फिक्शन और डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के प्रदर्शन के साथ तकनीकी और रचनात्मक मास्टरक्लास तथा विशेष समापन प्रस्तुतियां दी गईं।

क्राफ्ट शोकेस

क्राफ्ट शोकेस ने राजस्थान की पारंपरिक कला और शिल्प को हाइलाइट किया, जहां कारीगरों को वैश्विक उद्यमियों और निवेशकों से जोड़ा गया। यह एक क्यूरेटेड मार्केटप्लेस था, जहां ब्लू पॉटरी, ब्लॉक प्रिंटिंग और ज्वेलरी जैसे उत्पाद प्रदर्शित हुए।

गेम जैम जयपुर 2026

इस अवसर पर गेम डेवलपमेंट प्रतियोगिता 'गेम जैम' का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। अपने पहले संस्करण में 76 टीमों के 240 गेम डेवलपर्स ने 48 घंटे के गेम डेवलपमेंट चैलेंज में हिस्सा लिया। गेम जैम का आयोजन आउटलुक रेस्पॉन और सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा नॉडविन गेमिंग के सहयोग से किया गया।

टीजीएस100 और टाई वूमेन ग्लोबल फाइनल्स

टीजीएस100 एक पिचिंग कॉम्पिटिशन था, जो अर्ली-स्टेज स्टार्टअप्स के लिए था। यहां स्टार्टअप्स ने अपने आइडियाज पिच किए और टॉप 10 को फंडिंग और नेटवर्किंग के अवसर मिले। साथ ही टाई वूमेन ग्लोबल फाइनल्स ने महिलाओं द्वारा फाउंडेड या को-फाउंडेड अर्ली-स्टेज स्टार्टअप्स को मंच दिया। यहां महिलाओं ने अपनी चुनौतियां और सफलताएं साझा कीं। इसके अलावा टाई यू ग्लोबल फाइनल्स एक 6 महीने का प्रोग्राम था, जो कॉलेजिएट उद्यमियों के इनोवेटिव आइडियाज को मार्केट-रेडी वेंचर्स में बदलता है। यहां छात्रों ने अपने प्रोजेक्ट्स प्रस्तुत किए और टॉप टीमों को फंडिंग मिली।

कुल मिलाकर, यह समिट न केवल आर्थिक विकास का माध्यम बना, बल्कि युवाओं को प्रेरित करने वाला भी रहा। राजस्थान अब नवाचार का पर्याय बन चुका है, जहां परंपरा और तकनीक का अनोखा मेल देखने को मिलता है। समिट की सफलता से स्पष्ट है कि राजस्थान आधुनिकतम तकनीकों को अपनाने के मामले में अपनी विशिष्ट पहचान बना रहा है। ■

> **"एआई स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि सहित अनेक क्षेत्रों में परिवर्तन लाकर लोगों के जीवन को बेहतर बना रहा है और यह विकसित भारत एवं विकसित राजस्थान के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा।"**
>
> **– मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा**

राजस्थान संपर्क 2.0 : शिकायत निवारण का केंद्रीकृत मंच

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राजस्थान सरकार प्रदेश में नागरिक-केंद्रित सुशासन स्थापित करने के लिए पूरी तरह समर्पित है। इसी दिशा में राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 के जरिए आमजन को सरकार तक अपनी बात आसानी से पहुंचाने का सुविधाजनक माध्यम उपलब्ध कराया गया है। इस प्लेटफॉर्म से राज्य के सभी विभाग, बोर्ड, निगम, उपक्रम और शैक्षणिक संस्थान जुड़े हुए हैं। प्रदेशवासी अपनी कोई भी समस्या या शिकायत निम्न तरीकों से दर्ज करा सकते हैं:

- टोल-फ्री नंबर 181 पर कॉल करके
- वेबसाइट https://sampark.rajasthan.gov.in/ के माध्यम से मोबाइल ऐप के जरिए
- व्हाट्सएप नम्बर (+91 9461067924) पर

इन सभी माध्यमों से दर्ज शिकायतों का निश्चित समय-सीमा में समाधान सुनिश्चित किया जाता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी व मजबूत बनाया है, जिसके परिणामस्वरूप लाखों लोगों को समय पर राहत मिल रही है। यह मंच सिर्फ शिकायतों का निपटारा ही नहीं करता, बल्कि विभागों में जवाबदेही और पारदर्शिता भी बढ़ाता है, जिससे सुशासन की मजबूत नींव तैयार हो रही है। सरकार संवेदनशीलता के साथ हर समस्या सुन रही है और उसका त्वरित समाधान कर रही है। हेल्पलाइन 181 अब प्रदेशवासियों और सरकार के बीच एक मजबूत संवाद का सेतु बन चुकी है। यह एक ऐसा एकीकृत तंत्र है, जो सुगम, सरल, पारदर्शी और तेज़ी से राहत देने वाला साबित हो रहा है। खास बात यह कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा खुद समय-समय पर 181 कॉल सेंटर पहुंचकर आम लोगों की समस्याएं

व्यक्तिगत रूप से सुनते हैं और संबंधित अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश देते हैं।

राजस्थान संपर्क के जरिए न केवल शिकायतों का निस्तारण हो रहा है, बल्कि सरकारी योजनाओं और सेवाओं की जानकारी भी आसानी से उपलब्ध हो रही है। प्रतिदिन हजारों लोगों की समस्याओं का समाधान इस मजबूत व्यवस्था से हो रहा है, जो जनता और सरकार के बीच विश्वास का सेतु बनकर उभर रहा है।

सफलता की कहानी – 181 की जुबानी

पानी की सुचारू सप्लाई हुई सुनिश्चित

श्रीमाधोपुर, सीकर के श्री संदीप द्वारा 29 नवम्बर, 2025 को उनके क्षेत्र में 6 महीने से पानी की सुचारु सप्लाई नहीं होने के संबंध में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। दिनांक 30 नवम्बर, 2025 को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सहायक अभियंता द्वारा समस्या का निवारण कर दिया गया। परिवाद के निस्तारण के सत्यापन के दौरान श्री संदीप ने धन्यवाद देते हुए बताया कि 6 महीने पुरानी समस्या का समाधान राजस्थान संपर्क पोर्टल के द्वारा तुरंत करवा दिया गया है। उन्होंने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का धन्यवाद प्रकट किया।

वाहन फिटनेस सर्टिफिकेट जारी

कोटपूतली के श्री पप्पू मीणा द्वारा 25 नवम्बर, 2025 को उनके वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं बनने बाबत परिवाद दिया गया था। जिला परिवहन कार्यालय, कोटपूतली द्वारा 1 दिसम्बर, 2025 को वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करते हुए परिवाद का निस्तारण किया गया। परिवाद के निस्तारण के सत्यापन के दौरान श्री पप्पू मीणा ने फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्ति को सत्यापित करते हुए निस्तारण से संतुष्टि दर्ज करवाई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आमजन की परिवेदनाओं पर त्वरित कार्यवाही कर सुशासन की स्थापना कर रही है।

मीटर की लाइट दुरुस्त

खैरथल-तिजारा के श्री जयपाल ने 22 दिसम्बर, 2025 को राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करवाई कि इनके यहां तीन-चार दिन से लाइट नहीं आ रही है। हेल्पलाइन की ओर से इस संबंध में त्वरित कार्यवाही करते हुए जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से समन्वय किया गया और श्री जयपाल के निवास पर विद्युत आपूर्ति को अविलम्ब बहाल किया गया। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने जानकारी दी कि उपभोक्ता के मीटर की लाइट ठीक करवाकर विद्युत सप्लाई सुचारु रूप से चालू करवा दी गई है। परिवाद के निस्तारण के सत्यापन के दौरान श्री जयपाल जी ने संतुष्टि दर्ज करवाई और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा को धन्यवाद दिया। ■

गुप्तकालीन शिखरबंद देवरा

पांचवीं शताब्दी में बने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा

डॉ. अरुणा व्यास, स्वतंत्र लेखिका

राजस्थान भक्ति और शक्ति का प्रदेश है। यहां की संस्कृति धर्म और अध्यात्म में गुंथी हुई है। देवालयों के इतिहास में जांएगे, तो यह भी पाएंगे अपने देवताओं को बचाने के लिए यहां के लोगों ने हवेलियों में मंदिरों का निर्माण किया। हरि कीर्तन की हवेली संगीत परम्परा का यहां नाद हुआ। यह वह समय था, जब औरंगजेब द्वारा मंदिर ध्वस्त किए जा रहे थे। ऐसे दौर में महाप्रभु श्रीवल्लभाचार्य के वंशज ब्रज से श्रीनाथजी के विग्रह को लेकर मेवाड़ राज्य के सिहाड़ नामक स्थान पर पहुंचे। यह सिहाड़ ही नाथद्वारा के रूप में वैष्णव संप्रदाय की प्रमुख पीठ बनी। पर यह ज्ञात इतिहास है। अज्ञात इतिहास यह भी कि मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा बहुत से प्राचीन मंदिर राजस्थान में निरंतर ध्वस्त किए जाते रहे।

देवरा, बसई है आज का बाढ़ भावसिंह गांव

ऐसा ही एक गुप्तक़ालीन मंदिर कोटपूतली जिले में रहा है। यह मंदिर तब शिखरबंद देवरा, बसई (इस समय बाढ़ भावसिंह, बानसूर) से जाना जाता था। कहते हैं, लगभग पन्द्रह सौ वर्ष पुराने इस प्राचीन सिद्ध मंदिर को मुस्लिम आक्रांताओं ने अनेक बार नष्ट करने का प्रयास किया। पर, हर बार किसी ना किसी ठिकानेदार द्वारा या जन प्रयासों से इसका पुनर्निर्माण होता रहा। इस मंदिर से संबंधित, जो अब तक का सबसे पुराना लिखित प्रमाण मिला है, उसके अनुसार लगभग चार सौ वर्ष पूर्व राव सूजा जी ने बसई शहर को पुन: बसा कर इस मंदिर का भी पुनरुद्धार किया। इसके बाद फिर से यह ध्वस्त हो गया, पर 12वीं सदी में भी इस मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख फिर से मिलता है।

यह मंदिर जीर्ण–शीर्ण होते हुए भी अत्यंत भव्य था, पर आजादी के बाद एक समय वह भी आया, जब यहां स्थापित मूर्तियां गायब कर दी गईं। जीर्ण–शीर्ण मंदिर के अवशेष तब भी उसके इतिहास की कहानी कहते थे।

लक्ष्मी–नारायण की भव्य प्रतिमाएं स्थापित

इस प्राचीन, पर धार्मिक रूप से बहुत महत्त्वपूर्ण मंदिर का फिर से जीर्णोद्धार कर इसे जीवंत किया गया है। मंदिर का पुनर्निर्माण ही नहीं हुआ, बल्कि प्रबोधिनी एकादशी यानी देवउठनी एकादशी, भगवान विष्णु के जागरण के पवित्र दिन लक्ष्मी–नारायण की भव्य प्रतिमाएं स्थापित हुईं। सुदूर स्थानों से लोग मंदिर पहुंचे और पांचवीं सदी में निर्मित मंदिर के जीवंत इतिहास के फिर से गवाह बने। बानसूर का यह मंदिर जीवंत ही नहीं हुआ है, फिर से जन–जन की आस्था का केन्द्र बन गया है।

भारतीय देव-संस्कृति का जीवंत रूप

भारतीय पुलिस सेवा के धर्म-संस्कृति मर्मज्ञ अधिकारी श्री रमाकांत गुप्ता ने इस मंदिर के पुनरुद्धार में महत्ती भूमिका निभाई। उनके प्रयासों से अतीत में गुम हुए गुप्तकालीन प्राचीन मंदिर के पुनरुद्धार का कार्य जन सहयोग से संपन्न हुआ और यहां भगवान लक्ष्मी नारायण मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई। बानसूर के इस शिखरबंद देवरा, लक्ष्मी-नारायण मंदिर की बड़ी विशेषता इसका पांचवीं सदी में निर्मित होना तो है ही, यह भी है कि नए रूप में भी इसमें भारतीय देव-संस्कृति को जीवंत किया गया है।

मंदिर की मूर्तिकला और अलौकिक सौंदर्य

कोटपूतली से बानसूर जाने के रास्ते में मुख्य सड़क पर निर्मित शिखरबंद देवरा मंदिर की बाह्य दीवारों पर भगवान नरसिंह की छोटे आलय में भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है, तो गर्भगृह के बाहर भी विष्णु के द्वारपालों की संगमरमर की चित्ताकर्षक प्रतिमाएं स्थापित की गई है। गर्भगृह में लक्ष्मी-नारायण का मन को अलौकिक आनंद से भर देने वाला अष्टधातु का बहुत सुंदर विग्रह स्थापित किया गया है।

नागर शैली पर आधारित है सनातन मंदिर

पांचवीं शताब्दी के राजस्थान के मंदिरों का स्थापत्य मुख्य रूप से नागर शैली पर आधारित रहा है। इसमें ऊंचे शिखर, जटिल नक्काशी और देवताओं की प्रतिमाएं होती थीं। इस काल के बचे हुए, तोड़े जाने के बाद बार-बार बने मंदिरों में से एक बानसूर का यह लक्ष्मी-नारायण मंदिर, इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है कि इसमें गर्भगृह (जिसमें देवता की मूर्ति होती है) के ऊपर मंदिर का प्रमुख केंद्र शिखर अभी भी वैसा ही नजर आता है। हमारी 'देव संस्कृति' का मूल आधार धर्म और अध्यात्म ही रहा है। सनातन भारतीय संस्कृति का अर्थ ही होता है, शास्वत। इसका अंतिम लक्ष्य भौतिक सुख प्राप्ति नहीं होकर आत्मज्ञान और मोक्ष है। भगवान विष्णु को सृष्टि का संरक्षक, पालनकर्ता कहा गया है। लक्ष्मी-नारायण शब्द संयोजन जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि दोनों का आदर्श प्रतिनिधित्व है। इसीलिए लक्ष्मी-नारायण विग्रह भक्ति के साथ समर्पण का भाव जगाता है।

समुद्र मंथन से दिव्यता का संगम

नारायण से पहले लक्ष्मी का नाम आता है। इसलिए कि लक्ष्मी नारायणी है। भगवान नारायण की शक्ति वही हैं। लक्ष्मी नारायण की सबसे महत्त्वपूर्ण कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। भगवान विष्णु देवताओं और असुरों की सहायता के लिए क्षीरसागर मंथन में अपना कूर्म अवतार धारण करते हैं। मंथन से प्राप्त अनेक निधियों में से एक लक्ष्मी भी उभरती हैं। देवता विष्णु से उनसे विवाह करने का अनुरोध करते हैं और इस प्रकार उनकी शुभता का विवाह विष्णु की दिव्यता से होता है। इसी से ब्रह्मांडीय व्यवस्था पुन: स्थापित होती है। ब्रह्मांडीय व्यवस्था के पुन: स्थापित होने के आलोक में ही पांचवीं शताब्दी के प्राचीन मंदिर के देवउठनी एकादशी पर फिर से जीवंत होने की यह महती दृष्टि है।

सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गौरव गाथा

इस प्राचीन मंदिर के पुनर्निर्माण ने न केवल बानसूर को गौरवान्वित किया है, बल्कि पूरे राजस्थान की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को भी एक नया जीवनदान दिया है। यह मंदिर अब केवल एक स्थापत्य स्मारक नहीं रह गया है, बल्कि लोगों की आस्था, श्रद्धा और भक्ति का जीवंत प्रतीक बन गया है। प्राचीन काल में जीर्ण-शीर्ण हो चुके मंदिर की पहचान कर उसके पुनर्निमाण की यह दृष्टि न केवल इतिहास को संजोने का उदाहरण है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। पुनर्निर्माण के माध्यम से इस मंदिर ने अपनी प्राचीन महिमा और भव्यता फिर से प्राप्त की है और अब यह स्थल जन-जन के लिए आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना का केंद्र बन चुका है। इस प्रकार, शिखरबंद देवरा मंदिर का पुनरुद्धार केवल वास्तुकला का कार्य नहीं, बल्कि राजस्थान की समृद्धि, परंपरा और सनातन भारतीय संस्कृति के मूल्यों का भी पुन: संचार है। ■

Role of Environmental Laboratories and Quality Assurance

Dr. Aruna Sharma, SSO, RSPCB

An environmental laboratory is a laboratory processing samples taken from the environmental media (air, water, soil, biota) both from the environment as well as from sources disposing into the environment (industries, domestic and agriculture sources, automobiles etc.). Environmental laboratories are the essential cornerstones of any effective pollution control programme. These are basically analytical laboratories that provide qualitative as well as quantitative data for good decision-making purposes.

The Environmental laboratories required in the implementation of the various pollution control acts laid down for the protection of the environment; have been made essential under the following sections of various acts:

- The Water (Prevention and Control of Pollution), Act, 1974- Section 17 (2), Section 25 & 26, Section 51 & 52 and Section 53 Subsection (iii)
- The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981- Section 17 (2), Section 21, Section 28 & 29 Subsection (i)(ii)
- The Environment (Protection) Act, 1986- Section 12, Section 13

As per the above mandate under various Acts, the Rajasthan State Pollution Control Board (RSPCB) has established 27 Environmental laboratories (14 earlier established and 13 new laboratories). The State Board laboratories, being a part of Statutory Organization, have been entrusted with the responsibility to monitor & quantify the load of environmental pollutants in various components of the environment- air, water and noise etc. and to check the efficiency of installed pollution control devices (PCDs) installed in various industries. Therefore, the analytical results produced by these Environmental laboratories are the backbone for a stringent compliance mechanism & for effective decision making.

For generating this valuable data with a desired accuracy and to quantify the concentration of the constituents present in the samples, the laboratory should have the desired facilities and capabilities to achieve the above goal. Accreditation is the instrument to ensure Quality in the work of testing laboratories. Accreditation is a voluntary, independent, and peer-reviewed process of quality assurance that verifies that the laboratory/organisation/institution meets established standards of competency, credibility and valid results. Once achieved, accreditation is not permanent—it is renewed periodically to ensure that the quality of the entity is maintained.

The global standard for testing and calibration laboratories is ISO/IEC 17025:2017 Accreditation. The accrediting Government entity of this standard is NABL. NABL (National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories) is an autonomous body under India's Department for Promotion of Industry and Internal Trade, which formally recognizes the technical competence of testing and calibration laboratories. It validates compliance with international standards- ISO/IEC 17025 and ensures reliable, high-quality, and globally accepted test results.

NABL is a Mutual Recognition Arrangement (MRA) signatory to ILAC (International Laboratory Accreditation Co-

operation) as well as APAC (Asia Pacific Accreditation Co-operation) for the accreditation programs including ISO/IEC 17025 accreditation for Testing and Calibration laboratories. Such international arrangements/ MRA are based on peer evaluation and acceptance of other MRA Partner accreditation systems. MRA facilitates acceptance of test/ calibration results between countries that MRA partners represent. This ensures that, through peer evaluation, NABL-accredited test/calibration results are accepted globally, reducing technical barriers to trade and eliminating the need for re-testing

The implementation of ISO/IEC 17025:2017 standard involves the establishment of a Laboratory Management System in accordance with the various clauses (8 in numbers) of the standard. This Laboratory Management System ensures technical competence, impartiality and consistent operation. The results so produced are globally accepted.

The requirement of improvising/standardising the working of State Board Laboratories in reference to the International Standard – ISO/IEC 17025:2017; was being felt to improve the quality of working of the Laboratories through several national interventions from CPCB and Hon'ble NGT.

The performance Audit of the State Board by CPCB and Hon'ble NGT significantly pointed out the requirement for the accreditation of State Pollution Control Board Laboratories. A need was also felt by the State Government for achieving Quality in the area of Environmental Monitoring and for strengthening the State Board Laboratories. In this regard, the Budget Announcement (2024-2025) also emphasised on establishment of new State Board Laboratories and their NABL accreditation.

Taking a proactive leap for the cause, the State Board Authorities facilitated the accreditation of all previously established State Board Laboratories, in reference to the International Standard – ISO/IEC 17025:2017 from NABL – National Accreditation Board for testing and calibration laboratories; a constituent Board of Quality Council of India in a short span of time; raising the number of accredited laboratories from 2 laboratories in 2023 (As per the CPCB report incorporated in Hon'ble NGT order dated 23/11/23 in the matter of O.A 693/2023- "Pollution Control Boards are the weak link") to 14 laboratories in 2025.

All previously established and operational 14 State Board laboratories have adopted the Quality Management System as per ISO/IEC 17025: 2017 Accreditation. The Laboratory Quality Policy adopted in the system emphasizes and ensures impartiality, confidentiality, competency and consistent operation along with continual improvements in the day-to-day working of the State Board laboratories. The improvisation through the adoption of ISO/IEC 17025: 2017 Accreditation includes the following: -

1. Improvisation of accuracy and establishing metrological traceability for valid results through the use of certified Reference material, Intermediate check, time-bound calibration of instruments and glassware
2. Quality Control and Quality Assurance in laboratory operations.
3. Assurance of impartiality and confidentiality in the laboratory operations
4. Maintenance of requisite competency in analytical work through internal and external training.
5. Establishment of uniformity of working w.r.t the standard methods for sampling, handling and analysis in all the State Board Laboratories.
6. Adoption of a defined procedure for record review, error evaluation and mitigation measures

The current status of accreditation is as follows:-

Sr. No.	Name of State Board Laboratory	Status of Accreditation	Future Roadmap/ Timeline
1.	Central Laboratory	Valid Renewal of Accreditation	Validity- 04.09.26
2.	Regional laboratory, Bhiwadi	Accredited, yet to apply for renewal of accreditation.	–
3.	Regional laboratory, Udaipur	Valid Fresh Accreditation	Validity 08.04.26
4.	Regional laboratory, Sikar	Valid Fresh Accreditation	Validity 05.09.26
5.	Regional laboratory, Kishangarh	Valid Fresh Accreditation	Validity 05.09.26
6.	Regional laboratory, Alwar	Valid Fresh Accreditation	Validity 29.10.28
7.	Regional laboratory, Kota	Valid Fresh Accreditation	Validity 26.12.28
8.	Regional laboratory, Chittorgarh	Valid Fresh Accreditation	Validity 27.02.29
9.	Regional laboratory, Bhilwara	Valid Fresh Accreditation	Validity 13.05.29
10.	Regional laboratory, Bikaner	Valid Fresh Accreditation	Validity 23.06.29
11.	Regional laboratory, Pali	Valid Fresh Accreditation	Validity 30.06.29
12.	Regional laboratory, Balotra	Valid Fresh Accreditation	Validity 30.06.29
13.	Regional laboratory, Bharatpur	Valid Fresh Accreditation	Validity 31.07.29
14.	Regional laboratory, Jodhpur	Valid Fresh Accreditation	Validity 10.08.29

Therefore, it may be concluded that the Environmental Laboratories are an indispensable tool for the quantification of environmental pollutants and for framing required policies/decisions in the matter. State Government and State Board have taken best efforts to improve the quality of its environmental laboratories through the adoption of International Standard- ISO/IEC 17025:2017. Also, it may be inferred that Quality is ensured through the adoption of the International Standard - ISO/IEC 17025:2017 Accreditation in the testing laboratories w.r.t ensuring reliable, timely and precise analytical services that are internationally accepted. ■

प्रदेश नीति : विकास और गति

शैलेंद्र सिंह, सांख्यिकी अधिकारी, डीआईपीआर

राज्य सरकार ने विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने की दिशा में दूरदर्शी सोच के साथ अनेक नवीन और भविष्योपयोगी नीतियां लागू की हैं। इन नीतियों के माध्यम से राज्य को तकनीक एवं नवाचार का केंद्र बनाने, युवाओं को कौशल व रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा सतत एवं पर्यावरण–अनुकूल विकास को बढ़ावा देने का स्पष्ट रोडमैप तैयार किया गया है। राजस्थान एआई-एमएल पॉलिसी-2026, राजस्थान युवा नीति-2026, राजस्थान रोजगार नीति-2026 और राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति-2025 न केवल प्रशासनिक दक्षता और आर्थिक सशक्तीकरण को गति देंगी, बल्कि राजस्थान को समग्र, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार राज्य के रूप में स्थापित करने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

राजस्थान एआई-एमएल पॉलिसी-2026

क्या है यह नीति?

राजस्थान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-मशीन लर्निंग नीति-2026 (एआई/एमएल 2026) का लक्ष्य एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और एम एल (मशीन लर्निंग) टेक्नोलॉजी को सरकारी सेवाओं, डिजिटल गवर्नेंस, शिक्षा, कौशल विकास और उद्योग/स्टार्टअप ईकोसिस्टम में लागू करना है।

मुख्य उद्देश्य

ई-गवर्नेंस में एआई-एमएल का इस्तेमाल : सरकार के डिजिटल सेवाओं (जैसे शिकायत निवारण, दस्तावेज़ प्रसंस्करण और नागरिक इंटरफेस) को तेज़, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने के लिए एआई-एमएल का इस्तेमाल करना।

शिक्षा और कौशल विकास : स्कूल, कॉलेज, आईटीआई और पॉलिटेक्निक में एआई कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण बढ़ाना ताकि युवा रोजगार और नवाचार के लिए तैयार हों।

स्टार्टअप्स और इनोवेशन : एआई-एमएल आधारित स्टार्टअप्स, नवाचार केंद्र और अनुसंधान को बढ़ावा देनाए प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट और पायलट प्रोजेक्ट्स को समर्थन देना।

डेटा सुरक्षा और नैतिक एआई : एआई के जिम्मेदार, सुरक्षित और नैतिक उपयोग को सुनिश्चित करने के दिशा-निर्देश, जिससे व्यक्ति की निजता और डेटा सुरक्षा बनी रहे।

सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस की स्थापना : राज्य में एआई सेंटर ऑफ़ एक्सीलेन्स (एआई अनुसंधान एवं क्षमता निर्माण केंद्र) तैयार करने का प्रावधान।

कब लागू हुई?

यह नीति संभागीय एआई सम्मेलन और डिजिफेस्ट के आयोजन के दौरान 6 जनवरी 2026 को लॉन्च/लागू हुई।

किन क्षेत्रों में लागू होगी?

- सरकारी सेवा (सार्वजनिक सेवा वितरण)
- स्वास्थ्य (डॉक्टर सहायता/टेलीमेडिसिन)
- शिक्षा (एआई आधारित लर्निंग टूल्स)
- कृषि (डेटा विश्लेषण आधारित सलाह)
- शहरी प्रशासन (ट्रैफिक, सुरक्षा)
- रोजगार और स्टार्टअप सहायता

राजस्थान एआई-एमएल पॉलिसी-2026 सेवा प्रदायगी में सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते महत्व को ध्यान में रखते हुए ई-गवर्नेंस के विस्तार को सुनिश्चित करेगी। नीति के तहत प्रत्येक विभाग अपने-अपने कार्यक्षेत्र में एआई उपयोग की संभावनाओं की पहचान करेगा तथा एक एआई नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। आधुनिक डिजिटल एवं कंप्यूट अवसंरचना, एआई क्लाउड सेवाएं, सुरक्षित डेटा स्टोरेज और टेस्टिंग प्लेटफॉर्म विकसित किए जाएंगे।

राजस्थान युवा नीति-2026

राजस्थान युवा नीति – 2026 क्या है?

राजस्थान सरकार ने 12 जनवरी 2026 को राजस्थान युवा नीति 2026 जारी की है। इसका मुख्य उद्देश्य है राज्य के युवाओं को उनके जीवन के प्रमुख क्षेत्रों में बेहतर अवसर और समर्थन देना है, ताकि वे नैतिक रूप से जागरूक, आर्थिक रूप से सक्षम, और समाज में सक्रिय भागीदार बन सकें।

नीति के मुख्य उद्देश्य

समग्र विकास और क्षमतावर्धन

- युवाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार और बुनियादी अधिकार तक पहुंच सुनिश्चित करना।
- उन्हें अर्थव्यवस्था और समाज में सक्रिय भूमिका निभाने की क्षमता प्रदान करना।

शिक्षा और कौशल विकास

- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और करियर परामर्श को मजबूत करना।
- डिज़िटल, तकनीकी और रोजगार-उन्मुख कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देना।
- रोजगार-बाजार की मांग के अनुरूप युवाओं को तैयार करना।

रोजगार और उद्यमिता

- युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के अवसर देना।
- नए रोजगार अवसर सृजित करना और स्टार्टअप वातावरण को प्रोत्साहित करना।
- नीति के साथ युवाओं को ब्याज-मुक्त ऋण और उद्यम सहायता जैसे प्रावधान जोड़ने का उद्देश्य भी रखा गया है।

स्वास्थ्य और कल्याण

- शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना।
- खेल, फिटनेस और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देना।

युवा नेतृत्व और सामाजिक भागीदारी

- युवाओं को नेतृत्व-निर्माण और निर्णय-प्रक्रियाओं में भागीदारी के लिए तैयार करना।
- सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता और सांस्कृतिक उद्यमिता को समर्थन देना।

प्रतिभा का विकास और वैश्विक भागीदारी

- कला, खेल, संस्कृति और साहित्य जैसे क्षेत्रों में युवा प्रतिभा का विकास करना।
- वैश्विक प्रतिस्पर्धा में युवाओं की भागीदारी को सशक्त बनाना।

राज्य सरकार की प्रमुख नीतियां

1. राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स) 2024
2. राजस्थान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) नीति 2024
3. राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024
4. एकीकृत क्लस्टर विकास योजना 2024
5. राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024
6. राजस्थान खनिज नीति 2024
7. राजस्थान पर्यटन इकाई नीति (आरटीयूपी) 2024
8. राजस्थान नागरिक उड्डयन नीति 2024
9. राजस्थान एनीमेशन, विज़ुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स एवं एक्सटेंडेड रियलिटी (एवीजीसी-एक्सआर) नीति 2024
10. राजस्थान व्यापार प्रोत्साहन नीति 2025
11. राजस्थान वस्त्र एवं परिधान नीति 2025
12. राजस्थान लॉजिस्टिक्स नीति 2025
13. राजस्थान वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) नीति 2025
14. राजस्थान ट्रांज़िट उन्मुख विकास (ट्रांज़िट ओरिएंटेड डेवलपमेंट) नीति 2025
15. अप्रवासी राजस्थानी (नॉन- रेजिडेंट) नीति (एनआरआर पॉलिसी) 2025
16. राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025
17. राजस्थान डेटा सेंटर नीति 2025
18. राजस्थान कौशल नीति 2025
19. राजस्थान कृत्रिम बुद्धिमत्ता / मशीन लर्निंग (एआई/एमएल) नीति 2026 ■

बिना सिफारिश और बिना खर्चे : युवाओं को मिल रही नौकरी

कांस्टेबल नव नियुक्ति समारोह, जयपुर

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में 10 जनवरी को कांस्टेबल नव नियुक्ति समारोह आयोजित किया गया। समारोह में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह तथा मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति रही। आठ हजार से अधिक नव चयनित कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। यह आयोजन प्रदेश में पारदर्शी भर्ती, सुदृढ़ कानून व्यवस्था और युवाओं के बढ़ते भरोसे का प्रतीक बनकर सामने आया।

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के संबोधन के प्रमुख बिंदु

बिना सिफारिश और बिना खर्चे के नौकरी

पारदर्शी तरीके से लोकसेवकों की भर्ती करने से ही कोई प्रदेश आगे बढ़ सकता है और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार का पेपरलीक का सिलसिला खत्म कर राजस्थान को इससे निजात दिलाई है। राज्य सरकार भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता रखते हुए भ्रष्टाचार का उन्मूलन और योग्यता का सम्मान करते हुए राजस्थान के युवाओं को 'बिना सिफारिश और बिना खर्चे' के नौकरी दे रही है।

राजस्थान पुलिस देश का अग्रणी पुलिस बल

राजस्थान पुलिस बल देश के अग्रणी और सक्षम पुलिस बलों में स्थान रखता है। जिन युवाओं को आज वर्दी मिली है, वे स्थिर चित्त के साथ पूरा ध्यान अपने प्रशिक्षण पर लगाएं और इसके उपरांत अपने काम से जनता की सेवा और सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए सुरक्षित राजस्थान के संकल्प को चरितार्थ करें। उन्होंने चयनित कांस्टेबलों में 2,500 से ज्यादा महिलाओं के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।

अपराध नियंत्रण में उल्लेखनीय सुधार

राजस्थान में राज्य सरकार के दो वर्षों के कार्यकाल में कानून व्यवस्था और सुरक्षा पर केन्द्रित प्रयासों का परिणाम स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। कुल अपराधों में 14 प्रतिशत से अधिक की कमी दर्ज की गई है। गंभीर अपराधों में 19 प्रतिशत, हत्या में 25 प्रतिशत और हत्या के प्रयास में 19 प्रतिशत की गिरावट आई है। महिलाओं के खिलाफ अपराध 10 प्रतिशत कम हुए हैं, जबकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विरुद्ध अपराधों में 28 प्रतिशत, डकैती के मामले 47 प्रतिशत और लूट के प्रकरण लगभग 51 प्रतिशत घटे हैं। यह आंकड़े प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधार की दिशा में ठोस कदमों का प्रमाण हैं।

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के संबोधन के प्रमुख बिंदु

वर्तमान कालखंड देश की आजादी के बाद का अभूतपूर्व कालखंड है, जिसमें देश को यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का मजबूत और कुशल नेतृत्व मिल रहा है। धारा 370 को हटाकर जम्मू-कश्मीर को देश की मुख्यधारा से जोड़ते हुए देश की एकता एवं अखंडता को मजबूती देने का काम किया गया।

कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए किए महत्त्वपूर्ण कार्य

कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार ने पिछले दो साल में महिला सुरक्षा के लिए 65 एंटी रोमियो स्क्वॉड, 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट, 9,400 सीसीटीवी कैमरे लगवाने सहित कई महत्त्वपूर्ण काम किए हैं।

राजस्थान साइबर क्राइम को-ऑर्डिनेशन सेंटर की होगी स्थापना

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर साइबर अपराध की चुनौती से प्रभावी रूप से निपटने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) की तर्ज पर प्रदेश में राजस्थान साइबर क्राइम को-ऑर्डिनेशन सेंटर (आर4सी) की स्थापना की घोषणा की। ■

राजस्थान सरकार

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

भर्ती परीक्षा कैलेंडर
2026

श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री

युवाओं को सरकारी नौकरियों के बढ़ते अवसर

क्र.सं.	परीक्षा का नाम	पदों की संख्या	परीक्षा माह
1	प्राध्यापक भर्ती - 2025	09	जनवरी
2	राजस्थान प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (लेवल-I) सीधी भर्ती परीक्षा - 2025	5449	जनवरी
3	राजस्थान उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (लेवल-II) (विज्ञान गणित) सीधी भर्ती परीक्षा - 2025	1043	जनवरी
4	राजस्थान उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (लेवल- II) (सामाजिक अध्ययन) सीधी भर्ती परीक्षा - 2025	296	जनवरी
5	राजस्थान उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (लेवल- II) (अंग्रेजी) सीधी भर्ती परीक्षा - 2025	221	जनवरी
6	राजस्थान उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (लेवल- II) (हिन्दी) सीधी भर्ती परीक्षा - 2025	174	जनवरी
7	राजस्थान प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (लेवल-I) (संस्कृत) सीधी भर्ती परीक्षा - 2025	187	जनवरी
8	राजस्थान उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (लेवल-II) (संस्कृत) सीधी भर्ती परीक्षा - 2025	389	जनवरी
9	शिक्षा विभाग (विभिन्न पद)	10000	जनवरी - मार्च
10	सहायक विद्युत निरीक्षक भर्ती - 2025	09	फ़रवरी
11	कनिष्ठ रसायनज्ञ भर्ती - 2025	13	फ़रवरी
12	आयुष मिशन के विभिन्न पद	1548	फ़रवरी
13	सहायक अभियंता संयुक्त भर्ती - 2024 (मुख्य परीक्षा)	1014	मार्च
14	उप निरीक्षक पुलिस परीक्षा - 2025	1015	अप्रैल
15	कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा	1100	अप्रैल
16	पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती - 2025	1100	अप्रैल
17	सहायक कृषि अभियंता भर्ती - 2025	281	अप्रैल
18	प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा (भूगोल)	136	मई
19	प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा (विज्ञान)	668	मई
20	व्याख्याता, व्याख्याता कृषि एवं कोच संयुक्त भर्ती - 2025 (माध्यमिक शिक्षा)	3725	मई - जून
21	राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त) परीक्षा	500	मई
22	महिला पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा	72	जून
23	वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा	259	जून
24	कान्स्टेबल परीक्षा	4000	जून-जुलाई
25	लिपिक ग्रेड-II/कनिष्ठ सहायक सीधी भर्ती परीक्षा	10644	जुलाई
26	वरिष्ठ अध्यापक संयुक्त भर्ती - 2025(माध्यमिक शिक्षा)	6500	जुलाई
27	कनिष्ठ विधि अधिकारी भर्ती - 2025	12	जुलाई
28	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (विभिन्न पद)	3000	जुलाई-अगस्त
29	वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षा	322	अगस्त
30	बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षा	2214	अगस्त
31	सांख्यिकी अधिकारी भर्ती - 2025	113	अगस्त
32	शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा	1079	सितम्बर
33	निरीक्षक कारखाना एवं बायलर्स भर्ती - 2025	12	सितम्बर
34	निरीक्षक कारखाना (रसायन) भर्ती - 2025	01	सितम्बर
35	सहायक निदेशक एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी भर्ती - 2025	09	अक्टूबर
36	सफाई कर्मचारी भर्ती	24793	अक्टूबर
37	ऊर्जा विभाग (विभिन्न पद)	2000	अक्टूबर
38	विविध पद	6000	अक्टूबर - दिसम्बर
39	संरक्षण अधिकारी भर्ती - 2025	12	नवम्बर
40	कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती	774	नवम्बर
41	संविदा टीचिंग एसोसिएट सीधी भर्ती परीक्षा	3500	दिसम्बर
42	ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा	3430	दिसम्बर
43	चिकित्सा अधिकारी भर्ती	600	दिसम्बर
44	नर्सिंग एवं पैरा मेडिकल भर्ती	2000	दिसम्बर

1 लाख से अधिक सरकारी भर्तियां

सुजस प्रश्नोत्तरी

प्रश्नोत्तरी नं. – 05

1. **भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा आधार के लिए लॉन्च किए गए आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है?**
A. मित्रा B. उदय C. पहचान D. सारथी

2. **राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में प्रारंभ की गई 'e-Swasthya Samvad' पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है?**
A. ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करना
B. चिकित्सा शिक्षा को सुदृढ़ करने हेतु डिजिटल संवाद मंच विकसित करना
C. निजी अस्पतालों को प्रोत्साहन देना D. आयुष चिकित्सा को बढ़ावा देना

3. **सीएसआईआर 'स्मार्ट गांव' मिशन का शुभारंभ राजस्थान के किस गांव से हुआ है?**
A. देवमाली (ब्यावर) B. कैमरी (करौली)
C. अटारी (भरतपुर) D. सवाईपुरा (पाली)

4. **"धरती आबा" (धरती के पिता) की उपाधि किससे संबंधित है?**
A. गिरीराज सिंह B. भगवान बिरसा मुंडा
C. सुदर्शन झा D. रामकृष्ण परमहंस

5. **RSCERT द्वारा प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत बच्चों को भावनात्मक मजबूती देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है?**
A. खुशीशाला - खुद की खोज कार्यक्रम
B. मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान
C. मिशन मधुहारी कार्यक्रम
D. विकसित भारत युवा संसद- 2025 कार्यक्रम

6. **पर्यटन विभाग द्वारा बनास महोत्सव का आयोजन कब किया गया?**
A. 2 दिसंबर, 25 B. 19 दिसंबर, 25 C. 24 दिसंबर, 25 D. 13 दिसंबर, 25

7. **राज प्रशस्ति की रचना किसने की?**
A. मण्डल B. महाराणा कुम्भा C. कुमारिल भट्ट D. रणछोड़ भट्ट

8. **हाल ही में नागौर जिले में किस नदी के किनारे पर 3500 वर्ष पुराने सिक्के बनाने की दुर्लभ सीलें मिली हैं?**
A. जाखम नदी B. माही नदी C. चंबल नदी D. लूणी नदी

9. **हाल ही में राजस्थान के किस गांव में पुरानी संसद भवन जैसा विद्यालय बनाया गया है?**
A. दादाल गांव, जालौर B. रामपुरा गांव, झुंझुनूं
C. चौंप गांव, जयपुर D. बहज गांव, डीग

10. **स्वामित्व योजना किस से संबंधित है?**
A. ग्रामीण इलाकों में मिट्टी का संरक्षण B. शहरी इलाकों में जल संचयन
C. ग्रामीण इलाकों में आबाद भूमि का सीमांकन
D. ग्रामीण इलाकों में संपत्ति सर्वेक्षण योजना

11. **'धौलागढ़ देवी' का मंदिर किस जिले में स्थित है?**
A. अलवर B. बूंदी C. भरतपुर D. कोटा

12. **निम्नलिखित में से कौन-सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है?**
A. जमनादास B. बकसाराम C. नानकराम D. नंदराम

13. **निम्नलिखित में से किन तीन नदियों के संगम को 'त्रिवेणी' कहा जाता है?**
A. बनास, मैनाल, बेडच B. गम्भीरी, मांसी, धुन्ध
C. कोठारी, खोरी, बेडच D. सोम, आहू, बाण्डी

14. **कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रकाशित वह समाचार पत्र, जिसने बिजौलिया किसान आंदोलन को अखिल भारतीय स्तर पर उजागर किया?**
A. तरुण राजस्थान B. राजस्थान केसरी
C. प्रताप D. नवीन राजस्थान

15. **चारचोमा का शिव मंदिर निम्न में से किस काल से संबंधित है?**
A. कुषाण काल B. गुप्त काल C. वैदिक काल D. मौर्य काल

16. **78वें Army Day Parade में निम्न में से किस युद्ध-संचालन (ऑपरेशन) को विशेष रूप से दर्शाया गया?**
A. ऑपरेशन विजय B. ऑपरेशन सिंदूर
C. ऑपरेशन मेघदूत D. ऑपरेशन फ्लड

17. **हाल ही में राजस्थान की किस पंचायत को देश की पहली पूर्णतः जैविक पंचायत घोषित किया गया है?**
A. खेजड़ी B. बामनवास कांकड C. गोपालपुरा D. रतनपुरा

18. **राजस्थान में जेन-जी थीम पर आधारित पहला नवीनीकृत डाकघर कहां पर शुरू हुआ हैं?**
A. आई आई टी जोधपुर B. राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय
C. आईआईएम उदयपुर D. राजस्थान विश्वविद्यालय

19. **खेल–खिलाड़ी से संबंधित असत्य है –**
A. रुद्राक्ष खंडेलवाल - निशानेबाज़ B. सुन्दर सिंह गुर्जर - भाला फेंक
C. महेश्वरी चौहान - कबड्डी D. सचिन तंवर – कबड्डी

प्रश्नोत्तरी नं. – 04 के उत्तर एवं विजेताओं का नाम

उत्तर : 1 (d), 2 (d), 3 (d), 4 (b), 5 (d), 6 (a), 7 (d), 8 (d), 9 (b), 10 (a), 11 (d), 12 (a), 13 (b), 14 (d), 15 (a), 16 (b), 17 (a), 18 (c), 19 (a), 20 (b), 21 (b), 22 (d), 23 (b)

अंकित मालव
पीसाहैड़ा, कोटा

अमित कुमार शर्मा
श्रीमाधोपुर, सीकर

दिनेश सारण चेरई
जोधपुर

राज्य सरकार की प्रमुख गतिविधियों, योजनाओं तथा राजस्थान से संबंधित सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्नोत्तरी के उत्तर 20 फरवरी, 2026 तक ईमेल द्वारा **sujasconnect@gmail.com** पर प्रेषित करें। प्राप्त प्रविष्टियों में से चयनित प्रतिभागियों के फोटो सहित नाम एवं सही उत्तर 'राजस्थान सुजस' के आगामी अंक में प्रकाशित किए जाएंगे व प्रश्नोत्तरी के विजेताओं को डीआईपीआर द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा।

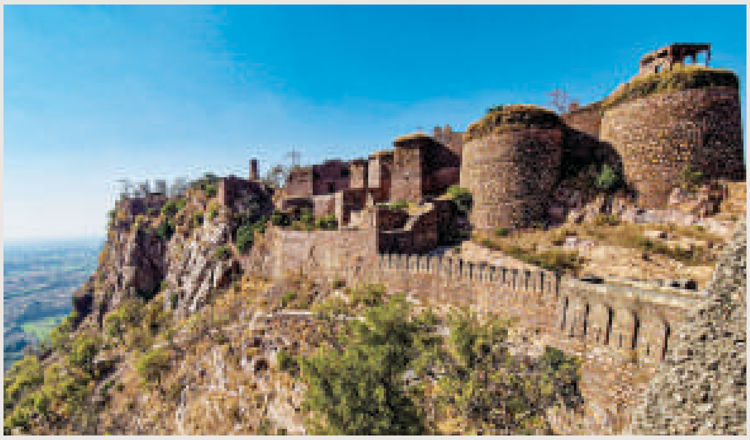

विजय मंदिर गढ़
बयाना

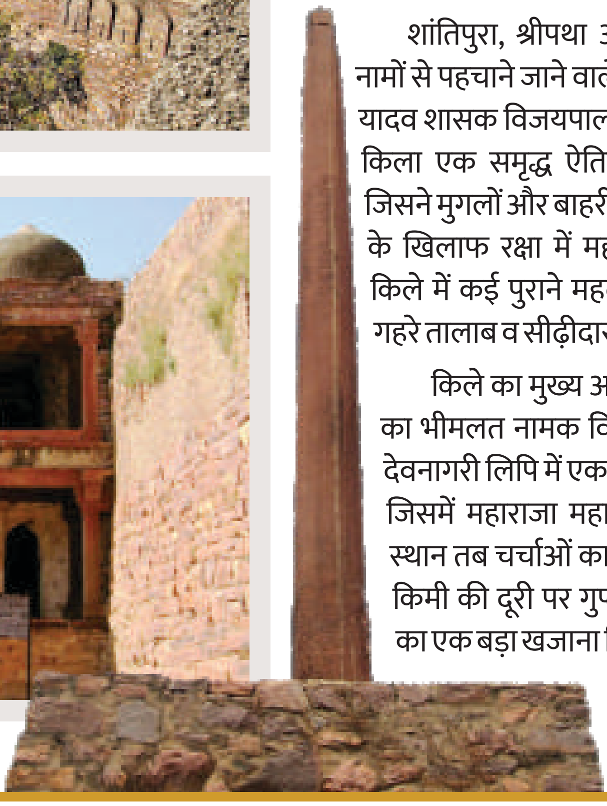

शांतिपुरा, श्रीपथा और विजय मंदिर गढ़ जैसे नामों से पहचाने जाने वाले इस किले को 11वीं सदी में यादव शासक विजयपाल द्वारा बनवाया गया था। यह किला एक समृद्ध ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रखता है, जिसने मुगलों और बाहरी आक्रमणकारियों के हमलों के खिलाफ रक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किले में कई पुराने महल और पानी रखने के लिए गहरे तालाब व सीढ़ीदार कुएं भी बने हुए हैं।

किले का मुख्य आकर्षण 300 शताब्दी ईस्वी का भीमलत नामक विजय स्तंभ है। इस स्तंभ पर देवनागरी लिपि में एक अधूरा शिलालेख अंकित है, जिसमें महाराजा महासेनापति का ज़िक्र है। यह स्थान तब चर्चाओं का विषय बना, जब यहां से 10 किमी की दूरी पर गुप्त काल के सोने के सिक्कों का एक बड़ा खजाना मिला था। ■

छाया व आलेख
अमन हरसाना

Postal Regd. No. Jaipur City/413/2023-25
Registered with Registrar of Newspapers for India under R. No. 56175/1991

सिलीसेढ़ झील को रामसर साइट का दर्जा

राजस्थान की अनेक ऐतिहासिक विरासतों में से एक है अलवर की सिलीसेढ़ झील। इस ऐतिहासिक और खूबसूरत स्थल को दिसंबर 2025 में भारत का 96वां और राजस्थान का 5वां रामसर साइट घोषित किया गया है, जिससे इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। झील के संरक्षण से प्रवासी पक्षियों को आश्रय देने, जैव विविधता और इको-टूरिज्म को बढ़ाने में सहायता मिलेगी, जो राजस्थान के पर्यटन के विकास और पर्यावरण के लिए महत्त्वपूर्ण है।

अलवर जिले में सिलीसेढ़ झील का निर्माण वर्ष 1845 में महाराजा विनय सिंह द्वारा रूपारेल नदी की सहायक नदी पर तटबंध बनाकर करवाया गया था। इस झील को अनेक पक्षी प्रजातियों और मगरमच्छों का घर माना जाता है।

उदयपुर को भारत की पहली 'रामसर वेटलैंड सिटी' के रूप में घोषित किया गया है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (भरतपुर), सांभर झील (जयपुर), मेनार (उदयपुर), खीचन (फलौदी) तथा सिलीसेढ़ (अलवर) को 'रामसर साइट' का दर्जा मिला है। रामसर साइट वह आर्द्र भूमि होती है, जिसे अंतरराष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड घोषित किया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1971 में ईरान के रामसर शहर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों के सम्मेलन से हुई थी। ■

आलेख : अम्बिका शर्मा

राजस्थान सुजस का यह अंक
https://dipr.rajasthan.gov.in/pages/sm/government-order/attachments/134/85/10/1702
पर देखा जा सकता है।

#DIPRRajasthan

प्रकाशक व मुद्रक - सूचना एवं जनसम्पर्क आयुक्त, राकेश शर्मा द्वारा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के लिए, शासन सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) से प्रकाशित
सम्पादक - डॉ. रजनीश शर्मा, मैसर्स रेनबो ऑफसेट प्रिन्टर्स, जयपुर से मुद्रित (.............. प्रतियां), 'राजस्थान सुजस' - पृष्ठ संख्या 72, मूल्य 1.00 रुपये • अंक प्रतियां 1,00,000